राष्ट्रीय दैनिक

प्रातः किरण

हर खबर की खबर

नई दिल्ली, पटना एवं जबलपुर (म. प्र.) से एक साथ प्रकाशित

/Pratahkiran /Pratahkiran /Pratahkiran

10 टैरिफ का दिखा असर, अमेरिका को भारत के निर्यात में.......

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी का.......... 11

वर्ष : 16 | अंक : 285 | नई दिल्ली, बुधवार, 18 फरवरी, 2026 | विक्रम संवत् 2082 | पेज : 12 | मूल्य ₹ : 03.00 | www.pratahkiran.com

मौसम

अधिकतम तापमान 22.0°C
न्यूनतम तापमान 20.0°C

राजधानी दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार

हां	45%
नहीं	45%
कह नहीं सकते	10%

बाजार

सोना 1,52,099

चांदी 2,92,200

सेंसेक्स 84,233

निफ्टी 25,953

गोवा समुद्री सम्मेलन 21 को, 14 देशों की नौसेनाएं सुरक्षा चुनौतियों पर करेंगी चर्चा

● नौसेना प्रमुख करेंगे मेजबानी, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ होंगे मुख्य अतिथि

प्रात: किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का गोवा समुद्री सम्मेलन 21 फरवरी को गोवा के नौसैनिक युद्ध महाविद्यालय में होगा। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों की सामूहिक बुद्धिमत्ता और परिचालन अनुभव को एक मंच पर लाएगा। सम्मेलन में समकालीन समुद्री चुनौतियों का समाधान निकालने के उद्देश्य से हिस्सा लेने वाली नौसेनाओं के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 14 देशों के नौसेना प्रमुखों, समुद्री बलों के प्रमुखों तथा वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मेजबानी करेंगे। इन देशों में बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और तंजानिया शामिल हैं। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में प्रख्यात वक्ता और विषय-विशेषज्ञ समुद्री सूचनाओं के वास्तविक समय में आदान-प्रदान और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करेंगे। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश मुख्य

भाषण देंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियां-अवैध और अनियमित मत्स्य पालन तथा अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों जैसे गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाना' रखा गया है। यह विषय हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री देशों के बीच तालमेल, सहयोग और समन्वय अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रत्येक दो वर्ष में होने वाले इस सम्मेलन के माध्यम से समुद्री पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जाती है और समग्र क्षमता निर्माण के लिए साझा मार्ग निर्धारित किए जाते हैं। नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि समुद्री क्षेत्र को पारंपरिक एवं अपारंपरिक दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका क्षेत्रीय सुरक्षा और आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध, अनियमित और बिना सूचना के मछली पकड़ना, समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती और अनियमित प्रवासन जैसे खतरे सुरक्षित समुद्र के लक्ष्य को लगातार कमजोर कर रहे हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत दौरा

प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत : मोदी

प्रात: किरण, एजेंसी

मुंबई /नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के महाराष्ट्र लोक भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता गले मिले और उनके बीच एक अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं की बातचीत का मुख्य केंद्र रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाना और उन्हें नए क्षेत्रों तक ले जाना रहा। राष्ट्रपति मैक्रों की इस यात्रा के दौरान 114 राफेल विमानों और हैमर मिसाइलों की खरीद समेत कई बड़े समझौतों पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की थी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में दोनों वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी के विशेष निमंत्रण पर 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर

हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। नवाचार के क्षेत्र में भारत और फ्रांस का यह साझा जश्न भविष्य की तकनीक के लिए एक नई राह तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे प्रिय मित्र प्रेसीडेंट का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट के लिए बुलाया था ।

उस समय हमने मार्सेय की यात्रा की- जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट, और फ्रांस, और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। मार्सेय वही शहर है, जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे। उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है। यह वही शहर है, जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। मुझे पिछले वर्ष मार्सेय में उनको याद करने और उन्हें नमन करने का अवसर मिला था।

इस बार जब प्रेसीडेंट भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत भारत के गेटवे यानि मुंबई में कर रहें हैं।भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष हैं। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रटीजिक पार्टनर्स में से एक है। और प्रेसीडेंट के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रटीजिक पाट्र्नर्शिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है।आज भारत में हेलिकाप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन, इसी गहरे विश्वास का एक और उज्ज्वल उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर, माउंट एवरेस्ट की ऊँचाइयों तक उड़ान भरने वाला, विश्व का एकमात्र हेलिकाप्टर भारत में बनाएंगे। और यह पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो-पेसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।

दिल्ली की सड़कों का होगा कायाकल्प

802 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी

केंद्र सरकार के सहयोग से करीब 400 किमी लंबी सड़कों को चमकाया जाएगा: सीएम रेखा गुप्ता

प्रात: किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों को गड्ढामुक्त, समतल और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी और व्यापक सड़क सुधार परियोजना को मंजूरी दी है। उन्नत तकनीक के माध्यम से

दिल्ली की 241 से अधिक प्रमुख सड़कों का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस परियोजना में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग है। सभी सड़कों को वॉल-टू-वॉल कारपेटिंग मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, ताकि सड़क निर्माण का काम आधा-अधूरा न रह जाए, बल्कि पूरी चौड़ाई में समान गुणवत्ता सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राजधानी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत 45 से ज्यादा विधानसभाओं की लगभग 400 किलोमीटर की प्रमुख सड़कें सुधारी जाएंगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि अक्सर सड़कों पर केवल बीच का हिस्सा ठीक किया जाता है या जहां गड्ढे होते हैं वहीं पैचवर्क कर दिया जाता है। इससे कुछ समय बाद सड़क फिर खराब हो जाती है। नई प्रणाली में पूरी सड़क को एक समान रूप से वॉल-टू-वॉल तैयार किया जाएगा, जिससे उसकी मजबूती और आयु दोनों बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि पूरी चौड़ाई में समतल और सीलबंद सतह बनने से धूल और वायु प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। टूटी-फूटी सड़कों से वाहनों की आवाजाही के दौरान मिट्टी और बारीक कण हवा में उड़ते हैं, जो प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं। अब नए तरीके से सड़कों को बनाने से हवा में उड़ने वाले पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व वायु गुणवत्ता बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी परियोजना को साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ट्रैफिक पर कम से कम असर पड़े और लोगों को असुविधा न हो। यह कार्य दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा करीब 45 विधानसभाओं में किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 802.18 करोड़ रुपये है। इसमें से 643.36 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) से प्राप्त होंगे, जबकि 158.82 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के सहयोग से दिल्ली के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य केवल मरम्मत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान देना है। सड़क की बेस लेयर की जांच, आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण, जल निकासी की व्यवस्था और अंतिम कारपेटिंग जैसे सभी चरणों को तकनीकी मानकों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

हरियाणा के मंत्रियों ने नितिन नवीन से मुलाकात की

नई दिल्ली। हरियाणा के मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मंगलवार को मुलाकात की। इनमें हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री राजेश नागर और खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्रियों ने बताया कि मुलाकात के दौरान भाजपा संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्रों में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लेकर बातचीत हुई।

अंतरिक्ष में छिपे हैं 15,000 सिटी-किलर एस्टेरॉयड नासा ने जारी की गंभीर चेतावनी, पृथ्वी से टकराने

प्रात: किरण, एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर एक अत्यंत डरावनी चेतावनी जारी की है। नासा के ग्रह रक्षा विभाग के अनुसार, अंतरिक्ष में लगभग 15,000 ऐसे मध्यम आकार के एस्टेरॉयड (NEOs) छिपे हैं, जिनका सटीक स्थान और रास्ता फिलहाल वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं है। इन एस्टेरॉयड को सिटी-किलर कहा जा रहा है क्योंकि इनकी चौड़ाई कम से कम 140 मीटर है। यदि इनमें से कोई भी पिंड किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र से टकराता है, तो वह पलक झपकते ही पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदल सकता है। वैज्ञानिकों की चिंता तब और बढ़ गई

जब R4 नामक एक विशाल एस्टेरॉयड पिछले क्रिसमस पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर गया और हमारी अत्याधुनिक प्रणालियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की डॉ. नैन्सी चाबोट ने आगाह किया है कि वर्तमान में दुनिया के पास ऐसी कोई सक्रिय सुरक्षा प्रणाली या तैयार अंतरिक्ष यान नहीं है, जिसे किसी अचानक आए खतरे को रोकने के लिए तुरंत लॉन्च किया जा सके। फिलहाल नासा केवल 40 प्रतिशत खतरनाक पिंडों की ही पहचान कर पाया है, जबकि शेष 60 प्रतिशत अब भी अंतरिक्ष की गहराई में छिपे हुए हैं। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए नासा अब नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर नामक एक नया स्पेस टेलिस्कोप अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन अज्ञात और रहस्यमयी एस्टेरॉयड को खोजना है जो मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तकनीकी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए ही इन विनाशकारी पिंडों को समय रहते पहचाना और नष्ट किया जा सकता है। आने वाले दशक में अंतरिक्ष सुरक्षा नीतियों को मजबूत करना अब मानवता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो गया है।

वर्धा जिले में जीटी एक्सप्रेस के पार्सल कोच में आग से हडकंप, कोई हताहत नहीं

प्रात: किरण, एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सेवाग्राम स्टेशन के पास चेन्नई से नई दिल्ली की ओर नागपुर जा रही ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस (जी.टी. एक्सप्रेस) के एक पार्सल कोच में मंगलवार को अचानक आग लग जाने से हडकंप मच गया। इसकी सूचना मिलते ही रेलवे स्टाफ ने तुरंत आग लगे कोच को ट्रेन से अलग किया और ट्रेन को आगे रवाना कर दिया। मध्य रेलवे के प्रवक्ता संजय मुले ने मीडिया को बताया कि जीटी एक्सप्रेस के पार्सल कोच में आग लगने की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टाफ और फायर ब्रिगेड के जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और आग लगी कोच को ट्रेन से अलग कर दिया। इसके बाद ट्रेन को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। ट्रेन के सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं । कोच में आग लगने के कारणों को पता लगाने का काम जारी है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि ट्रेन अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से चल रही थी, उसी समय पार्सल कोच के यात्रियों ने ट्रेन से धुआं निकलते देखा। कुछ यात्रियों ने तुरंत चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंचा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन को सेवाग्राम में रोक दिया गया। जलते हुए कोच में सवार यात्रियों को तुरंत नीचे उतारकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इसके बाद जलते हुए कोच को ट्रेस से अलग किया गया और ट्रेन को आगे रवाना कर दिया । फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का सही कारण अभी साफ नहीं है। शुरूआती अनुमान के मुताबिक यह माना जा रहा है कि आग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी की वजह से लगी होगी। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है ।

एआई से स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव: अनुप्रिया

प्रात: किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को कहा कि भारत की विशाल एवं विविध जनसंख्या ग्रामीण-शहरी विभाजन और संक्रामक एवं गैर-संक्रामक बीमारियों का दोहरा बोझ देश के सामने बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बेहद जरूरी है और भारत ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का व्यापक एकीकरण किया है। अनुप्रिया पटेल ने यहां भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' से पहले आयोजित विशेष सत्र में कहा कि एआई को केवल तकनीक अपनाने के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे देश की विशिष्ट चुनौतियों का रणनीतिक समाधान माना जा रहा है। आज स्वास्थ्य क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। बीमारी की निगरानी से लेकर रोकथाम, जांच और इलाज तक एआई बहुत ज्यादा कारगर है। एआई स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में एआई का इस्तेमाल कई स्तरों पर हो रहा है। बीमारी की शुरूआती पहचान, समय पर रोकथाम, सटीक जांच और बेहतर इलाज के लिए एआई आधारित

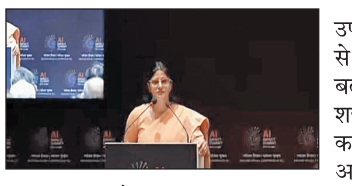

उपकरण काम कर रहे हैं। एआई से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ रही है और यह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने में भी मदद करेगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एआई आधारित रोग निगरानी प्रणाली से बीमारियों का फैलाव पहले ही पकड़ में आ जाता है। इसी तरह एआई से जांच और निदान तेज और सटीक हो रहा है। इलाज के दौरान एआई डॉक्टरों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहा है। भारत की स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए एआई का इस्तेमाल केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में स्वास्थ्य क्षेत्र की मजबूती बेहद जरूरी है और एआई इसमें अहम भूमिका निभा रहा है।

एआई के लिए ऊर्जा परत में निवेश का यह बड़ा लाभ भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा..................

देश में एआई में दो सालों में आएगा 200 अरब डॉलर निवेश: अश्विनी वैष्णव

प्रात: किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि आने वाले दो वर्षों में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र की पांचों परतों में 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है। जोखिम पूंजी कंपनियां गहन तकनीक स्टार्टअप्स, बड़े समाधान और अनुप्रयोगों, अत्याधुनिक मॉडल्स पर शोध और बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परतों में निवेश कर रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। वैष्णव ने यहां भारत मंडपम में एक सत्र में कहा कि भारत की एक बड़ी ताकत यह है कि देश की 51 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों

से आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के कारण यह संभव हुआ है। एआई के लिए ऊर्जा परत में निवेश का यह बड़ा लाभ भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उन्होंने एआई के संभावित खतरों को बताते हुए कहा कि वैश्विक नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बन रही है कि एआई का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए और इसके हानिकारक प्रभावों को रोकना जरूरी है। इसके लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि तकनीकी और कानूनी दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे तकनीकी समाधान तैयार कर रहा है, जो एआई के दुष्प्रभावों को रोक सकें। एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग के सम्मेलन में शामिल न होने पर वैष्णव ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से आने में असमर्थता जताई, लेकिन अपनी वरिष्ठ टीम को भेजा है। एनवीडिया भारत की कई कंपनियों के साथ मिलकर एआई ढांचा और सॉफ्टवेयर के बड़े निवेश कर रहा है। वैष्णव ने कहा कि भारत अपने मजबूत आईटी सेक्टर में तकनीकी बदलाव को रणनीतिक रूप से संभाल रहा है। सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के सहयोग से कर्मचारियों की प्रतिभाओं को निखारना, नई प्रतिभा तैयार करना और भविष्य की पीढ़ियों को तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है। एआई आधारित रीस्किलिंग और 100 से अधिक कॉलेजों में पाठ्यक्रम सुधारों के जरिए युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जा रहा है।

सम्राट चौधरी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बिहार पवेलियन का किया उद्घाटन, 468 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर

प्रात: किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 के दौरान बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने की। इस मौके पर बिहार सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह, उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल तथा राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बिहार सरकार राज्य को उभरते हुए प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इन पहलों के तहत बिहार एआई मिशन के अंतर्गत मेगा एआई कोर ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी, निवेशकों के साथ निवेश समझौते तथा बिहार जीसीसी नीति 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 का शुभारंभ शामिल है। इसके अलावा आईआईटी पटना में अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है, जिससे अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। समिट के दौरान बिहार सरकार ने प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों और आईआईटी पटना के साथ कुल 468 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इनमें बिहार एआई उत्कृष्टता केंद्र (एआई-कोड) की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपये तथा आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इस परियोजना में टाइगर एनालिटिक्स उद्योग भागीदार तथा आईआईटी पटना शैक्षणिक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त बिहार जीसीसी नीति 2026 और बिहार आईटी नीति 2024 के अंतर्गत रेड साइबर, ग्रोक्यूआर और सीआईपीएल जैसी प्रमुख आईटी और जीसीसी कंपनियों के साथ भी निवेश और तकनीकी सहयोग के समझौते किए गए हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुंबई के होटल ताज में 26/11 पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

प्रात: किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनिअल मैंक्रों ने मुंबई के ताज होटेल में 26/11 हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों भी उनके साथ मौजूद रहीं। इसकी जानकारी देते हुए मैंक्रों ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मुंबई के ताज महल पैलेस में, हमने 2008 के हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए कहा कि इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों और प्रियजनों के लिए, और भारत के लिए फ्रांस हमेशा साथ खड़ा है। आतंकवाद के सामने, एकता और दृढ़ निश्चय सबसे बड़ी ताकत है। इससे पहले सुबह मैक्रों तड़के मुंबई के मरीन ड्राइव पर दौड़ सैर की। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा की थी। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे और मुंबई में मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। यह उनकी भारत की चौथी यात्रा है। हालांकि वह मुंबई पहली बार गए हैं।

देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें
@Pratahkiran www.pratahkiran.com
राष्ट्रीय दैनिक प्रातःकिरण
नई दिल्ली, बुधवार, 18 फरवरी, 2026

संक्षिप्त समाचार

नैनीताल नाबालिग रेप मामला, आरोपी ठेकेदार उस्मान खान को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

नैनीताल, एजेंसी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज सोमवार 16 फरवरी को भी उस्मान खान कोई राहत नहीं दी. साथ ही अब मामले की अगली सुनवाई हेतु 18 फरवरी 2026 को होगी. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती आलोक कुमार महरा की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी. इस घटना के सामने आने के बाद नैनीताल के लोग आक्रोशित हो गए थे. उन्होंने शहर में तोड़फोड़ भी की थी. पुलिस ने जैसे-कैसे माहौल को शांत किया और हालात का काबू में करते हुए आरोपी उस्मान को हिरासत में लिया था. तभी से आरोपी जेल में बंद है. इससे पहले भी आरोपी कई बार जमानत याचिका दायर कर चुका है, लेकिन कोर्ट ने हर बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है. वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के नन्ही परी हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाए दोष सिद्ध अभियुक्त अख्तर अली के शीर्ष अदालत से बरी हो जाने के मामले में महिला अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने और अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता जे एस विर्क से सुझाव देने को कहा है. खुद संज्ञान वाली जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई. आज कुछ सोशल मीडिया साइट की ओर से अपना पक्ष रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया. इसके बाद अदालत ने न्यायमित्र अधिवक्ता को निर्देश दिए कि वह इस मामले में आवश्यक सुझाव पेश करें. आज प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है. विशेष अनुसंधान बल (एसआईटी) को जांच सौंपी गई है. सोशल मीडिया साइट से अभद्र संदेश उपलब्ध नहीं हैं. बता दें कि नैनीताल के काठगोदाम में 10 साल पहले नन्ही परी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. दोषी अख्तर अली की फांसी की सजा उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दी थी. इस निर्णय के बाद के प्रदेश में कई जगह पर प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया में महिला अधिवक्ता के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया.

पिरान कलियर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर घायल

रुड़की, एजेंसी। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में 48 घंटे के बाद एक ओर दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल, एक स्कूटी और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अपस्ताल भिजवाया है, जहां पर उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र में कांवड़ पटरी पर बाइक और स्कूटी की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. बताया गया है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, वहीं इस दुर्घटना में दोनों युवक प्रशांत शुक्ला निवासी सिद्धार्थ एनक्लेव, रामनगर रुड़की और गुलशन पुत्र देशराज निवासी पूरनपुर, राजपुर कोतवाली रानीपुर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा होते ही मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल कलियर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद प्रशांत शुक्ला की हालत को नाजुक देखते हुए रुड़की के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान प्रशांत शुक्ला की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि अस्पताल के चिकित्सकों ने की है. वहीं पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है. बताते चलें, 7 फरवरी शनिवार की देर शाम भी तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर भगवानपुर कस्बा क्षेत्र से हरिद्वार की ओर जा रहे थे, जैसे ही वह कलियर थाना क्षेत्र के बेडपुर चौक के पास ईट-भट्टे के पास पहुंचे तो इसी दौरान ओवरटेक करते समय उनकी बाइक एक ट्रक की चपेट में आ गई, हादसा इतना भयंकर था कि बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी और बाइक पर सवार शिवम (28 वर्ष) और सूरज (26 वर्ष) निवासी बनारस की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि अमन यादव (25 वर्ष) निवासी बनारस हाल निवासी भगवानपुर गंभीर रूप से घायल हो गया था.

रैमजे इंटर कॉलेज के सामने पार्क को जनता के लिए खोलने की मांग

अल्मोड़ा, एजेंसी। सेवानिवृत केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समिति की नगर निगम परिसर के जन सुविधा केंद्र में बैठक हुई। वक्ताओं ने रैमजे इंटर कॉलेज के सामने पार्क को जनता के लिए खोलने की मांग की। पार्क के भीतर व्यवसायी के सामान रखने पर रोक लगाने की मांग की।

हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, कोतवाली घेरकर सख्त कार्रवाई की मांग

चमोली, एजेंसी। विकासखंड गैरसैंण के अंतर्गत शिवरात्रि के दिन फरसों गांव में कार की चपेट में आकर घायल हुए 7 साल के बच्चे की हायर सेंटर रेफर किए जाने के बाद रास्ते में ही मौत हो गयी. जिसके बाद एक तरफ बच्चे की मौत का गम तो दूसरी तरफ बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. गुसाए ग्रामीणों ने मामले में अस्पताल प्रबंधन व पुलिस पर लापरवाह रवैया का आरोप लगाया. जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली गैरसैंण का घेराव कर आरोपी वाहन चालक महिला के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. वहीं मामले में पुलिस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रवैये पर भी जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया. जिला उपचिकित्सालय कर्णप्रयाग से पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का शव घर लाने के दौरान ग्रामीण भारी संख्या में गैरसैंण कोतवाली पहुंच गए. जहां पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के साथ ही दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बच्चे को रेफर कर एंबुलेंस चालक के भरोसे ही भेजे जाने पर भारी नाराजगी दिखाते हुए ग्रामीणों ने लापरवाह लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगाते हुए मामले में भारी लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया. साथ ही कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर हुई मौत को लेकर बीएनएस की धारा 125 व 106 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई. रविवार को शिवरात्रि के दिन 7 वर्षीय बच्चा अपनी मां ,छोटी बहन व अन्य ग्रामीणों के साथ धुनारघाट शिवालय मंदिर दर्शनों को गए थे. जहां से वापसी के बाद घर के सामने ही सड़क पार करने के दौरान मेहलचोरी से गैरसैंण की तरफ आ रही वेगन आर की चपेट में बच्चा आ गया. जिससे बच्चा कुछ दूरी तक टायर के साथ घसीटता चला गया. जिससे उसके सिर में गंभीर फ्रैक्चर आ गए, घटना के बाद ग्रामीणों ने बच्चे को प्राइवेट वाहन से तत्काल गैरसैंण अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया. इस दौरान 108 एंबुलेंस के अन्यत्र होने से एक घंटे बाद पहुंचने की बात बतायी गई. जिसके चलते गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल की एंबुलेंस में बगैर किसी सहायक और फार्मासिस्ट के ही आगे भेज दिया गया. रास्ते में ही एंबुलेंस चालक द्वारा बच्चे के दम तोड़ने की सूचना अस्पताल को दी गयी थी. इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले मालसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी उपचार नहीं मिल पाया. कर्णप्रयाग तक के 50 किलोमीटर लंबे सफर में गंभीर रूप से घायल बालक को एंबुलेंस चालक के भरोसे ही भेजे जाने को लेकर ग्राम प्रधान अमित रावत व अन्य ने इसे गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. जिला पंचायत सदस्य सुरेश बिष्ट ,नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ,जीतेन्द्र नेगी ,अवतार सिंह आदी ने कहा कि पहले ही गैरसैंण की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. मामले को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्जुन रावत ने बताया कि 108 के अन्यत्र होने से बालक की गंभीर हालत को देखते हुए विभागीय एंबुलेंस में भेजना पड़ा. जिसमें विभागीय स्तर से फार्मासिस्ट जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं. मामले को लेकर सीएमओ चमोली अभिषेक गुप्ता ने कहा कि इस तरह के गंभीर मामलों में अस्पताल स्टाफ को आवश्यक रूप से साथ जाने के लिए आदेश जारी कर किए गए हैं. रविवार को कुछ फार्मासिस्टों के मातृत्व अवकाश के चलते व अस्पताल में एक अन्य डिलीवरी वाली महिला के भर्ती होने के कारण एक फार्मासिस्ट को अस्पताल में रोका गया था. जिसके कारण कोई स्टाफ साथ में नहीं भेजा जा सका. मामले में पंजीकृत मुकदमे के विवेचना अधिकारी चौकी प्रभारी मेहलचोरी बिशनलाल ने बताया कि परिजनों द्वारा पहली सूचना में अज्ञात का नाम लिखा गया था. दोबारा से दी गई सूचना के अनुसार अब नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है. वहीं लापरवाही से वाहन चलाने के साथ ही मौत का मामला भी जोड़ा गया है, जिसकी विवेचना के बाद मामला न्यायालय में भेजा जाएगा.

सोमेश्वर में दिव्यांग की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पैसे की तंगी खींच लाई वापस घर

अल्मोड़ा, एजेंसी। जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद कई शहरों में छिपता फिर रहा था, लेकिन पैसों की तंगी उसे वापस अल्मोड़ा खींच लाई, जहां पुलिस ने उसे धर दबोचा. पुलिस के अनुसार 24 जनवरी 2026 को कोतवाली सोमेश्वर क्षेत्र के ग्राम रस्यारागांव में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कुंदन राम के रूप में की, जो दिव्यांग था. अगले दिन 25 जनवरी को मृतक के भाई हरीश राम की तहरीर पर आरोपी दीपक पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ एससी एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सर्विलांस और तकनीकी टीमों की मदद से लगातार आरोपी की तलाश जारी रखी. जांच में सामने आया कि 18 जनवरी की शाम आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने पत्थर से कुंदन राम के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी गिरफ्तारी के डर से गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और बनारस में छिपता रहा. करीब एक महीने तक फरार रहने के बाद जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह अल्मोड़ा अपने परिचितों से मदद लेने पहुंचा. पुलिस को इसकी भनक लगते ही 15 फरवरी 2026 को करबला तिराहा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के घर से घटना के समय पहने खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक पांडे (34 वर्ष) पुत्र महेश पांडे, निवासी ग्राम रस्यारागांव के रूप में हुई है.

उत्तराखंड में सस्ती आवास योजना पर संकट, पांच महीने से नहीं मिला कोई डेवलपर

देहरादून, एजेंसी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत पीपीपी मोड पर प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। पिछले पांच महीनों से परियोजना के लिए प्राइवेट पार्टनर की तलाश की जा रही है, लेकिन एक भी डेवलपर ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। फरवरी माह में पुनः निविदा जारी कर 31 मार्च तक निजी क्षेत्र के पार्टनर्स को आमंत्रित किया गया है, इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। डेवलपर्स की बेरुखी से राज्य में सस्ती आवास योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। रियल एस्टेट क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित नए भुगतान फार्मूले को बिल्डर्स व्यवहारिक नहीं मान रहे हैं। उनका तर्क है कि लाभार्थी-आधारित किश्तों और सरकारी सब्सिडी पर निर्भर माडल में कैश फ्लो की अनिश्चितता बनी रहती है। इससे परियोजना का वित्तीय ढांचा प्रभावित होता है। यदि शीघ्र निजी पार्टनर की तलाश पूरी नहीं हुई तो राज्य में सस्ते आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय समयसीमा से आगे बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार पीपीपी आधारित अफोर्डेबल हाउसिंग में निजी भागीदारी की सुस्ती केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी डेवलपर्स ने अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद कई जगहों पर शर्तों में संशोधन, अतिरिक्त एफएआर, शुल्क में छूट और सिंगल विंडो क्लीयरेंस जैसे कदम उठाकर परियोजनाओं को गति दी गई। नीतिगत स्तर पर इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने केंद्र से भी सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित बाजार आकार का हवाला देते हुए विशेष प्रोत्साहन और लचीले प्रविधानों का अनुरोध किया था, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में प्रति यूनिट कीमत निर्धारित होती है। निर्माण लागत खासकर सीमेंट, स्टील और श्रम में वृद्धि के चलते मुनाफा सीमित रह गया है। इसके अलावा भूमि उपयोग परिवर्तन, नक्शा स्वीकृति और अन्य विभागीय अनुमतियों की जटिल प्रक्रिया भी निजी डेवलपर्स को हतोत्साहित करती है। जोखिम और रिटर्न के असंतुलन ने पीपीपी माडल को व्यवहारिक बनाने की चुनौती बढ़ा दी है।

राज्य विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण अब अनिवार्य, इस बात पर दिया जा रहा जोर

देहरादून, एजेंसी। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी विश्वविद्यालयों को विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों के साथ एमओयू करना होगा, ताकि छात्रों को उनके विषय से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके। इस व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण की मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, यह पहल नई शिक्षा नीति के अनुरूप कौशल आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सरकार का मानना है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक अनुभव से छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों में भी आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों को उद्योगों से समन्वय स्थापित कर छात्रों को कौशल विकास से जोड़ना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्रशिक्षण की प्रगति पर शासन स्तर से नियमित निगरानी की जाएगी और इसमें लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी संभव है। प्रदेश के 12 राजकीय विश्वविद्यालयों से 119 राजकीय महाविद्यालय संबद्ध हैं। इनमें सर्वाधिक 59 महाविद्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय तथा 54 महाविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय हल्द्वानी से जुड़े हैं। इन महाविद्यालयों में 80 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। ऐसे में इन छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत उद्योग हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए उद्योगों से एमओयू करना अपेक्षाकृत आसान होगा। हालांकि, चमोली और उत्तरकाशी जैसे दूरस्थ पर्वतीय जिलों में स्थित संस्थानों के लिए उद्योगों से जुड़ाव एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने पर सरकार विचार करना होगा

प्रदेश में बढ़ी गर्मी, पहाड़ों में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख हैं और पहाड़ से मैदान तक तेज धूप खिलने से दिन गर्म होने लगे हैं।

सोमवार इस वर्ष का अब तक सबसे गर्म दिन रहा। ज्यादातर क्षेत्रों में पारा सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।

आज भी मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। हालांकि, कल से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के करवट बदलने के आसार हैं।

सोमवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटख धूप खिली रही। जिससे दिन में तपिश बढ़ गई और गर्मी महसूस की गई।

दून में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जो कि इस वर्ष अब तक का सर्वाधिक है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी अधिकतम पारा सामान्य से चार से छह डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

इधर, दून में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक होने के कारण अब सुबह-शाम ठंड कम होने लगी है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में भी ठिठुरन बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। जिससे पारे में भी वृद्धि हो सकती है।

अगले दो-तीन दिन में ज्यादातर क्षेत्रों में पारे में वृद्धि के आसार हैं। बुधवार को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रहने से लेकर कहीं-कहीं वर्षा-बर्फबारी की उम्मीद है।

झ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमपात हो सकता है।

फोम से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगी आग, बुझाने में फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

रुद्रपुर, एजेंसी। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में तीन पानी डैम आज सोमवार 16 फरवरी को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भीषण आग लग गई थी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी सी मच गई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगने के पूरा मामला ट्रांजिट थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक तीन पानी के पास दोपहर को अचानक से ट्रैक्टर-ट्रॉली आग लग गई. मौके पर मौजूद लोग इससे पहले कुछ समझ पाते आग ने भयावह रूप ले लिया था. स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 पर कॉल कर आग लगने की सूचना दी. तीन पानी डैम में आग लगने की सूचना मिलते ही उधम सिंह नगर के अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में फायर यूनिट तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने देखा कि तीन पानी डैम ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली आग भड़कती जा रही है और तेजी से फैल भी रही है.

मामले की की गंभीरता को देखते हुए फायर यूनिट ने तुरंत वाहन से पंपिंग कर मॉनिटर ब्रांच व एक हौज पाइप की सहायता से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई. दमकल कर्मियों की तत्परता और समन्वित प्रयासों से कुछ ही समय में आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है.

महेश चंद अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही एक बड़ा और एक छोटा फायर टैंक तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया था. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. हेलमेट बनाने के लिए जिस फोमका इस्तेमाल होता है, वो ट्रैक्टर ट्राली में भरी हुई थी.

बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्राली बिजली के तारों से टकराई थी, उसी वजह से ट्राली में भरी फोममें आग लग गई. गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. घटनास्थल पर थाना ट्रांजिट कैंप के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया. अग्निशमन कार्य पूर्ण होने के बाद अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र द्वारा घटनास्थल का आवश्यक निरीक्षण किया गया. संतुष्ट होने के उपरांत फायर यूनिट सुरक्षित रूप से वापस फायर स्टेशन लौट आई.

कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा चार लेन दोराहा रेलवे ओवर ब्रिजः रवनीत सिंह बिट्टू

उप राज्यपाल के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार अच्छे नतीजे दे रही हैः सीएम

- केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हुए कार्यक्रम में शामिल

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। लेवल क्रॉसिंग संख्या 164 एबी, दोराहा पर चार लेन रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण मालवा क्षेत्र, पंजाब की राजधानी तथा आसपास के जिलों के बीच संपर्क को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना साबित होगा। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री (रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) रवनीत सिंह बिट्टू ने कही। कार्यक्रम में विनोद भाटिया, मंडल रेल प्रबंधक, अंबाला,राजीव रंजन राजू,चीफ इंजीनियर (रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। चार लेन आरओबी का शिलान्यास करने के बाद मंत्री ने बताया कि लगभग 70.55 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना अगले एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब इस कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले लगभग 12 वर्षों से इस लेवल क्रॉसिंग पर लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि दोराहा का यह लेवल क्रॉसिंग रूप नगर से लुधियाना को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है, जो पंजाब की राजधानी और पूरे मालवा क्षेत्र के बीच एक अहम कड़ी का काम करती है। मंत्री ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 190 ट्रेनें इस क्रॉसिंग से गुजरती हैं और 3,000 से अधिक वाहन यहां से होकर निकलते हैं। रेल यातायात के कारण बार-बार फाटक बंद होने से जाम, लंबा इंतजार और आम यात्रियों, व्यापारियों तथा परिवहनकताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरओबी के निर्माण से ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रवनीत सिंह ने इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है। नया चार लेन आरओबी न केवल दैनिक आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि माल एवं सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित कर आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। पंजाब में चल रहे रेलवे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य में 166 स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज और लो हाइट सबवे के कार्य 1,480.09 करोड़ की लागत से प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में रेलवे अवसंरचना विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार राज्य में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में रेलवे का वार्षिक बजट आवंटन 2009झ2014 की अवधि की तुलना में आज लगभग 25 गुना बढ़कर 5,673 करोड़ हो गया है। वर्तमान में राज्य में 26,382 करोड़ के अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास, सुरक्षा उन्नयन तथा क्षमता विस्तार से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 30 रेलवे स्टेशनों का 1,311 करोड़ की लागत से व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने दिल्ली और अंबाला के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। यह परियोजना अत्यधिक व्यस्त दिल्लीझजम्मू रेल कॉरिडोर को चौड़ा करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उत्तरी राज्यों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सबसे व्यस्त मार्गों में से एक दिल्ली - अंबाला रेल खंड देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है, जहां यात्री और माल यातायात दोनों का भारी दबाव है। तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण से लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, परिचालन दक्षता सुधरेगी और भीड़भाड़ में कमी आएगी। 194 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 5,983 करोड़ है और इसे चार वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों तथा दिल्ली के सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। क्षमता वृद्धि से अतिरिक्त यात्री एवं मालगाड़ियों का संचालन संभव होगा, जिससे समयपालन और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार आएगा। यह कॉरिडोर रोपड़, पानीपत और राजपुरा स्थित ताप विद्युत संयंत्रों सहित कृषि गोदामों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है। बेहतर माल परिवहन से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्नत कॉरिडोर से प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, श्रीनगर, जम्मू, शिमला तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर तंजानिया को भारत का सहयोग

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। भारत व तंजानिया के सैन्य अधिकारी साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपस में सहयोग कर रहे हैं। तंजानिया पीपुल्स डिफेन्स फोर्सेज के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को भारत के साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्र पर पहुंचे। यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ी पहल है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, तंजानिया पीपुल्स डिफेन्स फोर्सेज (टीपीडीएफ) का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। भारत आए तंजानिया पीपुल्स डिफेन्स फोर्सेज के इन अधिकारियों ने मंगलवार को भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के रक्षा व साइबर सुरक्षा से जुड़े अहम केंद्रों का भी दौरा किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, डिफेन्स फोर्सेज के इन अधिकारियों ने 17 फरवरी को अपनी यह भारत यात्रा शुरू की है। यह विजिट 19 फरवरी तक चलेगी और इन तीन दिनों के दौरे में तंजानिया के सैन्य अधिकारी विभिन्न स्तर पर भारतीय अधिकारियों से वार्ता व मुलाकात करेंगे। बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा साइबर सुरक्षा को लेकर हुई। दोनों देशों ने माना कि आज के समय में साइबर खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। यह बातचीत तकनीकी जानकारी साझा करने, संयुक्त प्रशिक्षण, और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने जैसे विषयों पर केंद्रित है। तंजानिया के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रक्षा साइबर सुरक्षा संस्थानों में जाकर देखा कि भारत किस तरह साइबर हमलों से निपटने की तैयारी कर रहा है। उन्हें आधुनिक सिस्टम, निगरानी तंत्र और प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। दरअसल, यह दौरा दिखाता है कि भारत और तंजानिया के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। अक्टूबर 2023 में तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान जो पांच साल का रक्षा सहयोग रोडमैप तय हुआ था, उसी के तहत यह पहल आगे बढ़ रही है। दोनों देशों का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में भरोसा बढ़ाना व नई तकनीकों में साथ काम करना है। इसके अलावा, दोनों देश भविष्य की चुनौतियों के लिए मिलकर तैयारी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी।

पांच साल से फरार उम्रकैद का दोषी गिरफ्तार

- दोस्त की चाकू मारकर की थी हत्या

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा और मार्च 2021 से फरार चल रहा दोषी रोबिन तमांग उर्फ जोजो उर्फ पानचाए (45) को आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी करीब पांच वर्षों से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था और अलग-अलग राज्यों में ठिकाना बदलकर छिप रहा था। डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने बताया कि मामला वर्ष 2013 का है। थाना बुराड़ी में दर्ज इस केस में रोबिन तमांग ने दोस्त नीरज की हत्या की थी। मोबाइल सिम कार्ड और एक युवती को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो झगड़े में बदल गई। इसी दौरान रोबिन ने नीरज के सीने में 3-4 बार चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गया। घायल नीरज को हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने रोबिन तमांग को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वह मंडोली जेल में बंद था। 3 सितंबर 2020 को उसे तीन सप्ताह की फरलो पर रिहा किया गया था, जिसकी अवधि 15 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई, लेकिन वह तय तारीख पर जेल वापस नहीं लौटा और तब से फरार था। डीसीपी ने बताया कि फरारी के दौरान आरोपी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में छिपा रहा। इसके अलावा वह नागालैंड, मेघालय, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी रहा और ढाबों व फूड स्टॉल पर काम कर पहचान छिपाता रहा। हाल ही में उसके दिल्ली लौटने की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र के जरिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से उसे दबोच लिया।आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

कुत्ता घुमाने के विवाद में शख्स पर जानलेवा हमला

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। सागरपुर इलाके में 12 फरवरी की देर रात कुत्ता घुमाने के दौरान हुए विवाद में छह-सात युवकों ने एक शख्स पर पथराव कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंकित कुमार सिन्हा अपने परिवार के साथ डाबड़ी एक्सटेंशन में रहते हैं। पुलिस को दिए बयान में अंकित ने बताया कि वह 12 फरवरी की देर रात अपने दोस्त मोहित पासवान के साथ कुत्ता घुमाने निकले थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ युवकों पर कुत्ता भौंकने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। अंकित का आरोप है कि युवकों ने गाली-गलौच शुरू कर दी और उनमें से एक ने मोहित को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद आरोपी गली से पत्थर उठा लाए और मोहित के सिर पर वार कर दिया। मोहित जमीन पर गिर पड़ा तो आरोपियों ने उसके चेहरे पर दोबारा पत्थर मारा और लात-घूंसे से हमला किया। अंकित ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी उसपर भी पत्थर फेंकने लगे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अंकित के बयान पर पुलिस ने साहिल, लकी, आदित्य, साजिद, अमन और चमन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चेहरे को कुचलने की कोशिश डॉक्टर ने बताया कि आरोपियों ने पत्थर से हमला कर मोहित के चेहरे को कुचलने की कोशिश की।

डीयू ने परिसर में विरोध प्रदर्शन करने पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने यातायात में बाधा, सुरक्षा को खतरा और सार्वजनिक शांति बाधित होने की आशंका का हवाला देते हुए परिसर में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा करने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन एवं धरना देने पर मंगलवार को एक महीने के लिए रोक लगा दी। विश्वविद्यालय के कुलानुशासक (प्रॉक्टर) कार्यालय ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध इस सूचना के बाद लगाया गया है कि बिना नियंत्रण वाली सार्वजनिक सभाएं कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं। इसमें सिविल लाइंस के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा पहले जारी किए गए उस निर्देश का भी उल्लेख किया गया है जिसमें सार्वजनिक सभाएं करने, मशालें या इसी तरह की सामग्री साथ लेने, नारे लगाने और ऐसे भाषणों पर रोक लगाई गई है जो सार्वजनिक शांति या यातायात प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलानुशासक मनोज कुमार ने एक बयान में कहा कि अतीत में, आयोजक अक्सर ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, ये प्रदर्शन बढ़ गए और व्यापक रूप से फैल गए जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। आदेश में कहा गया है, पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, नारे लगाना और भाषण देना तथा मशाल, टॉर्च आदि सहित किसी भी प्रकार की खतरनाक सामग्री ले जाना निषिद्ध है। आदेश में कहा गया है, यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता है तो यह एक महीने तक लागू रहेगा। हंसराज कॉलेज में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर और दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने इस कदम को व्यापक प्रतिबंध करार दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए और विश्वविद्यालय को व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए लेकिन सभाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात अवरोध का हवाला देना अस्वीकार्य है। धुसिया ने एक बयान में कहा, क्या प्रशासन नियुक्तियों, नयी शिक्षा नीति (एनईपी) के क्रियान्वयन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विधेयक और शिक्षकों के हालिया निलंबन जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने यह आदेश वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुलानुशासक कार्यालय सार्वजनिक सभाओं पर एकतरफा तरीके से इस प्रकार पूर्ण रोक नहीं लगा सकता। यह आदेश हालिया विवादों के बाद आया है, जब पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्र समूहों के बीच झड़प के बाद दो प्राथमिकी दर्ज की थीं तथा 12 फरवरी को सामाजिक न्याय कार्यक्रम में इतिहासकार इरफान हबीब के भाषण के दौरान उन पर बाल्टी से पानी फेंका गया था।

एआई भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से देश की भावी पीढ़ी सशक्त बनेगी। यह तकनीक भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पत्रकारों से कहा कि भारत की नई पीढ़ी को एआई-सक्षम शिक्षा प्रदान करना अब सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी और प्राथमिकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन ने युवाओं में एक नया उत्साह पैदा किया है। इसके अलावा एआई की यह प्रगति साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग को प्रशस्त करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दो विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें शिक्षा में एआई और एआई के बारे में शिक्षा शामिल हैं। प्रधान ने कहा, ह्लभारत के पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य के आधुनिक ज्ञान तक, एआई का उपयोग करके हमें न केवल छात्रों को, बल्कि शिक्षकों और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को भी सशक्त बनाना है। शिक्षा में एआई और एआई में शिक्षा- ये दोनों अब एक-दूसरे के पूरक हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे एआई का इस्तेमाल सीखने, सिखाने और नए नवाचार करने के लिए करें ताकि भारत इस क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बन सके। सम्मेलन के साथ-साथ शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे सभी छात्रों को अपना संदेश दिया। उन्होंने छात्रों को एग्जाम वॉरियर बताते हुए कहा कि वे तनावमुक्त होकर परीक्षा को एक त्योहार की तरह मनाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो-2026 का उद्घाटन किया था।

लालू की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी। इसमें देवघर कोषागार से जुड़े एक घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि दलीलें पूरी नहीं हुई हैं और कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने एक गैर-कानूनी आदेश पारित किया है और कानून का उल्लंघन करते हुए सजा निलंबित की गई है। लालू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ आरोपियों को नोटिस नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि हम दोनों ही जानते हैं कि यह कैसी विशेष अनुमति याचिका है। हमें लगता है कि आप दोनों जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि कानून का सवाल क्या है। लोग 60, 70 और 80 की उम्र के हैं। पीठ ने कहा कि फाइलें बस लटकी हुई हैं। हम अप्रैल में तारीख देंगे। जिन मामलों में प्रतिवादियों की मौत हो गई है, हम उन्हें बंद कर देंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल जुलाई में यादव को सुनाई गई सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई की अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली थी।

ट्रैफिक पुलिस को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल (एआरएससी) ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को फर्जी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले एक और गिरोह का पदार्फाश किया है। पुलिस ने इस मामले में महिला सरगना समेत अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त संजीव यादव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपित की पहचान समालखा, हरियाणा निवासी 32 वर्षीय महिला (सरगना), सचिन (35) और सुल्तानपुरी निवासी आमिर उर्फ सिकंदर के रूप में हुई है। आमिर उगाही के लिए फोन करता था। जबकि सचिन वीडियो एडिट करता था। पुलिस ने आरोपितों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद किया हैं। पुलिस उपायुक्त के अनुसार क्राइम ब्रांच थाने में 19 जनवरी 2026 को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक फर्जी और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे 1.20 लाख रुपये वसूले गए। पुलिस शिकायतकर्ता के बयान पर संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस उपायुक्त के अनुसार 10 फरवरी को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि हरियाणा के समालखा निवासी 32 वर्षीय महिला इस गिरोह की मास्टरमाइंड है। वह अपने साथियों के साथ दिल्ली आकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की चालान कार्रवाई के दौरान छिपे कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड करती थी। इन वीडियो को गिरोह का सदस्य सचिन एडिट कर इस तरह से तोड़-मरोड़ देता था कि देखने में पुलिसकर्मी की गलती प्रतीत हो। इसके बाद आरोपित आमिर उर्फ सिकंदर पुलिसकर्मियों को फोन कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और झूठी शिकायत दर्ज कराने की धमकी देता था। वीडियो हटाने के बदले पैसे की मांग की जाती थी। जो लोग पैसे देने से इनकार करते, उन्हें बार-बार परेशान किया जाता और झूठी शिकायतें दर्ज कराई जातीं। रकम मिलने के बाद ही शिकायत वापस ली जाती थी। पहले भी चल चुका है ऐसा गिरोह पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला पहले रोहिणी निवासी अशोक कुमार उर्फ बबली नामक व्यक्ति के गिरोह से जुड़ी थी। दिसंबर 2025 में उसकी मौत के बाद उसने अपना अलग गिरोह बना लिया। वहीं आमिर पहले भी इसी तरह के एक अन्य गिरोह से जुड़े मामले में गिरफ्तार हो चुका है।

विक्रांत जेटली प्रकरणः केंद्र को और समय, यूएई से राजनयिक सहयोग मांगा जाएगा

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली की संयुक्त अरब अमीरात में कथित हिरासत के मामले में केंद्र सरकार को राजनयिक माध्यमों से वहां की सरकार से सहयोग प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। न्यायालय ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई मार्च तक स्थगित कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौर की पीठ को बताया कि भारतीय दूतावास ने 13 फरवरी को विक्रांत जेटली से वाणिज्य दूतावासीय संपर्क की अनुमति मांगी थी, किंतु संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। केंद्र ने न्यायालय से तीन से चार सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय और दूतावास राजनयिक स्तर पर आवश्यक प्रयास कर रहे हैं, ताकि संबंधित पक्षों से सहयोग प्राप्त किया जा सके। न्यायालय सेलिना जेटली द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि विक्रांत जेटली को 6 सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। सुनवाई के दौरान विक्रांत जेटली की पत्नी ने भी न्यायालय से इस मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया, ताकि वह लगाए गए आरोपों का उत्तर प्रस्तुत कर सकें।

दिल्ली के बच्चों को मिला ग्लोबल एजुकेशन इकोसिस्टम, क्लासरूम से ग्लोबल करियर तक

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सरोजिनी नगर में बने सीएमश्री स्कूल का उद्घाटन किया। साथ ही राजधानी में 75 सीएमश्री स्कूल परियोजनाओं की शुरूआत भी की गई। दिल्ली सरकार की यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक आधुनिक, तकनीक से जुड़ी और बेहतर शिक्षा देने के लिए शुरू की गई है। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने एक साल के अंदर शिक्षा से जुड़े अपने वादों को पूरा करने की दिशा में अच्छा काम किया है। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएमश्री स्कूल सिर्फ नए भवन नहीं हैं, बल्कि यह दिल्ली के बच्चों को बेहतर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की पहल है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेष रूप से 75 सीएमश्री विद्यालयों की स्थापना को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया और कहा कि इन्हें उच्च मानक के रूप में विकसित कर दिल्ली सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन विद्यालयों में गरीब, सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं और तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि दिल्ली में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध-केंद्रित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में दिल्ली सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएमश्री स्कूल केवल नए भवन या सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि यह दिल्ली के बच्चों के भविष्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का संकल्प है। इन स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आधुनिक तकनीक, कौशल शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और समग्र व्यक्तित्व विकास को एक साथ जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था देना है जो बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में एआई से जुड़े स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। इनमें इंटरैक्टिव पैनल, डिजिटल पढ़ाई सामग्री और आधुनिक लर्निंग टूल्स होंगे। इससे हर छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाई कराई जा सकेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास पोर्टल भी बनाया गया है। इसके जरिए जेईई, नीट, सीयूईटी, सीएलएटी और एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी।

सीएमश्री स्कूलों की प्रमुख विशेषताएं

- एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम
- प्रतियोगी परीक्षा पोर्टल
- मल्टी-सेक्टोरियल स्किल लैब्स
- आईसीटी लैब्स
- डिजिटाइज्ड लाइब्रेरी
- करियर लैब
- बहुभाषी शिक्षा और विदेशी भाषाएं सीखने की सुविधा
- पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों से जुड़कर काम का अनुभव
- पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों से जुड़कर काम का अनुभव
- छोटे बच्चों के लिए खेल और गतिविधि आधारित पढ़ाई
- 7,000 से अधिक स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ, गणित प्रश्नपत्र रहा संतुलित

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

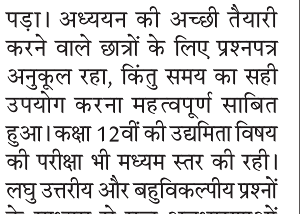

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से आरंभ हो गईं। पहले दिन कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने गणित का प्रश्नपत्र हल किया, जबकि कक्षा 12वीं के छात्रों की जैव प्रौद्योगिकी, उद्यमिता सहित विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित हुई। देशभर में इस वर्ष 43 लाख से अधिक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा मंय शामिल हो रहे हैं। कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नपत्र को लेकर विद्यार्थियों और शिक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। अधिकांश विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र को मध्यम स्तर का बताया। उनका कहना था कि प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप थे और अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी आधारित थे, जिससे अवधारणात्मक समझ की जांच हुई। बहुविकल्पीय प्रश्न सीधे थे, जबकि कुछ प्रश्नों में तर्क की आवश्यकता पड़ी। दो तथा तीन अंकों के प्रश्न संतुलित रहे, लेकिन प्रश्नपत्र लंबा होने के कारण समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण रहा। विद्यार्थियों के अनुसार अंतिम खंड में विस्तार से हल करने वाले प्रश्न अधिक समय लेने वाले थे, जिससे कई परीक्षार्थियों को अंत में समय की कमी का सामना करना पड़ा। अध्ययन की अच्छी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रश्नपत्र अनुकूल रहा, किंतु समय का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण साबित हुआ। कक्षा 12वीं की उद्यमिता विषय की परीक्षा भी मध्यम स्तर की रही। लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से मूल अवधारणाओं की स्पष्टता परखी गई, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विश्लेषणात्मक रहे। शिक्षकों का मत है कि नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रश्नपत्र संतुलित था। परीक्षा का आयोजन प्रातः 10 बजकर 30 मिनट पर हुआ और प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च तक तथा कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 तक चलेंगी।

PUBLIC NOTICE

मैं रमेश पुत्र कैलाश ग्राम चुचैला कलां जिला अमरोहा का निवासी हूं। मेरी पॉलिसी संख्या 255180941 है, जो कळ्ळ कार्यालय अमरोहा में पप्पू वर्मा पुत्र कैलाश के नाम से चल रही है। मैंने अपने आधार कार्ड व अन्य डॉक्युमेंट्स में अपना नाम रमेश पुत्र कैलाश कर लिया है। भविष्य में अब मुझे इसी नाम से जाना जाए।

राष्ट्रीय दैनिक
प्रातः किरण

राजधानी किरण

देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें
@Pratahkiran
www.pratahkiran.com
नई दिल्ली, बुधवार, 18 फरवरी, 2026

संक्षिप्त खबरें

पार्किंग विवाद में आरोपियों ने की हवाई फायरिंग

नई दिल्ली। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में रविवार शाम को आरोपियों ने हवाई फायरिंग की। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। अमर कॉलोनी थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता 24 वर्षीय मोहम्मद अंजार अपने परिवार के साथ साउथ डीडीए फ्लैट्स, ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में रहता है। पीड़ित ने बताया कि वह घर धोने का काम करता है। रविवार सुबह करीब 10:15 बजे पड़ोस में रहने वाले अरुण ठकराल ने अपनी गाड़ी गलत तरीके से खड़ी कर दी थी, जिससे अन्य गाड़ियों की धुलाई प्रभावित हो रही थी। अंजार चाबी लेने अरुण के घर गया, लेकिन उसने चाबी देने से इंकार कर दिया था। पीड़ित का आरोप है कि शाम करीब चार बजे अरुण ठकराल अपने साथी अनिल उर्फ कान्हा के साथ डीडीए मार्केट स्थित कैफे पर पहुंचा। वहां अंजार पहले से ही बैठा था। अंजार का आरोप है कि दोनों ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया और मौके से फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई।

जल निकायों के लिए कार्ययोजना तैयार करे डीपीसीसी: एनजीटी

नई दिल्ली। राजधानी में जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को जल निकायों के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों से वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग इसी योजना के क्रियान्वयन में किया जाए और छह माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। यह आदेश पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में एक व्यक्ति द्वारा भूजल के अवैध दोहन के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि संबंधित अनधिकृत बोरवेल को सील कर दिया गया है तथा 35,064 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल की जा चुकी है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि डीपीसीसी जिला आर्द्रभूमि समिति और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के साथ परामर्श कर दिल्ली के सभी जल निकायों के पुनर्जीवन के लिए ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करे।

धीरपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इस माह भूमि की मिट्टी जांच कराकर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें कामकाजी महिलाओं के ठहरने व खाने की सुविधा के साथ अध्ययन की व्यवस्था भी होगी। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली युवतियों को भी ठहरने की अनुमति दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 100 महिलाओं के ठहरने के लिए हॉस्टल बनाने की योजना है। इसकी बनावट तय करने से पहले मिट्टी की जांच कराई जाएगी। मिट्टी की जांच के लिए जमीन की गहराई तक ड्रिलिंग कर सैंपल जुटाएगा। इससे यह पता चल सकेगा कि भूमि के भीतर किस प्रकार की मिट्टी है व उसकी वहन क्षमता कितनी है। इसके आधार पर ही विशेषज्ञ यह तय करेंगे कि हॉस्टल भवन की नींव किस प्रकार की होनी चाहिए। उसका डिजाइन किस प्रकार का होना चाहिए।

प्रीमियम आवास योजना की पंजीकरण तिथि बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की प्रीमियम आवास योजना की पंजीकरण तिथि बढ़ा दी गई है। अब फ्लैट खरीदार 20 फरवरी तक पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के साथ फ्लैट खरीदार फ्लैटों की श्रेणी के हिसाब से बयाना राशि भी जमा करा सकते हैं। डीडीए की इस आवासीय योजना में 582 फ्लैट और गैरेज के लिए ई-नीलामी होगी। इसमें वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, जसोला, दिलशाद गार्डन, नरेला में लोग फ्लैट के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना के तहत एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, जनता फ्लैट, ईडब्ल्यूएस और कार व स्कूटर गैराज के पंजीकरण कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, एलआईजी, जनता फ्लैटों के लिए चार लाख रुपये, एमआईजी फ्लैटों के लिए दस लाख रुपये, एचआईजी फ्लैटों के लिए 15 लाख रुपये, कार गैरेज के लिए चार लाख रुपये और स्कूटर गैराज के लिए एक लाख रुपये बयाना राशि जमा करानी है।

भाजपा बताए, शिक्षा मंत्री आशीष सूद का एपीजे स्कूल से क्या रिश्ता? : सौरभ भारद्वाज

सोमवार देर रात तक बच्चों का एडमिट कार्ड लेकर शिक्षा मंत्री के घर क्यों बैठे थे एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल?

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने बच्चों का एडमिट कार्ड लेकर देर रात तक शिक्षा मंत्री आशीष सूद के घर में बैठे मिले एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर को लेकर गंभीर सवाल खड़ा किया है। आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पूछा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद का एपीजे स्कूल से क्या रिश्ता है? स्कूल का बच्चों को एडमिट कार्ड देने का होता है, लेकिन एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों का एडमिट कार्ड लेकर सोमवार देर रात तक शिक्षा मंत्री के घर क्यों बैठे थे? उन्होंने कहा कि आशीष सूद को 18 लाख बच्चों के अभिभावक बताते हैं। अगर ऐसा सच में होता तो वे एडमिट कार्ड रोकने पर एपीजे स्कूल पर एफआईआर कराते, लेकिन उनकी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है। मंगलवार को आप मुख्यालय पर विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार के साथ प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोमवार को दिन भर जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी एपीजे स्कूल के बाहर धरना देती रही, वही एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल और मैनेजर भाजपा मंत्री आशीष सूद के घर में छिपे मिले। आखिर आशीष सूद का एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल से क्या रिश्ता है? क्या वे रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं? एडमिट कार्ड देना तो स्कूल का होता है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल एडमिट कार्ड लेकर मंत्री के घर पर बैठे हैं। वे वहां क्यों बैठे थे? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षा है और सोमवार को सुबह से लेकर रात 9:00 बजे तक एपीजे स्कूल ने पुलिस के सामने बच्चों के पैरेंट्स के साथ ब्लैकमेलिंग की। स्कूल ने साफ कहा कि अगर बढ़ी हुई फीस दोगे तभी एडमिट कार्ड मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। पैरेंट्स के लिए स्कूल फीस की लड़ाई लड़नी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें बच्चे शामिल होते हैं। अभिभावक अपनी लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि बच्चों को स्कूल में प्रताड़ित किया जाता है। सौरभ भारद्वाज ने डीपीएस द्वारका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी छोटे-छोटे बच्चों को कक्षा में नहीं बैठने दिया गया। उन्हें रोज लाइब्रेरी में बिठाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और बाकी बच्चों के सामने बेइज्जत किया जाता था कि वे नालायक हैं, जिनके मां-बाप फीस नहीं दे रहे। इसलिए कक्षा से बाहर जाएं। स्कूल के बाहर बाउंसर खड़े किए गए। आशीष सूद में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट के आदेश के बावजूद डीपीएस द्वारका के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दें। उन बच्चों को सबके सामने प्रताड़ित किया गया, लेकिन विधानसभा में प्रश्न लगाने पर जवाब आया कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सौरभ भारद्वाज ने आशीष सूद पर निशाना साधते हुए कहा कि आशीष सूद कहते हैं कि वे दिल्ली के 18 लाख बच्चों के अभिभावक हैं। ऐसा अभिभावक बेहद गिरा हुआ होता है, जिसकी 10वीं कक्षा की बेटी का अगले दिन गणित का पेपर हो और रात को 9:00 बजे तक बेटी और उसका पिता स्कूल के बाहर खड़े हों कि एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं। इसकी तैयारी कौन करेगा? क्या आशीष सूद करेंगे या भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके लिए गणित का पेपर लिखकर आएंगी? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आशीष सूद की यह बेशर्मी ही है कि वे खुद को 18 लाख बच्चों का अभिभावक कहते हैं। अगर वे सच में अभिभावक होते तो एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल को वहीं जूते मारते कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने बच्चों का एडमिट कार्ड रोक लिया, जबकि अगले दिन परीक्षा है। लेकिन आशीष सूद, एपीजे स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल को अपने साथ बिठाए हुए थे। आशीष सूद ने अभी तक स्कूल पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो आदमी 10वीं की बेटी को प्रताड़ित करे, उसे भावनात्मक और मानसिक रूप से टॉर्चर करे, उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एफआईआर का सीधा प्रावधान है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 बच्चों के प्रति क्रूरता के लिए सजा निर्धारित करता है। यह सेक्शन किसी भी ऐसे कृत्य को कवर करता है जो बच्चे को मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है। परीक्षा से ठीक पहले एडमिट कार्ड रोकना कानूनी रूप से मानसिक उत्पीड़न और क्रूरता का ही एक रूप माना जाता है। यह स्पष्ट कानूनी प्रावधान है, लेकिन आशीष सूद ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं या उनके लिए घाघरा बनवा दें? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभिभावकों की तरफ से शिक्षा निदेशक को एक बार नहीं, दर्जनों बार चिट्ठियां लिखी गई हैं कि बच्चों के एडमिट कार्ड रोके गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर साउथ और शिक्षा सचिव को भी बार-बार सूचित किया गया, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इस विवाद की असल वजह ये है।

विश्व कायस्थ संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई की एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक संपन्न

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

लखनऊः विश्व कायस्थ संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई की एक्जीक्यूटिव कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सक्सेना को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने उनका नाम प्रस्तावित किया, जिसे सभी सदस्यों ने एकमत से स्वीकार किया। नए अध्यक्ष सुधीर सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास में कायस्थ समाज के महापुरुषों का योगदान सदैव अविस्मरणीय और गौरवपूर्ण रहा है। आज भी यह समाज राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रहा है। कायस्थ महापुरुषों के इस योगदान पर हमें गर्व है और इन्हें स्मरण करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लेना चाहिए। बैठक में भगवान चित्रगुप्त महराज की मूर्ति स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। यह कदम कायस्थ समाज की आस्था और परंपरा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। संस्था में अधिक से अधिक लोगों का विश्वास जगाने तथा नए सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी पदाधिकारियों ने इस दिशा में सक्रिय प्रयास करने का संकल्प लिया। होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन 21 मार्च 2026 को लखनऊ के एलएमए हॉल में किया जाएगा। यह समारोह समाज के सदस्यों के बीच भाईचारे, उत्साह और एकजुटता को बढ़ावा देने का प्रमुख अवसर साबित होगा। इस वर्ष संस्था द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की गई। महिला प्रकोष्ठ द्वारा संचालित कार्यक्रमों की प्रगति पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। विश्व कायस्थ संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई कायस्थ समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा दे रही है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने नए अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत किया और आगामी योजनाओं को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। यह संस्था कायस्थ समाज को संगठित एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बैठक में प्रमुख रूप से सर्व आकांक्षा निगम, रूपाली चन्द्रा, संजय कुमार, अनुज श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, डाक्टर अजय प्रकाश, नीरज श्रीवास्तव, राजीव प्रधान, दिवाकर खरे, राहुल निगम तथा विजय श्रीवास्तव सहित अन्य सम्मानित सदस्य उपस्थित थे।

संयम बरतें, एक-दूसरे के खिलाफ बयान न दें: अदालत ने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी और बहन से कहा

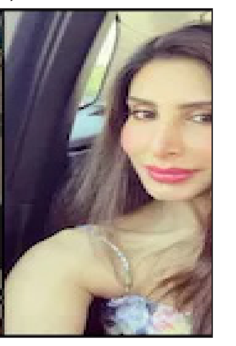

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया एस. कपूर और बहन मंदिरा कपूर स्मिथ के एक-दूसरे के खिलाफ बयान देने पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने यह आदेश प्रिया कपूर के अपनी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उनकी ननद पॉडकास्ट, साक्षात्कार, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों के जरिये लगातार दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला अभियान चला रही हैं। न्यायाधीश ने कहा, ह्यदोनों पक्षों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक-दूसरे के खिलाफ बयान देने में संयम बरतने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने मामले पर स्मिथ और पॉडकास्ट की मेजबान पूजा चौधरी को भी समन जारी किया तथा मामले को मई में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। प्रिया कपूर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उनकी (प्रिया की) ननद ने याचिकाकर्ता की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर सामग्री अपलोड और साझा की। दूसरी ओर, स्मिथ के वकील ने कहा कि उन्हें (स्मिथ को) बदनाम करने के लिए मीडिया में सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। प्रिया कपूर ने कहा कि संजय कपूर की मौत के कुछ ही दिनों के अंदर, उनकी ननद ने उनकी छवि खराब करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाया।

डीटीयू में एआई-डेटा साइंटिस्ट के पदों पर 19 फरवरी तक आवेदन का मौका

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्रायोजित एक शोध परियोजना के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह परियोजना एआई आधारित ऑडिट समाधान के विकास और साइबर सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट की गुणवत्ता निगरानी से संबंधित है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी मान्य नहीं होगी।

देश के युवा प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के शिल्पकार हैं: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। यह संस्थान केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के उन सपनों का प्रतीक है, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना की थी। ये विचार दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज के 35 वें वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। तीन दशकों से अधिक की शैक्षणिक उत्कृष्टता का जश्न मनाने वाले इस कार्यक्रम में कॉलेज प्रशासन, संकाय सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। समारोह के दौरान अध्यक्ष ने मेधावी छात्रों को शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवर्तित ह्यविकसित भारतह्न के रोडमैप के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि इस परिवर्तन के प्राथमिक शिल्पकार भी हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी की ऊर्जा और नवाचार ही भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के मिशन के पीछे की प्रेरक शक्ति है। छात्रों को प्रेरित करते हुए गुप्ता ने कहा कि वर्तमान युग प्रतिभा और नवाचार का है। उन्होंने उल्लेख किया कि युवा एक पुनरुत्थानवादी भारत का हिस्सा हैं जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा याद रखें, आपकी डिग्री केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी की घोषणा है। बाबासाहेब अंबेडकर के प्रतिष्ठित आह्वान शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने जोर दिया कि आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ राष्ट्रीय चुनौतियों को हल करने और समावेशी विकास को गति देने के लिए शिक्षा का उपयोग करना है। पुरस्कार विजेताओं और छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि आपकी सफलता आपकी कड़ी मेहनत और आपके शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। जिन्हें आज पुरस्कार नहीं मिले, वे याद रखें कि असफलता केवल इस बात का संकेत है कि और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। जीवन की असली दौड़ कॉलेज के बाहर शुरू होती है, जहां आपके चरित्र और दृष्टिकोण का महत्व आपकी डिग्री से अधिक होगा। जोखिम लेने से न डरे, गिरने के बाद संभलने वाले ही इतिहास रचते हैं। गुप्ता ने आगे कहा कि तकनीक और आधुनिकता के युग में भी छात्रों को अपनी जड़ों और मानवीय मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए युवा दिमागों को आकार देने में कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों की भूमिका की सराहना की।

एआई की सफलता जीवन को आसान करने वाले समाधान बनाने पर निर्भर करेगी : आईटी सचिव एस. कृष्णन

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, एस. कृष्णन ने मंगलवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रचार से परे सफल होगा या नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह ऐसे समाधान प्रदान करता है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन एल्गोरिदम से परिणामों तकः लोगों के लिए काम करने वाली एआई का निर्माण शीर्षक वाले सत्र को संबोधित करते हुए, कृष्णन ने कहा कि इंडिया एआई मिशन को विविध आवश्यकताओं और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने पैनल चर्चा में कहा, हम कंप्यूटिंग, मॉडल और डेटा केवल एक ही उद्देश्य वास्तविक प्रभाव डालने वाले एप्लिकेशन बनाने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप प्रदर्शनी में घूमेंगे, तो आपको स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में काम कर रहे सैकड़ों स्टार्टअप दिखाई देंगे। प्रभाव यहीं से उत्पन्न होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारों के पास कभी भी पर्याप्त शिक्षक, डॉक्टर या न्यायाधीश नहीं होंगे, लेकिन यदि एआई उत्पादकता बढ़ा सकता है, तो सेवा की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने आगे कहा, चुनौती यह है कि कारगर उपायों का चयन किया जाए, उन्हें जिम्मेदारीपूर्वक लागू किया जाए, गोपनीयता की रक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक धन से मापने योग्य परिणाम प्राप्त हों। इस महत्वपूर्ण सत्र में जन-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संप्रभु तकनीकी क्षमता की दोहरी अनिवार्यता का विश्लेषण किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक कल्याण में मापने योग्य सुधार लाएं। आधिकारिक बयान के अनुसार, चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि कंप्यूटिंग, मॉडल और डेटा का उपयोग अंततः ऐसे अनुप्रयोगों में कैसे किया जाना चाहिए जो उत्पादकता बढ़ाएं, शासन को मजबूत करें और नागरिकों को ठोस लाभ पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा कि यह समय वर्षभर के परिश्रम को निखारने का एक सुनहरा अवसर है और विद्यार्थियों को पूरे आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ परीक्षा में भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट पर अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा को उत्सव की तरह लेने की प्रेरणा दी है। उनका मूल मंत्र आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा।

उन्होंने विद्यार्थियों से प्रसन्नचित्त होकर अपनी मेधा का परिचय देने और धैर्य एवं निरंतर प्रयास को अपनी असली शक्ति बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि दिल्ली के छात्र अपनी लगन और मेहनत से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

ई–निविदा (ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

एनआईटी	82, 83, 84, 85, 86-W-V
काम का नाम (स्थान के साथ)	**82:** फरीदाबाद स्टेशन पर कॉमर्शियल RO सिस्टम लगाकर पानी की क्वालिटी में सुधार, साथ ही ADEN/TKD के तहत SSE/W/FDB सेक्शन में दो साल की AMC. **कार्य की समान प्रकृतिः** ट्रैक के काम के अलावा कोई भी सिविल कार्य।
	83: एडीईएन/टीकेडी के तहत तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी में पार्कों का विकास, खेल बुनियादी ढांचे (बास्केट बॉल कोर्ट, वॉलबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट), सड़क का निर्माण और अन्य संबद्ध कार्य। **कार्य की समान प्रकृतिः** ट्रैक के काम के अलावा कोई भी सिविल कार्य।
	84: ADEN/DEE के तहत "DLI-RE सेक्शन के बीच ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का प्रोविजन" के काम के लिए ऑटो रिले हट्स की सर्विस बिल्डिंग बनाने का बचा हुआ काम। **कार्य की समान प्रकृतिः** बिल्डिंग/क्वार्टर का कंस्ट्रक्शन।
	85: ADEN/DEE के तहत SSE/W/GGN सेक्शन में LHS नंबर 47A और 49 हम्प, क्रॉस–ड्रेन, साइड ड्रेन, सोक वेल और कवरिंग शेड का कंस्ट्रक्शन। **कार्य की समान प्रकृतिः** ट्रैक कार्य के अलावा कोई भी सिविल कार्य।
	86: सीनियर डीईएन/वी के तहत डीईई डिपो में जीर्ण–शीर्ण पुरानी वॉशिंग सह पिट लाइन नंबर 2 और 3 के प्रतिस्थापन का शेष कार्य। **कार्य की समान प्रकृतिः** कंक्रीटिंग कार्य से संबंधित कोई भी सिविल कार्य।
काम की अनुमानित लागत (₹)	**82:** ₹84,99,849.08; **83:** ₹93,99,216.97; **84:** ₹1,00,38,696.73; **85:** ₹2,33,74,930.70; **86:** ₹1,82,75,771.20
अग्रिम राशि (₹)	(यह नेट बैंकिंग के रूप में होना चाहिए या केवल भुगतान गेटवे द्वारा) **(नोटः** रेलवे बोर्डों के पत्र संख्या 2015/सीई–आई/सीटी/5/1 दिनांक 31.08.2016 के अनुसार जो टेंडर आईआरईपीएस पर आमंत्रित किया गया है उसमें एफडीआर को निविदा के लिए ईएमडी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा) **82:** ₹1,70,000/-; **83:** ₹1,88,000/-; **84:** ₹2,00,200/-; **85:** ₹2,66,900/-; **86:** ₹2,41,400/-
काम की समाप्ति अवधि	**82, 83, 84, 85, 86 के लिएः** 06 महीने
निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खोलने के लिए दिनांक और समय	13.03.2026 को 15:00 बजे तक तथा 13.03.2026 को 15:00 बजे निविदा खुलना है।
वेबसाइट के विवरण का नोटिस बोर्ड स्थान निविदा का पूरा विवरण	यह निविदा IREPS वेबसाइट अर्थात् **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है

No.: 128-W/280/OET/2025-26/NIT-82, 83, 84, 85, 86-W-V
Date: 16.02.2026 539/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

मेरठ के मेडिकल छात्र पर मेट्रो स्टेशन से पर्स चोरी का आरोप, 24 घंटे में गिरफ्तारी

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। मेट्रो यूनिट की नेहरू प्लेस मेट्रो थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर चोरी का मामला सुलझाते हुए छह लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने के गहने बरामद कर लिए। गहने एक 60 वर्षीय महिला के थे, जो टिकट काउंटर पर अपना पर्स भूल गई थीं। मेट्रो के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने मंगलवार को बताया कि 16 फरवरी को फरीदाबाद निवासी सुनीता ने शिकायत दी कि वह लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर अपना पर्स भूल गई थीं। पर्स में चार सोने की अंगूठियां, एक सोने की चेन व पेंडेंट, एक जोड़ी सोने के झुमके और नकदी थी। मामले को गंभीता से लेते हुए मेट्रो पुलिस ने स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में एक युवक दिखाई दिया, जो पर्स उठाकर स्टेशन के अंदर जाता नजर आया। डिजिटल जानकारी के आधार पर और डीएमआरसी के सहयोग से आरोपित का पता मेरठ (उप्र) में चला। मेट्रो पुलिस ने मेरठ के स्थानीय मेडिकल थाने की मदद से आरोपित को पकड़ लिया। उसकी पहचान आजिम-उल-हक (25) के रूप में हुई। वह मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्र है। पुलिस ने आरोपित के पास से चार सोने की अंगूठियां, एक सोने की चेन व पेंडेंट, दो सोने के झुमके और पर्स में रखी नकदी बरामद कर ली। सभी सामान सुरक्षित रूप से शिकायतकर्ता को लौटाने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपित का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

डीयू में पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट पर एक महीने के लिए रोक

नई दिल्ली, प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी के बाहर छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक कठोर कदम उठाते हुए परिसर में एक महीने के लिए किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार ने विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ को इस संबंध में सूचना हेतु एक आदेश जारी किया है जोकि 17 फरवरी 2026 से अगले एक महीने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश इस जानकारी के आधार पर जारी किया गया है, कि डीयू परिसर में बिना रोक-टोक के सार्वजनिक समारोहों, जुलूस या प्रदर्शन से ट्रैफिक में रुकावट, इंसानी जान को खतरा और जनशांति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी, आयोजक अक्सर ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है। प्रॉक्टर ने अपने आदेश में यह भी बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सब-डिवीजन सिविल लाइंस ने भी 26 दिसंबर, 2025 को इस आशय में एक आदेश जारी किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट भारत सरकार, के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी पब्लिक मीटिंग, रैली, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन अथवा किसी भी ऐसी गतिविधि पर रोक लगाई गई है जिससे कि आम लोगों की शांति या ट्रैफिक की सुगम आवाजाही पर असर पड़ सकता है। यह आदेश 17 फरवरी 2026 से लागू है और एक महीने तक लागू रहेगा। हालांकि डीयू के इस आदेश का शिक्षकों ने विरोध किया है। शिक्षक सुनील कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा जो कि धरने प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं या समाज में भेदभाव पैदा करने उसका विरोध भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। लेकिन ये आदेश जो कि प्रॉक्टर ऑफिस से निकला है उसमें प्रत्येक संगठन की प्रत्येक गतिविधियों पर एक महीने का पूरा प्रतिबंध लगाने का हम समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा प्रतिबंध हमारी अपनी जायज मांग को सवैधानिक तरीके से प्रशासन के सामने रखने की भी मनाई करता है। ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार किया गया है। इस नोटिस पर विश्विद्यालय को पुनः विचार करना चाहिए ऐसा हमारा अनुरोध है। कुछ अन्य शिक्षकों ने भी इसी प्रकार की राय रखी है।

राज्यपाल का अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों से साथ दिखा आगामी लक्ष्यों का खाका

मप्र को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य

● भोपाल, प्रात:किरण संवाददाता।

मप्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों का खाका पेश किया। राज्यपाल ने कहा कि देश अमृत काल की दहलीज पर खड़ा है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का उल्लेख किया। अभिभाषण में पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए सुधारों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का दृष्टिपत्र तैयार किया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास, कृषि उन्नति और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं।

दूध उत्पादन में नई ऊंचाई का लक्ष्य

अभिभाषण में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का भी विशेष उल्लेख किया गया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाईयां स्थापित हैं, जिनमें 1 करोड़ 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही, प्रदेश में 6 हजार 670 से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत है। राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, सड़क, पेयजल और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

बुनियादी ढांचे और बड़े प्रोजेक्ट्स पर जोर

अभिभाषण में प्रदेश में चल रही बड़ी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया। लाड़ली बहना, संपदा 2.0, यूनिपे-डीबीटी, ई-एचआरएमएस, एमपीएसएसओ और सायबर तहसील जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों से सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जीआईएस, ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से नगरीय नियोजन, भूमि प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण में डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को सशक्त बनाया गया है। सड़क, सिंचाई, शहरी विकास और औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के जरिए प्रदेश को तेज विकास पथ पर ले जाने की बात कही गई। साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

किसानों के हित में सरकार प्रतिबद्ध

राज्यपाल ने कहा कि सरकार वर्ष 2026 को समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की थीम पर मना रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। फसल विविधीकरण, सिंचाई विस्तार और समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का विशेष ध्यान है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑफ नेचरल फॉर्मिंग को प्रभावी तरीके से लागू किया है। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। हमारा अन्नदाता समृद्ध होगा।

मप्र में पुलों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा

पुलों की सुरक्षा और उनकी स्थिति की होगी सटीक निगरानी

भोपाल। मप्र में पुलों की सुरक्षा और उनकी स्थिति की सटीक निगरानी के लिए डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है। सरकार प्रदेश के सभी प्रमुख, पुराने और विशेषकर शार्प टर्न (तीखे मोड़) वाले पुलों का तकनीकी सर्वे डिजिटल माध्यमों से करवाएगी। जानकारी के अनुसार, प्रदेश में पुलों की सुरक्षा, मरम्मत और मजबूती की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। मप्र सड़क विकास निगम लिमिटेड ने मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट के जरिए राज्य भर के पुलों का डिजिटल सर्वे कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निगम ने परामर्श सेवाओं की निविदाएं जारी की हैं, जिनके माध्यम से पुलों की इन्वेंटरी, स्थिति सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। जानकारी के अनुसार, प्रदेश के सालों पुराने पुलों से भविष्य में किसी प्रकार की आपदा न हो इसके लिए अब प्रदेश के छह मीटर से साठ मीटर के मध्यम पुल और साठ मीटर से अधिक लंबाई वाले वृहद पुलों का गूगल शीट पर डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। वहीं बीस साल पुराने सभी पुलों का प्रोफेशनल सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। केबल रोपवे, सस्पेंशन पुल, स्टे ब्रिज सहित अन्य पुलों की भी विशेष देखरेख मानीटरिंग का इंतजाम किया जाएगा। निगम द्वारा जारी निविदा के अनुसार के माध्यम से राज्यभर में सभी श्रेणी की सड़कों पर बने बड़े-छोटे पुल, फ्लाय ओवर, पुलिया और स्लैब नालियों का इन्वेंटरी डेटा तैयार किया जाएगा। साथ ही उनकी मौजूदा स्थिति का सर्वे कर उन्हें मजबूत बनाने, रेट्रोफिटिंग या पुनर्निर्माण का आंकलन किया जाएगा।

मप्र के किसानों की बल्ले-बल्ले...जारी हुआ

सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन

भोपाल। मप्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों को स्थाई बिजली कनेक्शन देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को महज 5 रुपए में स्थाई विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद किसानों को अब ढाई हजार की जगह महज 5 रुपए देकर स्थाई कनेक्शन मिल जाएगा।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी किसानों को 5 हॉर्स पॉवर तक के ऑनलाइन स्थाई कृषि विद्युत कनेक्शन ढाई हजार रुपए की जगह पर मात्र पांच रुपए में देगी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों को पांच हॉर्स पॉवर तक स्थाई कृषि संयोजन के लिए आवेदन शुल्क को मात्र 5 रुपए निर्धारित किया है। यह सुविधा उन मामलों में दी जाएगी, जहां विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण ने बताया कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है।

बिल में शामिल होगी राशि

नए फैसले के तहत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा स्थापित सर्विस लाइन की सुरक्षा नियमों की जांच के उपरांत मात्र 5 रुपए शुल्क में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि शेष सुरक्षा निधि की राशि प्रथम विद्युत बिल में समायोजित की जाएगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत सुविधा सरल, सुलभ एवं किफायती बनाना है। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऑनलाइन स्थाई कृषि पंप संयोजन जारी करने की कार्रवाई नियमानुसार शीघ्र पूर्ण की जाए, जिससे किसानों को समय पर लाभ मिल सके।

विधानसभा बजट सत्र के बाद ही सजेगी सियासी चौसर!

● भोपाल, प्रात:किरण संवाददाता।

मध्य प्रदेश की सियासत में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। चर्चा थी कि फरवरी में ही निगम-मंडलों और प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़ी सूची जारी हो सकती है, लेकिन अब संकेत साफ हैं। विधानसभा के बजट सत्र के बाद ही ताजपोशी का दौर शुरू होगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए नेताओं को ताजपोशी के लिए इंतजार करना होगा।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर मुलाकातें की हैं और संगठन के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ भी मंथन हो चुका हैं। इससे पहले एक छोटी समन्वय बैठक भी हुई थी, जिसमें संभावित नामों पर प्रारंभिक चर्चा बताई जा रही है। हालांकि अब पार्टी ने प्राथमिकता विधानसभा सत्र और बजट को दे दी है। पार्टी का मानना है कि बजट सत्र काफी लंबा चलने वाला है। इसलिए पार्टी और संगठन स्तर पर नियुक्ति का समय ठीक नहीं है। फिलहाल कुछ दिनों का इंतजार और किया जा सकता है।

हैवीवेट नेताओं को साधना सबसे बड़ी कसौटी

भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन हैवीवेट नेताओं को एडजस्ट करने की है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजित हो गए थे। इनमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, जिनका कद और अनुभव बड़ा है। ऐसे नेताओं को सक्रिय बनाए रखना और संगठन या सरकार में नई भूमिका देना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। दिक्कत यह भी है कि कई पूर्व मंत्रियों का राजनीतिक स्तर निगम-मंडल की जिम्मेदारी से ऊपर माना जाता है। ऐसे में उन्हें किस पद पर और किस भूमिका में समायोजित किया जाए। इस पर मंथन जारी है। रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन अंतिम सूची तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा।

मप्र कांग्रेस ने सभी जिलाअध्यक्षों से खाली जमीनों का मांगा ब्यौरा

पार्टी की हर संपत्ति का दस्तावेजी ब्योरा उपलब्ध कराया

● भोपाल, प्रात:किरण संवाददाता।

मध्य प्रदेश की राजनीति में नए सिरे से सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब अपनी आर्थिक सेहत सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर कांग्रेस के नाम दर्ज जमीन, भवन और अन्य अचल संपत्तियों की विस्तृत जानकारी मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि संगठन अपनी निष्क्रिय या कम उपयोग में आ रही संपत्तियों को किराए पर देकर स्थायी फंड जुटाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से कई जिलों में कांग्रेस की जमीन और भवनों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से अपडेट नहीं हुआ था। कई जगह पुराने कार्यालय जर्जर हालत में हैं, तो कुछ संपत्तियां वर्षों से बंद पड़ी हैं। ऐसे में मुख्यालय ने सभी इकाइयों को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी की हर संपत्ति का दस्तावेजी ब्योरा उपलब्ध कराया जाए, चाहें वह उपयोग में हो, खाली हो या विवादित स्थिति में हो।

एक हजार करोड़ से ज्यादा संपत्ति का अनुमान

आंतरिक आकलन के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नाम पर दर्ज संपत्तियों का कुल मूल्य करीब एक हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। हालांकि यह अनुमानित आंकड़ा है और वास्तविक स्थिति जिला इकाइयों से मिलने वाली रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। संगठन का मानना है कि यदि इन संपत्तियों का पेशेवर प्रबंधन किया जाए तो पार्टी को नियमित आय का बड़ा स्रोत मिल सकता है, जिससे चुनावी और संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी जा सके।

कब्जों और विवादों की शिकायत: कई जिला अध्यक्षों ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ स्थानों पर कांग्रेस की पुरानी जमीनों और भवनों पर अवैध कब्जे हैं। आरोप हैं कि स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों या राजनीतिक विरोधियों ने संपत्तियों पर नियंत्रण जमा रखा है। मुख्यालय ने ऐसे मामलों में पूरी जानकारी मांगी है, ताकि कानूनी कार्रवाई कर संपत्तियों को मुक्त कराया जा सके। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि संपत्ति का संरक्षण संगठन की सामूहिक जिम्मेदारी है। भोपाल मॉडल से प्रेरणा- हर महीने 25 से 30 लाख की आय राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के नाम दर्ज भवन को एक सफल उदाहरण माना जा रहा है। यहां स्थित दुकानों को किराए पर देकर हर महीने करीब 20 से 25 लाख रुपये की आय पार्टी को होती है। इसी राशि से प्रदेश कार्यालय का संचालन, नेताओं के दौरे और विभिन्न कार्यक्रमों का खर्च वहन किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि इसी मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू करने पर विचार हो रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर कदम राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में दलों के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़

सौम्या चौरसिया ने लगाई एक साथ दो जमानत याचिकाएं

हाई कोर्ट ने ईडी और राज्य शासन से 20 फरवरी तक मांगा जवाब

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाले के बाद शराब घोटाला केस में हाई कोर्ट में दो जमानत याचिकाएं लगाई है. मामले में ईडी और राज्य शासन ने जवाब के लिए 10 दिन का समय मांगा, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने नामंजूर करते हुए 20 फरवरी से पहले जवाब मांगा है.बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था. लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया था. अब ईडी और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया है.

सौम्या चौरसिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया. जिसके बाद सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की है.

सौम्या की वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां नई-नई एफआईआर दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं. अब तक उन्हें 6 बार हिरासत में लिया जा चुका है. यह सब राजनीतिक षडयंत्र के तहत किया जा रहा है.मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करें. साथ ही हाईकोर्ट को उनकी याचिका पर प्राथमिकता से सुनवाई करने कहा है.

सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य शासन की तरफ से इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया. जिसे हाई कोर्ट ने नामंजूर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है. जवाब के लिए समय दिया गया तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. इसके साथ ही 20 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है।

राजधानी में उठाईगिरी रजिस्ट्री कराने आए अफसर की कार से 38 लाख पार ,जांच में जुटी पुलिस

रायपुर। राजधानी रायपुर में जमीन रजिस्ट्री कराने आए अफसर की गाड़ी से 38 लाख रुपए पार हो गए. उठाईगिरी करने के आरोप में क्राइम ब्रांच की टीम अफसर के परिचित सहित अन्य चार को हिरासत में लेकर पड़ताल करने के बाद क्राइम ब्रांच ने बरामद की रकम पूछताछ कर रही है. पुलिस ने चोरी की रकम बरामद कर ली है. घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ऑक्सीजोन की है.मंदिर हसौद निवासी एफसीआई के अफसर ज्ञानप्रकाश पाण्डेय जमीन रजिस्ट्री कराने सोमवार को कलेक्टोरेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय कार से पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि कार की सीट पर पैसे रखकर वे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान अज्ञात चोर ने कार की सीट से नोटों से भरा बैग पार कर दिया. रकम गायब देख ग्रामीण शिकायत करने थाने पहुंचा. उठाईगिरी की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर चोर के बारे में पतासाजी करने जुट गई. रखवाली करने वाले की बिगड़ी नियत।

व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चल रहा था सट्टा नेटवर्क पुलिस ने दो महिला सटोरियों को किया गिरफ्तार

कवधा, प्रात:किरण संवाददाता।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप समूह के जरिए संचालित हो रहे सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में दो महिला सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से नगद राशि, सट्टा-पट्टी और अन्य सामग्री जब्त की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहला मामला कवर्धा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 शिवाजी कॉलोनी का है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। यहां नन्दिनीन उर्फ नीलू गुप्ता को उसके घर के सामने अंकों पर सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से सट्टा-पट्टी, नगद रकम और पेन बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।

दूसरी कार्रवाई वार्ड क्रमांक 05 लोहाराना देवारपारा क्षेत्र में की गई। यहां पूजा बांधेकर को सट्टा गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके विरुद्ध पृथक अपराध दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि दोनों महिला आरोपी व्हाट्सएप समूह बनाकर अलग-अलग नामों से सट्टा संचालन कर रही थीं। वे विभिन्न समूहों के माध्यम से खाईवाली के नाम से अंकों का लेन-देन करती थीं और मोबाइल के जरिए सट्टा खेलवाया जाता था। पुलिस को प्रारंभिक जांच में कुछ अन्य

व्यक्तियों के नाम भी प्राप्त हुए हैं, जो इस नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्य संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके और समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे।.

CM साय ने बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का बढ़ाया आत्मविश्वास, कहा- ऑल द बेस्ट, प्यारे बच्चों

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आत्मविश्वास और हौसले के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है. उन्होंने विद्यार्थियों के नाम अपने आत्मीय संदेश में कहा कि परीक्षाओं का समय जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसमें उत्साह के साथ थोड़ा तनाव भी स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है.मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि परीक्षाओं का समय आ गया है. मैं जानता हूं कि इन दिनों आपके मन में उत्साह भी है और थोड़ा सा तनाव भी. लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए — आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं उन्होंने कहा कि परीक्षाओं का समय कभी-कभी मन में घबराहट भी लेकर आता है. यह स्वाभाविक है. यदि आपको डर लग रहा है तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को गंभीरता से लेते हैं.उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह समझ लीजिए — डर कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है. लेकिन इस डर को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें. आपने पूरे वर्ष मेहनत की है. हर दिन का प्रयास, हर अभ्यास, हर दोहराव — सब आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़े हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी नियमित पढ़ाई करें, कठिन विषयों को दोहराएं, समय का संतुलन बनाए रखें. पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें।

निर्णय

ने ने ने ने ने ने ने

बिना अनुमति डीजे संचालन पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई, वाहन किया जब्त

रायपुर, प्रात:किरण संवाददाता।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत गोल बाजार थाना क्षेत्र में बिना वैध पुलिस अनुमति डीजे संचालित करने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई को कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करते हुए डीजे वाहन व उपकरण जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि डीजे संचालक कुणाल बावले, जो मूलतः धमतरी के निवासी है, वह बिना अनुमति डीजे चला रहा था, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही थी।बता दें कि डीसीपी सेंट्रल ज़ोन की अध्यक्षता में पहले आयोजित बैठक में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शोर-शराबे से बचने की भी अपील की गई थी।

पूर्व में दी गई चेतावनी और अपील के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध डीजे संचालन पर आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और बिना अनुमति संचालन करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

एआई समिट नयी चुनौतियां

सोमवार 16 फरवरी से नयी दिल्ली में भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरूआत हुई, जो 20 फरवरी तक चलेगी। एआई पर यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कम से कम 20 देशों के राष्ट्रप्रमुख, 50 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा बड़े सीईओ हिस्सा लेने आ रहे हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डेरियो अमोडी, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ, एडोब के शांतनु नारायण जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इन तमाम बड़ी हस्तियों की एक साथ एक बैनर के नीचे उपस्थिति यह बता रही है कि दुनिया ने एक बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिया है, जो ऊपरी तौर पर केवल तकनीकी से जुड़ा नजर आता है, लेकिन असल में इसका असर जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ना शुरू हो चुका है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब हर क्षेत्र में दिखाई देने लगी है। विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, व्यापार हर जगह अब एआई का सहयोग लिया जा रहा है। दशकों तक भू राजनैतिक आकलन बंद दरवाजों के पीछे विदेशी राजनयिकों और जांच एजेंसियों के भरोसे होता रहा, क्योंकि सरकारी दस्तावेज और अंदरूनी खबरों तक इन्हीं की पहुंच होती थी। थिंक टैंक्स, रिस्क एनालिस्ट्स (जोखिम विश्लेषकों) या मीडिया के आकलन सब राजनयिकों और जांच एजेंसियों के सूत्रों पर निर्भर होते थे। लेकिन अब एआई ने यह परिदृश्य भी बदल दिया है। अब एआई की मदद से विभिन्न देशों में लिए जा रहे फैसलों, सेटेलाइट छवियों, आयात-निर्यात, पूंजी का प्रवाह, मीडिया में चलाई जा रही खबरों सब पर निगाह रखने के साथ तुरंत ही उसका विश्लेषण भी किया जा रहा है। नतीजा ये है कि एक देश के हालात का असर दूसरे देश पर पड़ने में पहले जितना वक्त लगता था, अब वो कुछ पलों में सिमट चुका है। ऐसे महत्वपूर्ण समय परिदृश्य में भारत में इस एआई समिट के होने के खास मायने हैं, क्योंकि दुनिया इसे ग्लोबल साउथ की बढ़ती ताकत के नजरिए से देख रही है। औपनिवेशिक दासता से मुक्त देश तीसरी दुनिया कहलाते रहे हैं, अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ऐसे तमाम देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा कहलाते हैं। ग्लोबल साउथ एक भौगोलिक शब्द न होकर भू-राजनीतिक और आर्थिक धारणा है। एआई समिट का भारत में होना तीसरी दुनिया के उन तमाम देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिनके डेटा तक वैश्विक शक्तियों की पहुंच है। इन देशों के राजनैतिक, आर्थिक फैसलों पर वैश्विक शक्तियां इसी डेटा की मदद से प्रभाव डालती हैं। और इसमें एआई की मदद ली जाती है। ऐसे में इस समिट के दौरान कुछ बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे क्या भारत बड़ी वैश्विक शक्तियों के सामने अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठा सकेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में और बाद में भी एआई के खतरों और संभावनाओं दोनों को खुल कर सरकार के सामने रखा है। राहुल ने कहा, एआई क्रांति आ गई है, जो खतरे और मौके दोनों लेकर आ रही है। आईटी और सर्विसेज सेक्टर, हमारी अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा है वो खतरे में है। अगर हम आने वाले तूफान के लिए तैयार नहीं हुए तो हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेशनल अपनी रोजी-रोटी खो देंगे लेकिन हमारे पास मौके भी हैं। राहुल गांधी ने कहा, डेटा वो पेट्रोल है जो एआई इंजन को चलाता है। जैसा कि मैंने संसद में कहा था कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे शानदार लोग हैं और वह बहुत सारा डेटा जो हम बनाते हैं। राहुल ने एआई समिट की मेजबानी पर कहा कि यह भारत के लिए नेतृत्व दिखाने का एक मौका होना चाहिए था, यह दिखाने का कि 1.4 बिलियन लोगों का देश अपने डेटा का इस्तेमाल करके ग्लोबल एआई फ्यूचर को अपनी शर्तों पर कैसे बना सकता है। लेकिन बेबस प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील में अमेरिका के चोकहोल्ड के आगे समर्पण कर दिया है। राहुल ने देश को सावधान करते हुए कहा कि भारत में 1.5 बिलियन भारतीयों का डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर करना, अपने सोर्स कोड और एल्गोरिदम में पारदर्शिता लाना, हमारे डेटा का इस्तेमाल करके होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाना मुश्किल होगी। राजनैतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर राहुल गांधी की इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अभी भारत को यह देखना है कि हमारा आईटी सेक्टर एआई के इस दौर के लिए कब पूरी तरह तैयार होगा। चैट जीपीटी जैसे बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत को खुद बनाने चाहिए, या छोटे-छोटे सेक्टर जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए खास एआई टूल पर फोकस करना चाहिएइ एआई को चलाने के लिए बहुत सारे डेटा सेंटर चाहिए, जो बिजली और पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होगा ?ऐसे कई सवालों पर इस समिट में चर्चा हो, तभी इसकी सार्थकता है। वैसे भारत सरकार ने इरादा जताया है कि एआई सिर्फ बड़े देशों का खेल न रहे, बल्कि सभी देशों के लिए फायदेमंद हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि हमारा ध्यान ह्यपीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर है।

संतोषः परमं धनम-संतोष ही सबसे बड़ा धन है

सुनील कुमार महला

संस्कृत साहित्य में यह बात कही गई है कि- संतोषः परमं धनम्, अर्थात संतोष मनुष्य का सबसे मूल्यवान धन है। इससे बड़ा धन दुनिया में कोई और नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हमारे पास है, उसमें प्रसन्न रहना ही सच्ची समृद्धि है। आज की तेज भागदौड़, तनाव और अवसाद भरी दुनिया में लोग अधिक से अधिक धन, सुख-सुविधाएँ और प्रतिष्ठा पाने के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी संपत्ति हमें केवल थोड़े समय का सुख(क्षणिक सुख) दे सकती है, स्थायी मानसिक शांति नहीं। पाठक जानते हैं कि मनुष्य की इच्छाएँ कभी समाप्त नहीं होतीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। यदि व्यक्ति केवल इच्छाओं के पीछे ही भागता रहे, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास बहुत धन है लेकिन संतोष नहीं, वह भी मन से गरीब ही रहता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति संतोषी है, वह सीमित साधनों में भी सुखी और शांत जीवन जी सकता है। संस्कृत में कहा गया है कि -यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥ इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सहज प्राप्त वस्तु में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से मुक्त होता है और सफलता-असफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। वास्तव में, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य महत्वाकांक्षा छोड़ दे या प्रगति करना बंद कर दे। इसका सही अर्थ है- प्रयास करते हुए भी मन में लोभ, ईर्ष्या और असंतोष को स्थान न देना। संतोषी व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, बल्कि उनसे वह प्रेरणा लेता है। उसका जीवन सरल, संतुलित और तनावमुक्त होता है। यही कारण है कि संतोष मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और मनुष्य मन को शांति भी देता है। वास्तव में संतोष का भाव व्यवहार से जुड़ा है- संतोषी व्यक्ति सबका प्रिय बनता है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया -न कश्चित् कस्यचिद् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा॥ संतोष मनुष्य को नैतिक और ईमानदार भी बनाता है। असंतोष ही वह कारण है, जिसके कारण व्यक्ति लालच में पड़कर गलत रास्ता अपनाता है। यदि व्यक्ति संतोषी हो, तो वह अनुचित तरीकों से धन कमाने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार संतोष समाज में नैतिकता और सदाचार को भी बढ़ावा देता है। संतोष का संबंध केवल धन या वस्तुओं से नहीं, बल्कि जीवन की परिस्थितियों से भी है। जीवन में कठिनाइयाँ और असफलताएँ आती हैं, लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य और संतोष बनाए रखे, तो वह उन्हें आसानी से पार कर सकता है। संतोष मानसिक शक्ति देता है और निराशा से बचाता है। संतोषी व्यक्ति वर्तमान में जीना जानता है - वह न अतीत के पछतावे में उलझता है और न भविष्य की चिंता में, बल्कि वर्तमान क्षण का आनंद लेता है। इसके अलावा, संतोष का संबंध कृतज्ञता से भी है। जो व्यक्ति अपने जीवन की छोटी-छोटी खुशियों के लिए आभारी रहता है, वही सच्चा संतोष अनुभव करता है। उसका सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके भीतर से उत्पन्न होता है। अंततः, यह बात कही जा सकती है कि धन-दौलत जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, पर सच्चा सुख केवल संतोष से मिलता है। जिस व्यक्ति के पास संतोष का खजाना है, वह हर परिस्थिति में आनंद और शांति महसूस करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता को विकसित करना चाहिए।

पारदर्शिता की पहल, पर एकरूपता के अभाव में अदालतों तक पहुंचते कर्मचारी

सभी विभागों में समान कार्यकाल व्यवस्था लागू हो, जिससे कर्मचारियों को समान अवसर मिल सकें। नई नियुक्तियों को समयबद्ध रूप से ऑनलाइन प्रणाली में शामिल किया जाए, ताकि वरिष्ठता प्रभावित न हो। स्थानांतरण प्रक्रिया का निश्चित वार्षिक कार्यक्रम हो, जिससे पारदर्शिता बढ़े और कर्मचारियों में अनिश्चितता समाप्त हो हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर मनमानी, सिफारिश, पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने और प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष तथा योग्यता आधारित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू की गई। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, सेवा अवधि और विशेष परिस्थितियों के आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से कार्यस्थल आवंटित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो। यह नीति आधुनिक प्रशासनिक सोच और तकनीकी उपयोग का सकारात्मक उदाहरण है। 50 या उससे अधिक पदों वाले संवर्गों पर लागू इस व्यवस्था में 80 अंकों का योग्यता आधारित मूल्यांकन तंत्र निर्धारित किया गया है। इसमें आयु और कुल सेवा अवधि को प्रमुख आधार बनाया गया है,

डॉ. सत्यवान सौरभ

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

सभी कर्मचारियों की एकमुश्त अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि कार्यस्थल वरिष्ठता निष्पक्ष रूप से निर्धारित हो और भविष्य में किसी प्रकार की असमानता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद पारंपरिक स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सभी विभागों में समान कार्यकाल व्यवस्था लागू हो, जिससे कर्मचारियों को समान अवसर मिल सकें। नई नियुक्तियों को समयबद्ध रूप से ऑनलाइन प्रणाली में शामिल किया जाए, ताकि वरिष्ठता प्रभावित न हो। स्थानांतरण प्रक्रिया का निश्चित वार्षिक कार्यक्रम हो, जिससे पारदर्शिता बढ़े और कर्मचारियों में अनिश्चितता समाप्त हो हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर मनमानी, सिफारिश, पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने और प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष तथा योग्यता आधारित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू की गई। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, सेवा अवधि और विशेष परिस्थितियों के आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से कार्यस्थल आवंटित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो। यह नीति आधुनिक प्रशासनिक सोच और तकनीकी उपयोग का सकारात्मक उदाहरण है। 50 या उससे अधिक पदों वाले संवर्गों पर लागू इस व्यवस्था में 80 अंकों का योग्यता आधारित मूल्यांकन तंत्र निर्धारित किया गया है। इसमें आयु और कुल सेवा अवधि को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिससे वरिष्ठता को उचित महत्व मिल सके। सेवा अवधि को 365 दिनों से विभाजित कर अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनती है। महिला कर्मचारियों को 10 अंक, पतिझपत्नी मामलों में 5 अंक तथा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामलों में 10 से 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से जुड़े ऑनलाइन मंच के माध्यम से संचालित होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद संवर्ग सूची सार्वजनिक की जाती है और कर्मचारी एकमुश्त पासवर्ड के माध्यम से सत्यापन कर अपने पसंदीदा कार्यस्थलों का चयन करते हैं। निर्धारित समय में विकल्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में कर्मचारी को किसी भी स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है। अतिरिक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाता है तथा आदेश जारी होने के निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होता है। नीति लागू होने के बाद कई विभागों में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों में कमी भी आई है। ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र ने कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मंच दिया है। इससे यह विश्वास मजबूत हुआ है कि अंकीय प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक सुधार प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं। फिर भी, नीति के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। सभी विभागों में समान कार्यकाल, समान समय-सारिणी और समान नियम लागू नहीं हैं। कहीं न्यूनतम कार्यकाल अलग है, कहीं अधिकतम कार्यकाल की सीमा भिन्न है, तो कहीं विशेष परिस्थितियों की परिभाषा बदल जाती है। इससे समान संवर्ग के कर्मचारियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है और नीति की मूल भावना प्रभावित होती है। ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान की पहली ही प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की एकमुश्त अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रारंभिक चरण में कुछ कर्मचारी किसी कारणवश बाहर रह जाते हैं, तो उनकी कार्यस्थल वरिष्ठता प्रभावित होती है और भविष्य में विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए ह्लएक बार की अनिवार्य सहभागिताह्व के माध्यम से सभी कर्मचारियों को समान आधार पर लाना चाहिए। सभी विभागों में निर्धारित कार्यकाल समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष या एक स्थानांतरण अभियान से अगले अभियान तक तथा अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया जा सकता है। इससे कोई भी कर्मचारी अत्यधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहेगा और न ही किसी को अल्प अवधि में बार-बार स्थानांतरण झेलना पड़ेगा। जब भी नई नियुक्ति हो, उसे अनिवार्य रूप से अगले स्थानांतरण अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद अब तक कोई कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे वर्तमान अभियान में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे सभी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्यस्थल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और मनमानी या रिश्वतखोरी के माध्यम से पारंपरिक आदेशों द्वारा कार्यस्थल प्राप्त करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। सभी विभागों में स्थानांतरण अभियान एक ही समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इससे पतिझ पत्नी प्रकरणों में निर्णय लेने में सुविधा होगी और परिवारों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि विभिन्न विभाग अलग-अलग समय पर स्थानांतरण करेंगे, तो पारिवारिक समन्वय कठिन हो जाता है। कार्यकाल की गणना करते समय वित्तीय वर्ष को एक वर्ष माना जाना चाहिए, न कि दिनों की गणना के आधार पर। कई बार स्थानांतरण अभियान वित्तीय वर्ष के मध्य में पूरा होता है और कार्यभार ग्रहण वर्ष के अंतिम चरण में होता है, जिससे कार्यकाल की गणना में एक वर्ष का अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि वित्तीय वर्ष को पूर्ण इकाई के रूप में

शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रनिर्माण की नई पहल - कॉलेजों में मातृभाषा के साथ दूसरी भारतीय भाषा अनिवार्य

वर्ष 2026 से देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को मातृभाषा के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यह दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किया गया है और यह नियम स्नातक, परास्नातक (PG) और पीएचडी, तीनों स्तरों पर लागू होगा। यह निर्णय केवल शैक्षणिक सुधार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और विकसित भारत 2047 के विजन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यूजीसी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह व्यवस्था लागू होगी। इस नीति के अंतर्गत हर छात्र को मातृभाषा के अतिरिक्त कम-से-कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी होगी। यह अध्ययन अनिवार्य लेकिन लचीला (Flexible) होगा। छात्रों को प्रवेश और निकास (Exit) के बहुविकल्पी अवसर मिलेंगे। यह व्यवस्था नये क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत लागू की जाएगी। यह पूरी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।

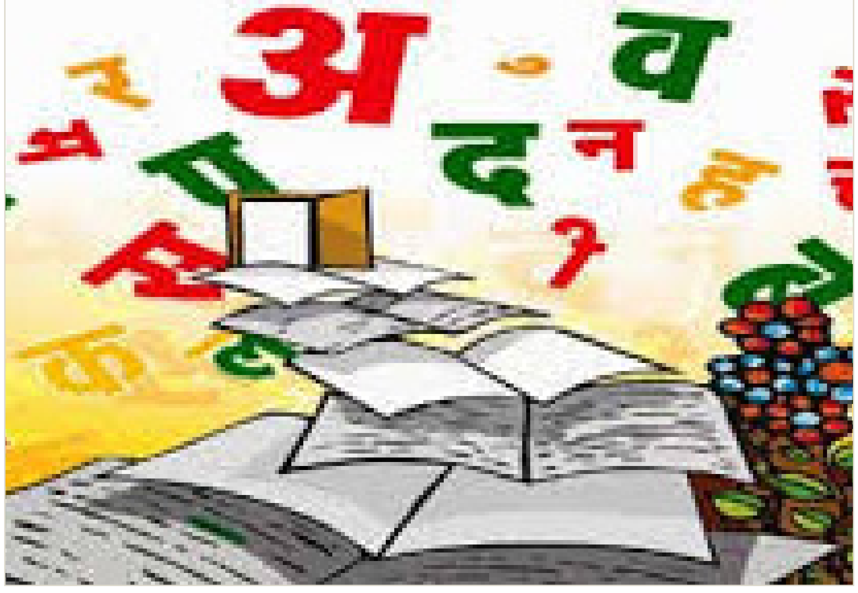

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

लेखक

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और पहचान की वाहक हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा में भाषाओं को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। वर्ष 2026 से देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को मातृभाषा के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यह दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किया गया है और यह नियम स्नातक, परास्नातक (PG) और पीएचडी, तीनों स्तरों पर लागू होगा। यह निर्णय केवल शैक्षणिक सुधार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और विकसित भारत 2047 के विजन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यूजीसी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह व्यवस्था लागू होगी। इस नीति के अंतर्गत हर छात्र को मातृभाषा के अतिरिक्त कम-से-कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी होगी। यह अध्ययन अनिवार्य लेकिन लचीला (Flexible) होगा। छात्रों को प्रवेश और निकास (Exit) के बहुविकल्पी अवसर मिलेंगे। यह व्यवस्था नये क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत लागू की जाएगी। यह पूरी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। NEP 2020 के प्रमुख भाषा-संबंधी उद्देश्य बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। मातृभाषा में शिक्षा को सशक्त करना। भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा और शोध से जोड़ना। भाषा को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ना। नई नीति ठएढ 2020 के इन सभी लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास है। यह भाषा कार्यक्रम तीनों उच्च शैक्षणिक स्तरों पर लागू होगाः स्नातक (UG) स्तर पर भाषा को एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स (AEC) के रूप में शामिल किया जा सकता है और यह मेजर या माइनर कोर्स का हिस्सा बन सकता है। परास्नातक (PG) स्तर पर विषयगत अध्ययन के साथ भाषा कौशल का विकास, शोध और अकादमिक लेखन में सहायता। पीएचडी स्तर पर अंतर-राज्यीय शोध में सहूलियत, क्षेत्रीय साहित्य और स्रोतों तक सीधी पहुँच। यूजीसी ने भाषा शिक्षण को तीन स्पष्ट चरणों में विभाजित किया है। पहला बेसिक (BÔsic Leve'), जिसमें दैनिक संवाद, सामान्य शब्दावली और परिचयात्मक व्याकरण। दूसरा इंटरमीडिएट जिसमें अकादमिक लेखन, सांस्कृतिक समझ और सामान्य साहित्य का अध्ययन। तीसरा एडवांस जिसमें साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथ, अनुवाद और व्याख्या और शोध एवं आलोचना। छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार, किसी भी स्तर से शुरूआत कर सकता है। नई भाषा नीति की एक बड़ी विशेषता है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। छात्र एक सेमेस्टर के बाद कोर्स छोड़ सकता है। तीन सेमेस्टर पूरे करने पर माइनर डिग्री और आवश्यकता अनुसार, दोबारा प्रवेश का विकल्प। यह व्यवस्था वर्किंग प्रोफेशनल्स और ओपन लर्निंग के छात्रों के लिए भी उपयोगी होगी। यूजीसी ने निर्देश दिया है कि संस्थानों को छात्रों के लिए आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से विकल्प देना होगा। इनमें प्रमुख हैं हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कश्मीरी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, कोंकणी, सिंधी और मणिपुरी। इससे छात्रों को अपने राज्य से बाहर की भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भाषा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है, बल्कि संस्कृति की आत्मा होती है। इस पहल से राज्यों के बीच सांस्कृतिक दूरी कम होगी। एक-दूसरे की परंपराओं को समझने का अवसर मिलेगा और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत होगी। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का भाषा शिक्षण एप, ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे देश-विदेश से छात्र जुड़ सकेंगे। भाषा विशेषज्ञ मेंटर्स की भूमिका निभाएंगे और लाइव सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर, संवाद अभ्यास चलेगा। यूजीसी ने यह स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय स्वयं पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकते हैं। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सामग्री तैयार की जा सकती है और क्रेडिट कोर्स, ऑडिट कोर्स या स्किल कोर्स, तीनों विकल्प खुले हैं। इस भाषा कार्यक्रम में 12वीं पास कोई भी व्यक्ति, 16 वर्ष से अधिक आयु का छात्र, नियमित, ओपन या डिस्टेंस मोड, सभी पात्र होंगे। आज के समय में बहुभाषी व्यक्ति को अधिक अवसर, पर्यटन, मीडिया, प्रशासन, अनुवाद, शिक्षण में मांग, स्टार्टअप और अंतर-राज्यीय व्यापार में लाभ, यह नीति भाषा को रोजगारपरक कौशल के रूप में स्थापित करती है। यह पहल ऐतिहासिक है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी सामने आएंगी। योग्य भाषा शिक्षकों की उपलब्धता। छोटे कॉलेजों में संसाधनों की कमी और छात्रों पर अतिरिक्त अकादमिक दबाव। समाधान के तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग, साझा फैकल्टी मॉडल और भाषा को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मातृभाषा के साथ एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य करना केवल शैक्षणिक सुधार नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा कदम है। यह नीति भारत की भाषाई विरासत को सशक्त करेगी। युवाओं को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाएगी और विकसित भारत 2047 के सपने को मजबूत आधार देगी। भाषा जब शिक्षा से जुड़ती है, तो वह केवल शब्द नहीं सिखाती है बल्कि वह संवेदना, समझ और समरसता का निर्माण करती है। यही इस नई नीति की

लोकतंत्र में राइट टू रीकॉल की चर्चा जरूरी

डॉ. निधि शर्मा

इस अधिकार के जमीनी स्तर पर आने से सबसे पहले भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को जनता नहीं चुनेगी और प्रतिनिधि जनता की सेवा और उनके कल्याण के कामों को करने के लिए जवाबदेह रहेगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए विशेषकर युवावर्ग में इसके प्रति विश्वास पैदा करना होगा। क्योंकि वोट प्रतिशत का गिरना लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। इस नींव की मजबूती के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आना ही होगा। क्योंकि इस प्रकार के निर्णय दूरगामी प्रभाव डालते हैं अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा द्वारा राइट टू रीकॉल मुद्दे को संसद में उठाया गया, जो वर्तमान की राजनीति और राजनीतिज्ञों की स्थिति को देखकर जरूर इस विषय पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार, लेकिन क्या तंत्र असलियत में अपना राजधर्म निभा रहा है, इसका निर्णय भी जनता को ही करना चाहिए। हमारा दायित्व सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हालांकि यह आंकड़ा भी चुनावों के दौरान औसतन 50 से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाता। शेष बची 40 से 45 प्रतिशत जनता इसलिए वोट नहीं डालती कि उन्हें उम्मीदवार पसंद नहीं था, उन्हें वोट डालना पसंद नहीं था या वो वर्तमान के राजनीतिक हालात से खुश नहीं हैं। ऐसी कई संभावनाएं हैं जो वोट के प्रतिशत को चुनाव आयोग के कई आयोजनों के बावजूद नहीं बढ़ा पा रहा है। बेशक वोटरों को नोटा जैसा प्रावधान दिया गया हो, लेकिन इसके अलावा राइट टू रीकॉल रूपी हथियार को मजबूती दी जाए तो जरूर लोकतंत्र जमीनी स्तर तक वोटरों की भारी भागीदारी के साथ ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा। राइट टू रीकॉल के अधिकार के इतिहास की बात करें तो प्राचीन एथेंसवासियों में यह प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक वर्ष की निश्चित तिथि पर वे निष्कासन प्रक्रिया का आयोजन करते थे। इस अवसर पर सभी नागरिकों को किसी पात्र में निष्कासन योग्य व्यक्ति का नाम लिखना होता था। जिस व्यक्ति के नाम के सबसे ज्यादा पत्र मिलते थे, उसे 10 महीने के लिए शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। यह प्रक्रिया बेशक उस समय भ्रष्ट व तानाशाह प्रवृत्ति पर लगाम जरूर लगाती रहेगी। आज भी ऐसी प्रक्रिया विश्व के 24 से ज्यादा देशों में चल रही है, जिसे राइट टू रिकॉल का नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल से पहले ही निष्कासित करने का अधिकार होता है। वर्ष 1995 से ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा विधानसभाओं ने मतदाताओं को ऐसा अधिकार दे रखा है। अमेरिका के जार्जिया, अलास्का, केन्सास जैसे राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है। जबकि वाशिंगटन में ऐसी प्रक्रिया तभी अपनाई जाती है अगर किसी प्रतिनिधि के बुरे आचरण या अपराध में शामिल होना प्रमाणित हो जाए। अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो राइट टू रिकॉल की शुरूआत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणापत्र में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में की थी। उस घोषणापत्र में लिखा था कि इस गणराज्य में मतदाओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा, यदि ऐसा चाहें, अन्यथा लोकतंत्र एक मजाक बन जाएगा। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1974 में संविधान (संशोधन) बिल जिसमें राइट टू रिकॉल के अंतर्गत विधायक व सांसदों को वापस बुलाने संबंधित बिल लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया, लेकिन पास नहीं हो पाया। वहीं वर्ष 2016 में भी उस समय के सांसद वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधत्व कानून (संशोधन) बिल के माध्यम से इस अधिकार को लागू करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। जबकि कई राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर राइट टू रिकॉल को रूपान्तरित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता में जागरूकता न होने कारण ये कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इस तरह के कानूनों को राजनीतिक पार्टियां भी जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती। जाने-माने राजनीतिक विचारक जेम्स मिल का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी डर के शासन करने का अधिकार दे दिया जाए, तो वे अधिकार का प्रयोग समाज के कल्याण से ज्यादा स्वयं के स्वार्थ के लिए करते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर शासन जिम्मेवार लोगों के हाथ में देना चाहिए। सामाजिक तौर पर कई प्रकार की चुनौतियाँ भी लोकतंत्र के सामने आती हैं चाहे चुनाव आयोग के खर्च बढ की बात हो या उस डर से राजनीति में रुचि कम लेने की बात हो। लेकिन विस्तृत नजरिए से देखें तो यह अधिकार लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों और जनता दोनों की जवाबदेही तय करता है।

राष्ट्रीय दैनिक प्रातःकिरण
नई दिल्ली, बुधवार, 18 फरवरी, 2026

प्रौद्योगिकी से सशक्त एमएसएमई : योगी सरकार ने यूपी को बनाया डिजिटल औद्योगिक शक्ति केंद्र

उद्यम सारथी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आसान हो रहा कारोबार

- एमएसएमई चैम्पियनशिप और तकनीकी उन्नयन से बढ़ी प्रतिस्पर्धा
- नई एमएसएमई नीति और प्लग एंड प्ले मॉडल से निवेश को गति

प्रात : किरण संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बहुस्तरीय पहल की गति तेज कर दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी उन्नयन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। योगी सरकार के इन कदमों से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त हुई है। डिजिटल अवसंरचना, नीतिगत सरलता और वित्तीय सहयोग के संयोजन ने प्रदेश को अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनाने की आधारभूमि को तैयार करने का काम किया है। एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में 3,822 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

ओडीओपी को मिला डिजिटल आयाम

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत मार्केटिंग डेवलपमेंट, टूलकिट वितरण और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके माध्यम से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के कारीगरों को तकनीक आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पारंपरिक उत्पादों को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने से स्थानीय वस्तुओं की पहुंच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बढ़ी है।

तकनीकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धा में बढ़त

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एमएसएमई चैम्पियनशिप इनीशिएटिव (चैंपियंस पोर्टल) के अंतर्गत चयनित इकाइयों को आधुनिक मशीनरी को अपनाने, गुणवत्ता सुधार और डिजिटल टूल्स के उपयोग के लिए तकनीकी सहायता दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादन लागत को घटाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और विकसित करना है। लाखों इकाइयों को डिजिटल उन्नयन और विपणन सहयोग का लाभ मिल रहा है।

उद्यम सारथी और आरएएमपी का सहारा

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 24 जनवरी, 2021 को लॉन्च की गई उद्यम सारथी ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन, योजनाओं की जानकारी और संचालन मार्गदर्शन एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। इससे उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों तक त्वरित पहुंच प्राप्त हो जाती है। प्रदेश में आरएएमपी (राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) योजना विश्व बैंक समर्थित एक केंद्रीय पहल है, इसके अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी समर्थन भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण को बल मिला है।

नीतिगत सरलता और त्वरित संचालन वर्ष 2022 से लागू

एमएसएमई नीति के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल से 72 घंटे में संचालन शुरू करने की सुविधा दी गई है। क्रेडिट प्रवाह में वृद्धि और पांच लाख रुपये तक बीमा कवरेज जैसी व्यवस्थाओं ने उद्यमियों को जोखिम प्रबंधन में सहूलियत प्रदान करने का काम किया है। इन उपायों से निवेश वातावरण मजबूत हुआ है।

बढ़ रहा है रोजगार और आर्थिक प्रभाव

प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों का असर रोजगार सृजन पर भी पड़ा है। एमएसएमई क्षेत्र पहले से ही करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार रहा है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इसमें नए अवसर जुड़े हैं। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सप्लाई चेन से जुड़ने के कारण ग्रामीण और अर्धशहरी इकाइयों को व्यापक बाजार हासिल हुआ है।

संक्षिप्त खबरें

3 मार्च को प्रदेश के सभी गन्ना तौल केंद्रों पर होगा प्रदर्शन

बागपत। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के किसान अधिकार आंदोलन के पदाधिकारियों ने बागपत जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए तीन मार्च को प्रदेश के सभी गन्ना तौल केंद्रों पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान अधिकार आंदोलन प्रदर्शन करेगा। किसान अधिकार आंदोलन के संयोजक नरेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के हितों के लिए वह पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। एक साल बाद 3 मार्च को प्रदेश के सभी तौल केंद्रों पर एक बार फिर प्रदर्शन होगा। आंदोलन के दूसरे चरण में गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए इस प्रदर्शन से अवगत कराया है। समस्याओं के निदान की मांग उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि सभी गन्ना तौल केंद्रों पर ज्ञापन लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था जिला स्तरीय अधिकारियों को करनी है। ज्ञापन न लेने की स्थिति में अगर कोई शांति भंग या अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

व्यापार में हो रहे नुकसान की वजह से व्यापारी ने फांसी लगाकर दी जान

फरुर्खाबाद। उत्तर प्रदेश में फरूर्खाबाद जिल के मऊदरवाजा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी ने मंगलवार को फांसी लगाकर जान दे दी। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि व्यापार में हो रहे नुकसान की वजह से उसने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अजब सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान बौरान निवासी अहसान मंसूरी (36) के रुप में हुई। उसके परिवार में पत्नी हुस्ना बेगम, दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। अहसान ने मंगलवार को गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ पर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी होने पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अजब सिंह, एसएसआई वीरेंद्र सिंह तथा हथियापुर चौकी इंचार्ज विनीत त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्र किए। थाना प्रभारी अजब सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में परिवार से पूछताछ में व्यापार में नुकसान के चलते मानसिक तनाव को आत्महत्या का कारण बताया है। पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी है।

कंप्यूटर सेंटर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

फरुर्खाबाद। उत्तर प्रदेश में फरुर्खाबाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को थाना कम्पिल क्षेत्र में बने एक कंप्यूटर सेंटर के अवैध निर्माण को बुलडोजर चला कर ध्वस्त किया गया है। यह सेंटर लव जिहाद का केंद्र बना हुआ था। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा ने प्रशासन को अवगत कराया था कि क्षेत्र में एक कंप्यूटर सेंटर है। यहां पर कंप्यूटर सीखने आने वाली एक लड़की को संचालक सलमान शिबू और उसके साथी अनस ने पांच माह पहले नशीला कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसकी अश्लील वीडियो बना ली और वायरल करने की धमकी देकर कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। घटना की जानकारी विश्व हिंदू परिषद को होने के बाद पीड़ित का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कंप्यूटर सेंटर की आड़ में लड़कियों को फंसाया जाता हैं।

शमसाबाद स्टेशन पर ट्रेन रोकने पहुंचे भाकियू कार्यकर्ता, समझाने पर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंप कर लौटे

प्रात : किरण संवाददाता

फरुखाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद में क्षेत्रीय जनता की लंबे समय से चली आ रही ट्रेन ठहराव की माँग को लेकर मंगलवार को शमसाबाद रेलवे स्टेशन पर भारी गहमागहमी रही। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के नेतृत्व में ट्रेन रोककर आंदोलन करने की तैयारी थी, लेकिन रेल अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के घंटों समझाने-बुझाने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन स्टेशन मास्टर को सौंपकर आंदोलन स्थगित किया। आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जीआरपी निरीक्षक रिपुदमन सिंह, आरपीएफ निरीक्षक फरुखाबाद ओम प्रकाश मीणा और नवाबगंज थाना प्रभारी राजीव कुमार भारी पुलिस बल के साथ स्टेशन पर डटे रहे। पूरा स्टेशन परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। भाकियू जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में पहुँचे कार्यकर्ताओं को अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी जायज माँगों को उच्चाधिकारियों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शमसाबाद स्टेशन एक बड़ी आबादी का केंद्र है, फिर भी यहाँ ट्रेन सं. 15041 सुबह 7:15 बजे फरुखाबाद-कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन सं. 15040: सुबह 10:30 बजे कानपुर की ओर जाने वाली एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है जबकि इस रूट की अन्य सभी जरूरत की ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। इन दो प्रमुख ट्रेनों के न रुकने से लखनऊ, कानपुर, कन्नौज और कासगंज जाने वाले छात्र, व्यापारी और मरीज परेशान हैं। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि इन ट्रेनों के ठहराव से न केवल यात्रियों को सुरक्षित व किफायती सफर मिलेगा, बल्कि रेलवे के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में यह ठहराव क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के साथ नवाबगंज नगर अध्यक्ष पप्पू राठौर, मोहम्मदाबाद ब्लॉक अध्यक्ष मानेंद्र, जिलाध्यक्ष राजीव राठौर, कुलदीप सक्सेना, ब्लॉक नवाबगंज अध्यक्ष अर्जित सिंह, सुरजीत कुमार सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे स्टेशन मास्टर अरुण कुमार ने बताया कि किसान नेताओं ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन उन्हें दिया है जिसे मूल रूप में जिलाधिकारी को भेज दिया जाएगा।

भाजपा कार्यालय पर पं. दीनदयाल कार्यशाला का आयोजन,कार्यकताओं को पार्टी की नीति रीति से कराया अवगत

प्रात : किरण संवाददाता

फरुर्खाबाद। उत्तर प्रदेश के फरुर्खाबाद जिले में मंगलवार को आवास विकास स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान की जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा की अध्यक्षता में शुरू प्रशिक्षण कार्यशाला को तीन सत्रों के माध्यम से संपन्न किया गया। जिला कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शास्त्री ने कहा कि भाजपा देश का एकमात्र ऐसा राजनैतिक दल है जो अपने कार्यकताओं को प्रशिक्षित करता है। संगठन में नए दायित्व का निर्वहन करने के लिए नवीन कार्यकर्ता संगठन की रीति-नीति को प्रशिक्षण के माध्यम से समझते हैं। भाजपा कार्यकर्ता अनुशासित होकर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं। भाजपा व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि असंख्य कार्यकताओं का एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सिर्फ कार्यकताओं की नींव पर आधारित है। जब नींव मजबूत होगी तभी संगठन मजबूत होगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा, नीति, सिद्धांत और कार्यशाली से भली भांति परिचित हो सके, इसके लिए सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि एक मजबूत संगठन का आधार प्रशिक्षित और जागरूक कार्यकर्ता होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्मक मानववाद के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता का वैचारिक एवं संगठनात्मक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। हमने संगठन में भी महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने का कार्य किया। द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी शिव महेश दुबे ने बताया जनपद के अधिकांश मंडल गठित हो चुके हैं और इन सभी मंडलों में मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है। 7 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य इन सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे, जिसमें मंडलों में कार्य करने वाले नवीन कार्यकताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण ही संगठन की ऊर्जा है। जिसके माध्यम से व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक दक्षता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। मंडलों के प्रशिक्षण के बाद जिले स्तर पर भी प्रशिक्षण होगा, जिसके लिए प्रदेश नेतृत्व जल्द ही स्वीकृति देगा। समापन सत्र में पूर्व जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह ने संगठनात्मक विषय पर चर्चा करते हुए कहा भाजपा आज शिखर पर है तो उसका सबसे बड़ा कारण भाजपा के असम के कार्यकताओं की अथक मेहनत और परिश्रम के कारण है भाजपा संगठन के माध्यम से नेतृत्व निर्माण करती है। एक ऐसा नेतृत्व जो राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के लिए आगे बढ़ता है।

कोडीन सिरप मामले में आरोपित प्रशांत उपाध्याय को तलाश रही एसआईटी

प्रात : किरण संवाददाता

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के मड़ौली निवासी प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू को कोडीनयुक्त सिरप तस्करी मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) टीम और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीमें हर एक स्थान पर तलाश रही हैं। आरोपित प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू के उत्तर प्रदेश के बाहर किसी राज्य में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। कोडीन सिरप मामले में बनी विशेष जांच दल (एसआईटी) टीम में शामिल एडीसीपी सरवनन टी. ने अपने बयान में मंगलवार को कहा कि कोडीनयुक्त सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल और उसके गुरु प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू की तेजी से तलाश की जा रही है। शुभम जायसवाल के गुरु के रूप पहचान बनाने वाले प्रशांत की राधिका इंटरप्राइजेज और राजेंद्र इंटरप्राइजेज पर कार्रवाई हुई है। बीते दिनों कोडीनयुक्त सिरप तस्करी में अमित यादव की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में भी प्रशांत उपाध्याय का नाम सामने आया है। अमित यादव ने यूपी एसटीएफ को बताया है कि प्रशांत ने ही फर्जी कंपनियों को बनाने और उसके माध्यम से फर्जी बिल बनाकर बड़ी धनराशि की हेराफेरी करने के तौर तरीके का ज्ञान दिया है। बताया जा रहा है कि कोडीन युक्त सिरप तस्करी मामले में फरार प्रशांत उपाध्याय ने कई राजनीतिक चेहरे, अधिवक्ताओं, दवा कारोबारियों की बड़ी धनराशि को तस्करी के धंधे में लगाने का ऑफर दिया था और बड़ी कमाई भी कराया है। इस वर्ष की शुरूआत में प्रशांत के मकान की तलाशी हुई थी और आवश्यक दस्तावेज को सीज किया गया था।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित नजरबंद, विधानसभा घेराव से पहले प्रशासन की कार्रवाइ

प्रात : किरण संवाददाता

बांदा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित को मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत लखनऊ में प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम से पहले ही प्रशासन ने नजरबंद कर लिया। यह कार्रवाई मंगलवार को सुबह की गई। राजेश दीक्षित ने बताया कि उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया, जिससे वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। दीक्षित ने कहा कि मनरेगा योजना ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे में उनकी आवाज को दबाना चिंता का विषय है। उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 17 फरवरी को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था, जिसके तहत बांदा से कई कार्यकर्ता लखनऊ जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों को उनका हक दिलाने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति कोई अपराध नहीं, बल्कि व्यवस्था को मजबूत करने का जरिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान की है। उन्होंने भरोसा जताया कि हाउस अरेस्ट जैसी कार्रवाई उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती और वे आगे भी शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीके से जनता की आवाज उठाते रहेंगे।

लखनऊ में ससुराल आए दामाद की पीट-पीटकर हत्या, प्रेम विवाह से ससुर था नाराज

प्रात : किरण संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काकोरी थाना क्षेत्र में ससुराल आए दामाद की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी शकील अहमद ने मंगलवार को बताया कि काकोरी ग्राम लालताखेड़ा के बाहर एक बाग में दो भाइयों को चाकू मार दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फारेंसिक टीम के साथ घटना की जांच कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक भाई की हालत गंभीर है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि मृतक की पहचान पीलीभीत जिले के निवासी ग्राम रामसागर (24) के रूप में हुई। पूछताछ में घायल युवक राहुल ने अपनी तहरीर में बताया कि रामसागर का दिसंबर 2024 में काकोरी के ग्राम लालताखेड़ा निवासी कामिनी से प्रेम विवाह हुआ था। कुछ समय से कामिनी ससुराल में रह रही थी। बाद में उसके परिजन उसे अपने घर लालताखेड़ा ले गए। आरोप है कि उसके परिजन उसकी दूसरी जगह शादी कराने की तैयारी कर रहे थे। रविवार को राहुल अपने भाई राम सागर के साथ उसकी पत्नी को विदा कराने लालताखेड़ा आया था। वहां पर कामिनी के पिता भीमा गौतम, उसके पुत्र सुमित, अमित और मौसी का लड़का पंकज से लालताखेड़ा गांव के बाहर बातचीत के दौरान विवाद हो गया। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर राम सागर और उसके भाई राहुल के साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान सुमित ने चाकू से प्रहार करके रामसागर को घायल कर दिया। राहुल के बीच-बचाव करने पर उसके साथ मारपीट की गई। शोर शराबा होने पर आरोपित मौके से फरार हो गये। इधर, घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने राम सागर को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

जिला पुस्तकालयों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा जीआईसी परिसर में बनेगी मॉडल लाइब्रेरी

प्रात : किरण संवाददाता

उरई। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पुस्तकालय समिति की बैठक की गई। इसमें जिले में सार्वजनिक पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और पाठकों में पठन संस्कृति के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि जीआईसी परिसर में स्थित जर्जर भवन का नियमानुसार ध्वस्तीकरण (डिमोलेशन) कराया जाए तथा उसी स्थान पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (उरफ) के माध्यम से एक आधुनिक मॉडल लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह मॉडल लाइब्रेरी जनपद के युवाओं के लिए ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनेगी। जिलाधिकारी ने राजकीय जिला पुस्तकालय की वार्षिक विकास योजना के निर्धारण एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राजकीय जिला पुस्तकालय को एक सक्रिय सामाजिक एवं बौद्धिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों, प्रतियोगी अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों को अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके। जिले के सभी अधिकृत सार्वजनिक पुस्तकालयों के निरीक्षण, आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही तथा पठन अभिरुचि बढ़ाने हेतु विशेष योजनाएं तैयार करने का भी निर्णय लिया गया।

सादाबाद सीएचसी में आयरन सुक्रोज सप्ताह का प्रारंभ

प्रात : किरण संवाददाता

हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर मंगलवार को आयरन सुक्रोज सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाव की जानकारी दी।सीएचसी सादाबाद में आयरन सुक्रोज सप्ताह का विधिवत शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल ने गर्भवती माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान खून की कमी (एनीमिया) एक गंभीर समस्या है, जिससे मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आयरन सुक्रोज के माध्यम से शरीर में तेजी से आयरन की कमी को पूरा किया जाता है, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलती है। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं से नियमित जांच कराने और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आयरन सुक्रोज लगवाने की अपील की। कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि आयरन सुक्रोज सप्ताह के अंतर्गत चिन्हित गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच की जाएगी तथा जिनमें खून की कमी पाई जाएगी, उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में आयरन सुक्रोज की डोज दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और प्रशिक्षित स्टाफ की निगरानी में की जाती है। स्वास्थ्य शिक्षकों ने उपस्थित महिलाओं को संतुलित आहार, हरी सब्जियों, दाल, गुड़, चना, मूंगफली और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही नियमित टीकाकरण और प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) कराने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के अंत में कई गर्भवती महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से आयरन सुक्रोज की पहली डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने आशा और एएनएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को इस अभियान से जोड़ें, ताकि क्षेत्र को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

विकास का सनातन मॉडल ही भारत को दोबारा बनाएगा विश्वगुरु : जलपुरुष

प्रात : किरण संवाददाता

गोरखपुर। भारत के जलपुरुष कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉ. राजेंद्र सिंह ने आज कहा कि सनातन विकास या विकास का सनातन मॉडल ही भारत को दोबारा विश्वगुरु बना सकता है। विकास के साथ प्रकृति का भी चिंतन भारत का सनातन विचार है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के लिए सुखद स्थिति है कि यहां के मुख्यमंत्री विकास के सनातन मॉडल को, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता के एकीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां विकास का विचार है तो साथ ही प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का प्रतिबद्ध चिंतन भी। डॉ. सिंह मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर (एमजीयूजी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ह्यविकास के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां : साझा प्रयास से सतत विकासह्व विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विकास के साथ पर्यावरण की चुनौतियों को समझते हुए इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन के लिए प्रदेश सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बधाई दी और पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन से विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने वाले विकास के सनातन मॉडल की चर्चा करते हुए कहा कि सनातन का मतलब सदैव, नित्य नूतन निर्माण। जिसका न आदि हो न अंत हो, वही सनातन है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारत का विकास सनातन विकास था। जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान के अस्तित्व में आने से हजारों वर्ष पहले वेदों, उपनिषदों में प्रकृति और पृथ्वी के प्रति मानव के कर्तव्य को समझाया गया है। पंचभूत की परिकल्पना के साथ ही प्रकृति के प्रति संस्कार और व्यवहार को भारत में सदियों पहले ही बता दिया गया था। इसी ज्ञान के कारण दुनिया भारत को विश्वगुरु मानती थी। आज दोबारा विश्वगुरु बनने के लिए भारत को अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा का अनुसरण करना होगा। जल संकट का विस्तार से उल्लेख करते हुए डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल संकट वैश्विक समस्या है लेकिन इसका स्थानीय हल निकाला जा सकता है। इसके लिए जल साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है। जल संकट से बचने के लिए वाटर डिस्चार्ज और वाटर रिचार्ज में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास पर एकतरफा ध्यान देने से हमने नदियों से उनकी निर्मलता और अविरलता को छीन लिया। पश्चिम की डैम डिजाइन को भारत की नदियों पर थोप देने से ही आज पारिस्थितिकी बदलने की समस्याएं दिख रही हैं। आज देश के 365 जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं। जल संकट से बचने, पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास की अवधारणा पर काम करने के लिए छोटे छोटे कार्य करने चाहिए। छोटे काम से बड़े काम की कल्पना में जोखिम नहीं है और सफलता शत प्रतिशत हो जाती है। छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने 50 साल में 23 नदियों को पुनर्जीवित किया है। डॉ. सिंह ने कहा कि सरिताएं बहती हैं तो सभ्यताएं भी जीवंत रहती हैं। डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रकृति व पर्यावरण के दृष्टिकोण से यूपी भगवान का लाडला बेटा है। यहां प्रचुर पानी और मिट्टी बेहतरीन है। यहां भविष्य में कोई जल संकट न हो, इसके लिए फसल पद्धति को वर्षा पद्धति से जोड़ने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी : मनोज कुमार सिंह संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पर्यवारण किसी एक व्यक्ति या संस्था से नहीं संभल सकता।

जौनपुर दीवानी न्यायालय और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी मिली

प्रात : किरण संवाददाता

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के दीवानी न्यायालय और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच की। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने मंगलवार को बताया कि धमकी भरा ईमेल जिला जज की आधिकारिक मेल पर सुबह 10:30 बजे प्राप्त हुआ। इसमे लिखा था कि दोपहर एक बजे से दो बजे के बीच सिविल कोर्ट के गेट नंबर-एक और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल में 5 से 6 मोबाइल नंबर भी अंकित थे और उन पर पैसे भेजने की मांग करते हुए अन्यथा विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। धमकी मिलते ही जिला जज सुशील कुमार शशि ने तत्काल प्रशासनिक आदेश जारी किए और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने एहतियातन न्यायालय परिसर खाली कराने का निर्देश दिए। सभी न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। इसके बाद अधिवक्ताओं के सहयोग से कचहरी परिसर को व्यवस्थित रूप से खाली कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने न्यायालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

तीन बाइकों पर आए बदमाशों ने युवकों को पीटकर लूटे आठ लाख रुपये

प्रात : किरण संवाददाता

कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर शताब्दी उद्यान मोड़ के पास सोमवार देर शाम तीन बाइकों पर सवार छह बदमाशों ने पीड़ित के साथ मारपीट करते हुए आठ लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी एकत्रित की, लेकिन पीड़ित ने तहरीर देने से इनकार कर दिया। नौबस्ता के यशोदा नगर निवासी मोहम्मद वासिद ने बताया कि वह श्याम नगर स्थित बैंक शाखा से नकदी निकालकर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में शताब्दी उद्यान मोड़ के पास वह कुछ देर के लिए रुका, तभी तीन बाइकों पर सवार छह युवक वहां पहुंचे। बदमाशों ने उसे घेर लिया और हेलमेट से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। इसके बाद तमंचे की बट से सिर पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल वासिद सड़क किनारे पड़ा रहा। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे तत्काल कांशीराम अस्पताल ले गई, जहां प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए श्याम नगर चौकी लाया गया, लेकिन वह घटना को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका और न ही लिखित शिकायत दी। सूचना पर डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित से बातचीत की, लेकिन घायल युवक ने किसी कारणवश पूरी जानकारी साझा नहीं की। चक्कर आने पर परिजन उसे इलाज के लिए अपने साथ ले गए। मौके पर मौजूद राहगीर सीमा ने भी बताया कि युवक के साथ लूट और मारपीट हुई हैं, लेकिन बदमाशों के हाथ में तमंचा होने की वजह से किसी ने भी पास जाकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की।

नवगठित नौगांवा सादात तहसील का डीएम ने किया निरीक्षण

प्रात: किरण संवाददाता

अमरोहा। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नव निर्मित नौगावां सादात तहसील परिसर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी। इस दौरान उन्होंने मुख्य भवन, हवालात, बैरक, गैराज, पम्प रूम, सीसी रोड, बाउंड्रीवाल, बोरिंग-ट्यूबवेल, बाह्य विकास कार्य और विद्युत संयोजन की प्रगति की जानकारी ली तथा विद्युत कनेक्शन का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आवासीय भवनों के निरीक्षण में डीएम ने टाइप-3 आवासों के कमरों का मापन कर गुणवत्ता की जांच की। भवनों के आसपास जलभराव की समस्या के समाधान के लिए एसडीएम और ईओ को संयुक्त टीम बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद डीएम ने नगर पंचायत कार्यालय में संचालित तहसील कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण भी किया। उन्होंने न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए तीन और पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को मार्च अंत तक निस्तारित करने के निर्देश दिए। संग्रह अनुभाग की समीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा डीएम ने खतौनियों में अंश निर्धारण की त्रुटियों को दूर करने के लिए तहसील स्तर पर बृहद शिविर आयोजित कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि त्रुटि सुधार तहसीलदार के प्रमाणीकरण के बाद ही किया जाए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सुनीता सिंह, तहसीलदार लकी सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जिले की सड़कों पर दस हजार गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी

प्रात: किरण संवाददाता

नोएडा। जिले की सड़कों पर दस हजार से अधिक गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही इन वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है। इसके बाद भी यह वाहन यदि सड़कों पर दौड़ते मिलेंगे तो सीज कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 10508 गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था।इसमें 10 साल पुराने 1542 डीजल वाहन और 15 वर्ष पुरानी 8966 पेट्रोल गाड़ियां शामिल हैं। समयसीमा पूरी होने के कारण यह प्रक्रिया की गई है। एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने कहा कि समयसीमा पूरी करने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र पहले निलंबित किया जाता है और इसके बाद समयानुसार निरस्त करने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया को करने से पहले वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाता है। वाहन मालिक इन वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां कबाड़ में बेच दी हैं वे परिवहन विभाग में पहुंचकर पंजीकरण निरस्त करवा लें। ऐसा न करने पर सबसे ज्यादा नुकसान व्यावसायिक वाहन मालिकों को होती है। व्यावसायिक वाहनों पर रोड टैक्स बनता रहता है। साथ ही जुमार्ना भी लगता है। नोटिस मिलने के बाद वाहन मालिक परिवहन विभाग पहुंचकर इस बात की जानकारी देते हैं कि वे गाड़ी को बेच चुके हैं। हालांकि इस स्थिति में भी जब तक का रोड टैक्स बन चुका होता है, उन्हें चुकाना पड़ता है। इस रोड टैक्स से लोगों को राहत नहीं मिलती है। जिले में गाड़ियों की संख्या 12 लाख से अधिक हुई परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वाहनों की संख्या 1220846 तक पहुंच गई है। इसमें निजी और व्यावसायिक दोनों तरह की गाड़ियां शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं। दोपहिया गाड़ियों की संख्या 710243 है। वहीं चार पहिया निजी वाहन 373695 हैं। दो केंद्रों में कटवा सकते हैं कबाड़ वाहन परिवहन विभाग के अनुसार जिले में दो अधिकृत वाहन कबाड़ केंद्र हैं। इनमें नोएडा में सेक्टर-80 स्थित मारुति सुजुकी टोसोसु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-1 स्थित महिंद्रा एसएसटीसी रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत केंद्र हैं।

संक्षिप्त खबरें

अधिवक्ता को हत्या की धमकी दी

गाजियाबाद। कविनगर थानाक्षेत्र में चैंबर में घुसकर अधिवक्ता को हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। आशिम अली ने पुलिस को बताया कि प्रताप विहार निवासी उसके समधी शफात खान, उसकी पत्नी सहाना और बेटा हयात खान ने कुछ समय पहले ठेकेदारी के काम का हवाला देकर उससे सोने के जेवरात लिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी जब जेवरात वापस नहीं किए गए तो उन्होंने तगादा किया। आशिम अली आरोप है कि 11 फरवरी को शफात खान, उसका बेटा और दो अन्य अज्ञात लोग जबरन उनके चैंबर में घुस आए। जेवरात लौटाने की बात करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कविनगर थाने में शिकायत दी। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

लोनी में युवक से मोबाइल छीना

लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र स्थित डीएलएफ गणेश अपार्टमेंट में रहने वाले प्रशांत सोमवार सुबह डीएलएफ अंडरपास के पास किसी कार्य से गए थे। उन्होंने बताया कि जब वह अंडरपास के पास खड़े थे, तो अचानक बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया। जब तक वह कुछ समझ पाते बदमाश बाइक से राम पार्क कॉलोनी की ओर फरार हो गए। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

नियम के उल्लंघन पर छह फार्म हाउस को नोटिस

ट्रांस हिंडन। इंदिरापुरम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के उल्लंघन पर नगर निगम ने छह फार्म हाउस को नोटिस दिया है। जांच के दौरान यहां कचरा निस्तारण संबंधी नियमों की अनदेखी पाई गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि नियमों के तहत बल्क में कचरा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर में ही गीले कचरे का निस्तारण करें। एक सप्ताह पहले की गई जांच में पाया गया कि गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं किया जा रहा था और ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण की व्यवस्था भी नहीं थी। निगम ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं हुआ तो फार्म हाउसों पर जुमार्ना लगाया जाएगा। साथ ही आवश्यक होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजना को लेकर जानकारी दी

गाजियाबाद। नवयुग मार्केट स्थित मुख्य प्रधान डाकघर में वरिष्ठ नागरिकों को डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में जानकारी दी गई। डाक घर में विभिन्न कार्यों से पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों को योजना में खाता खुलवाने को लेकर जागरूक भी किया गया। डाक घर की सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी अच्छी योजना है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक खाता खुलवा सकते हैं। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित भी है। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने इससे संबंधित कई जानकारी ली।

बहुउपयोगी भाषा की तरह हिंदी का उपयोग हो

नोएडा। सेक्टर-24 स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) कार्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई।इस दौरान मुख्य अतिथि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक डॉ. छबिल कुमार मेहरे ने कहा कि हिंदी को सिर्फ राजभाषा के रूप में नहीं, बल्कि बहुउपयोगी भाषा की तरह उपयोग होना चाहिए। यह संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रूप में भी दिखना चाहिए। इस मौके पर एफसीआई उत्तर क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक अजित कुमार सिन्हा, पुखराज मीना, संदीप कुमार पांडेय मौजूद रहे।

मंडल रेल प्रबंधक की अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन निर्माण कार्यो पर पैनी नजर

प्रात: किरण संवाददाता, नादिर त्यागी

मुरादाबाद। मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने मुरादाबाद-हरावाला रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडल के हरावाला तथा रूड़की स्टेशन का निरीक्षण कर पुनर्निर्माण कार्यों की गहनता से समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिये। 16 फरवरी को मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्री वास्तव ने मुरादाबाद से हरार्वाला रेल खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया तथा हरार्वाला स्टेशन एवं रूड़की स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किये जा रहे पुनर्निर्माण के कार्यों को सही रूप से परखा। मंडल रेल प्रबंधक ने हरार्वाला स्टेशन एवं रूड़की स्टेशन पर स्टेशन बिल्डिंग ,प्लेटफार्म ,सकुर्लेटिंग एरिया,एफओबी एवं दोनों स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विषय में सम्बंधित अधिकारियों से विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करते हुए किये जा रहे पुनर्निमाण कार्यों को परखा तथा सम्बंधित अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय से कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। रूड़की स्टेशन यार्ड में एलएचएस का निरीक्षण करते हुए सम्बंधित अधिकारियों से एलएचएस में पानी भरने की समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए निर्देशित किया। मंडल रेल प्रबंधक के निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा) एस पी तिवारी , सीपीएम (गति शक्ति) अनिल कुमार , वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (सामान्य) चेतन तनेजा , वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल अभियंता (प्रथम) पियूष पाठक , वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (समन्वय) अक्षय कुमार तथा मंडल के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

नोरैक्स फ्लेवर्स प्रा. लि. द्वारा नि:शुल्क मेंथा जड़ वितरण कार्यक्रम का आयोजन

प्रात: किरण संवाददाता

मंडी धनौरा/अमरोहा। नोरैक्स फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा स्थित अपने मुख्यालय में नि:शुल्क मेंथा जड़ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय किसानों को सहयोग प्रदान करना तथा क्षेत्र में सतत एवं टिकाऊ मेंथा खेती को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वैभव अग्रवाल ने मंडी धनौरा एवं हसनपुर क्षेत्र के किसानों को मेंथा की जड़ें वितरित कीं। इस कार्यक्रम में लगभग 100 किसानों ने भाग लिया, जिनमें राजेंद्र, मीना देवी, राम सिंह, सुरेश, मोहम्मद आरिफ, राजीव कंसल, रामफल सिंह एवं गणेश जैसे अग्रणी (चैंपियन) किसान भी शामिल रहे। बिहापुरी, मरगूबपुर, मिथनपुर, शकरथली, तरारा, चकोनी, बघरपुर, ब्रह्मावाद तथा आसपास के अन्य गांवों से आए किसानों को प्रत्येक किसान को 40 किलोग्राम मेंथा जड़ उपलब्ध कराई गई, जिससे आगामी खेती के मौसम के लिए पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर कंपनी अधिकारियों ने किसान कल्याण, सतत कृषि तथा गुणवत्ता युक्त इनपुट, तकनीकी मार्गदर्शन एवं दीर्घकालिक सहभागिता के माध्यम से मेंथा मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के प्रति नोरैक्स फ्लेवर्स की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शशांक अग्रवाल, क्यूएचएसई एवं सस्टेनेबिलिटी हेड श्री ललित, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर अनुराग नाथ, तथा फील्ड अधिकारी अरुण कुमार, दीपक शर्मा, अनिकेत एवं तेजपाल की उपस्थिति रही। जिन्होंने वितरण प्रक्रिया का सक्रिय रूप से संचालन किया और किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में शामिल किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए बुवाई से पूर्व समय पर सहयोग प्रदान करने के लिए नोरैक्स फ्लेवर्स प्रा. लि. का आभार व्यक्त किया। कंपनी ने भविष्य में भी इस प्रकार के किसान-केंद्रित एवं सततता आधारित कार्यक्रमों को जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया।

युवक ने फंदा लगाकर जान दी, युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

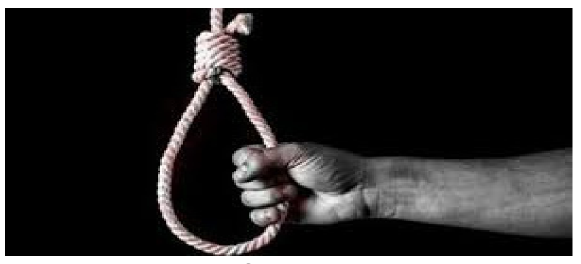

प्रात: किरण संवाददाता

गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एक युवती पर ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत पर युवती, उसके पिता और भाई के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नंदग्राम निवासी सचिन वर्मा ने पुलिस को बताया कि 16 फरवरी को उनके बेटे हर्ष वर्मा के मोबाइल पर नैंसी उर्फ संस्कृति का फोन आया था। आरोप है कि इस दौरान नैंसी ने हर्ष को ब्लैकमेल और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मानसिक दबाव के चलते हर्ष ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सचिन वर्मा का कहना है कि नैंसी के साथ-साथ उसके पिता और भाई की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उनके बेटे को लगातार फोन कर डराया-धमकाया जा रहा था, जिसकी वजह से वह तनाव में चला गया। उन्होंने नंदग्राम थाने में शिकायत देकर तीनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि शिकायत के आधार पर युवती, उसके पिता और भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने बोर्ड परीक्षा कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण नकलमुक्त परीक्षा कराने के निर्देश

प्रात: किरण संवाददाता

अमरोहा। जनपद में 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने अमरोहा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रवार रिपोर्टिंग प्रणाली तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर लगे कैमरों से लगातार और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। डीएम ने कंट्रोल रूम प्रभारी को परीक्षा कक्षों में कैमरों की स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करने तथा तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रश्नपत्र वितरण प्रक्रिया में लापरवाही न बरतने, परीक्षा केंद्रों पर बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी बृजपाल सिंह, शुभि गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मुनाफे का झांसा देकर दो लोगों से 35 लाख ठगे

प्रात: किरण संवाददाता

गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर दो लोगों से 35 लाख रुपये ठग लिए। दोनों ही मामलों में ठगों ने व्हाट्सऐप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेब पोर्टल के जरिए विश्वास जीतकर रकम ऐंठी। ठगी के संबंध में पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दी। अभय खंड-चार इंदिरापुरम के ग्रीन अनुकंपा अपार्टमेंट में रहने वाले सुरेंद्र राणा ने पुलिस को बताया कि वह एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़े थे, जिसे प्रेम प्रकाश वर्मा नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था। ग्रुप में शेयर बाजार से मुनाफा कमाने के दावे किए जाते थे और निवेश से जुड़ी जानकारी दी जाती थी। इस दौरान खुद को सर्विस मैनेजर बताने वाली ऐनली नाम की महिला ने अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करने को कहा। उन्होंने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच अलग-अलग तिथियों में 17.50 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद ठगों ने एक आईपीओ में अतिरिक्त शेयर आवंटित होने का दावा करते हुए 16 लाख रुपये और जमा कराने का दबाव बनाया। जब उन्होंने असमर्थता जताई तो आरोपियों ने उनके रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। कॉल करने पर मोबाइल नंबर बंद मिले। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज कराया। साइबर ठगी की दूसरी घटना क्रॉसिंग रिपब्लिक की जीएच-7 सोसाइटी में रहने वाले बाबू खान के साथ हुई। बाबू खान के अनुसार सितंबर 2025 में भावना शर्मा नाम की महिला ने व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क किया और खुद को ट्रेडिंग से मुनाफा कमाने वाली निवेशक बताया। इसके बाद उनसे कुल 17.16 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। पोर्टल पर करीब 42 लाख रुपये का लाभ दिखाया गया, लेकिन जब रकम निकालने की मांग की गई तो टैक्स के नाम पर 30 प्रतिशत राशि जमा कराने की शर्त रखी गई। इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह का कहना है कि दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

सतिंदर सरताज का दिल्ली मेगा कॉन्सर्ट बना ऐतिहासिक

सांस्कृतिक क्षण, 2 लाख से अधिक श्रोताओं ने रचा साझा संगीत अनुभव

प्रात: किरण संवाददाता

नई दिल्ली। शनिवार रात राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सतिंदर सरताज का भव्य स्टेडियम कॉन्सर्ट भारतीय लाइव संगीत जगत के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण बनकर उभरा। लगभग 50,000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से 1,50,000 से अधिक घरों तक पहुँचे इस आयोजन ने कुल मिलाकर 2,00,000 से अधिक श्रोताओं को एक साथ जोड़ते हुए एक अनूठा सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभव रचा। यह कार्यक्रम केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारत की बदलती सुनने की संस्कृति का सशक्त संकेत भी साबित हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे क्षण आए जब हजारों लोग पूर्ण शांति के साथ गीतों को सुनते दिखाई दिए। कविता, भावनाओं और गहरे चिंतन से भरे शब्दों ने पूरे वातावरण को एक विशेष गरिमा प्रदान की। हर प्रस्तुति के बाद गूँजती तालियाँ इस बात का प्रमाण थीं कि दर्शक केवल मनोरंजन के लिए उपस्थित नहीं थे, बल्कि हर पंक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। तेज ध्वनि और दृश्य चकाचौंध से भरे आधुनिक कॉन्सर्ट्स के दौर में यह शाम आत्मिक जुड़ाव, संवेदनशीलता और कलात्मक ईमानदारी का उत्सव बन गई। इस कॉन्सर्ट का पैमाना अपने आप में प्रभावशाली था, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व उससे भी अधिक व्यापक रहा। जहाँ बड़े स्टेडियम शो अक्सर भव्य मंच सज्जा और लोकप्रिय ट्रेंड्स पर आधारित होते हैं, वहीं इस कार्यक्रम का केंद्र स्वलिखित गीत, गहरी संगीत रचनाएँ और संतुलित, प्रभावशाली मंच उपस्थिति रही। दर्शकों ने इस प्रस्तुति को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि एक सामूहिक और आत्मीय अनुभव के रूप में महसूस किया। सांस्कृतिक विश्लेषकों के अनुसार यह आयोजन भारतीय श्रोताओं की बदलती पसंद को दशार्ता है। लगातार डिजिटल शोर और तेज गति वाले मनोरंजन के बीच दर्शक अब अर्थपूर्ण और गहराई से जुड़ी कला की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम ने यह साबित किया कि काव्यात्मक और विचारशील संगीत भी बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। स्टेडियम में मौजूद ऊर्जा उत्साहपूर्ण होने के साथ साथ केंद्रित और सजग थी, जहाँ लोग केवल जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि ध्यानपूर्वक सुन भी रहे थे। इस शाम की एक खास बात इसका राष्ट्रीय स्वरूप भी रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए अलग अलग आयु वर्ग के लोग एक ऐसे कलाकार के लिए एकत्र हुए जो पारंपरिक श्रेणियों से परे अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनकी मौलिकता, साहित्यिक दृष्टि और कलात्मक प्रतिबद्धता ने उनके प्रभाव को सीमित करने के बजाय और अधिक व्यापक बनाया है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से देशभर के दर्शकों की भागीदारी ने इस अनुभव को और विस्तृत आयाम दिया। प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे पल आए जब पूरा स्टेडियम शांत होकर शब्दों को आत्मसात करता दिखाई दिया। प्रेम, विनम्रता, आत्मचिंतन और जीवन के व्यापक प्रश्नों पर आधारित गीतों ने सामूहिक रूप से ऐसा वातावरण निर्मित किया जहाँ शांति भी प्रस्तुति का हिस्सा बन गई।

मीरपुर गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विरोध जारी

प्रात: किरण संवाददाता

लोनी। मीरपुर गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों और प्रशासनक के बीच का टकराव लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगभग दो माह से जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन ने उस समय जोर पकड़ लिया जब 3 दिन पूर्व प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग की घटना के बाद अब स्थानीय विधायक की कथित भूमिका पर भी विवाद गहराता नजर आ रहा हैं। गौरतलब हो कि गांव मीरपुर में लगभग 120 बीघा भूमि पर करीब 2000 टन कचरे के निस्तारण की क्षमता का प्लांट बनाया जा रहा है। ग्रामीणों को आशंका है कि प्लांट शुरू होने पर क्षेत्र में बदबू, प्रदूषण और बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। लोगो का कहना है कि गांव की उस भूमि पर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या अन्य जनहित की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए थीं। किसानों का कहना है कि वर्ष 2012 से इस परियोजना का विरोध हो रहा है। शुरूआती दौर में गांव वालों को डिग्री कॉलेज और आधुनिक सुविधाओं का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें लगता है विकास के नाम पर गांव को कूड़ा केंद्र बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर अधिकारियों के साथ बैठक में बातचीत के दौरान निर्माण रोकने का आश्वासन दिया गया था, मगर पीछले रास्ते से निर्माण कार्य जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीच कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जाना उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। आरोप है कि इसके विरोध सैकड़ो महिला पुरुष किसन शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठियां भांजकर उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि देर रात कागजी प्रक्रिया के बाद अधिकांश लोगों को रिहा कर दिया गया। लोनी विधायक पर लगाया गंभीर आरोप किसान प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पूर्व आधा दर्जन गांवों के किसान एकत्र होकर गनौली गांव स्थित विधायक के आवास पर पहुंचे थे, जहां कथित रूप से विधायक ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए यह आश्वासन दिया था कि,ह्वमैं तुम्हारे साथ हूं, आप मजबूती के साथ अपना धरना प्रदर्शन कीजिए ह्व अब इस मामले में किसानों का आरोप है कि इसके बाद धरना प्रदर्शन कर रहे महिला पुरुष ग्रामीण पर विधायक के कहने पर ही पुलिस ने उनपर लाठियां भांजी हैं। किसान प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि विधायक द्वारा महिला और पुरुष किसानों पर पूर्व नियोजित तरीके से बल प्रयोग कराया गया है। हालांकि इन आरोपों पर विधायक की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि इस मुद्दे पर जन प्रतिनिधि का पक्ष आता है, तो विवाद की दिशा बदलने की बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। आंदोलन को मिला राजनीतिक बल किसानों पर हुए लाठी चार्ज की घटना के बाद बसपा नेता सचिन शर्मा और मनोज जाटव अपने समर्थकों संग धरना स्थल पर पहुंचे। नेताओं ने किसानों के बीच पहुंचकर आंदोलन को खुला समर्थन दिया और पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की।उन्होंने इसे किसानों की आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए कहा कि निहत्थे किसान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक होगा। अबतक के तमाम घटनाक्रम पर गौर करें तो यह मामला अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। एक ओर प्रशासन इसे शहर की जरूरत बता रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीण अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खतरे का हवाला देते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब इस विवाद में जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और विधायक पर लगे आरोपों ने मामले को ओर गहरा दिया है। हर किसी की नजरें प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा किसानों के अगली रणनीति पर टिकी हैं।

दो सौ श्रमिकों की हुई स्वास्थ्य जांच

ग्रेटर नोएडा। निर्माण गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर जांच शिविर का आयोजन किया गया। जेटा-1 स्थित एसकेए डेस्टिनी वन परिसर में एसकेए ग्रुप द्वारा आयोजित इस शिविर में करीब 200 कर्मचारियों और साइट पर काम करने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिसमें सामान्य स्वास्थ्य जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, बीएमआई माप और बेसिक पैथोलॉजी जांच की गई। डॉक्टर प्रकृति झा और अन्य डॉक्टरों ने श्रमिकों को नियमित जांच कराने और सेहत का ध्यान रखने की सलाह भी दी। कंपनी की ओर से बताया गया कि निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर रहना जरूरी है।

ग्रेनो वेस्ट में मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन

प्रात: किरण संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में मेट्रो सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाने से स्थानीय लोग परेशान हैं। इस समस्या के समाधान के लिए नेफोवा के नेतृत्व में निवासियों ने 15 मार्च 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि एनसीआर क्षेत्र में होने के बावजूद उनकी आवाज केंद्र सरकार तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रही है। इसी कारण उन्हें अपनी मांगें उठाने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्र सरकार के अधिकारियों को इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। यहां लाखों लोग प्रतिदिन घंटों जाम में फंसकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिससे समय, ईंधन और स्वास्थ्य पर भारी बोझ पड़ रहा है। लोगों का आरोप लगाया है कि जहां कम आबादी वाले क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है, वहीं,ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में परियोजना लंबित पड़ी हुई है। नेफोवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो की फाइल को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के पास भेज दिया था, लेकिन तब से अब तक यह फाइल लंबित है। लगभग तीन बार केंद्र सरकार के द्वारा यहां के डीपीआर को निरस्त करके रूट को बदला जा चुका है एवं अभी भी मेट्रो की फाइल पीएमओ ने रोका हुआ है। इस देरी के कारण क्षेत्र के निवासी भारी असुविधा झेल रहे हैं। हम 15 मार्च को हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।वही, एक अन्य निवासी दीपांकर कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि इस प्रदर्शन के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए मेट्रो विस्तार को शीघ्र मंजूरी मिलेगी और परियोजना का रास्ता साफ होगा।

कार से स्कूटी सवार को टक्कर मारी, काफी दूर तक घसीटा

गाजियाबाद। लालकुआं स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। स्कूटर सवार कई मीटर तक कार के साथ घिसटता चला गया। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल के बेटे की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लालकुआं की पंच विहार कॉलोनी में रहने वाले कार्तिक गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उनके पिता काशीनाथ शाह होली चाइल्ड स्कूल के पास चाऊमीन की ठेली लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। 14 फरवरी की रात वह काम निपटाकर स्कूटर से घर लौट रहे थे। जब वह सिल्वर सिटी मॉल के पास से पंच विहार की ओर मुड़ रहे थे तो पीछे से आ रही कार ने तेज गति और लापरवाही से उनके स्कूटर में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चालक उनके पिता को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उनके पिता को कार से अलग कराया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उनके पिता की हालत नाजुक बताई है।

‘लैला मजनू’ की तर्ज पर ‘हीर रांझा’ बनाएंगी एकता कपूर

14 फरवरी ‘वैलेंटाइन डे’ पर फिल्म निर्माताओं ने ‘हीर रांझा’ की खास झलक शेयर की है। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इम्तियाज अली के छोटे भाई साजिद अली करेंगे। एकता कपूर ने आज अपनी नई फिल्म ‘हीर रांझा’ की एक खास झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने फिल्म ‘हीर रांझा’ को लेकर कैप्शन में लिखा, ‘कुछ प्रेम कहानियां कभी नहीं मरतीं।’ आगे एकता ने लिखा, ‘ ’लैला मजनू’ से लेकर ‘हीर रांझा’ तक की प्रेम कहानियों की विरासत जारी है।’ इस फिल्म के प्रस्तुतकर्ता इम्तियाज अली है। फिल्म का निर्देशन इम्तियाज के छोटे भाई साजिद अली करेंगे। फिल्म का निर्माण शोभा कपूर, एकता कपूर और प्रीति अली बालाजी मोशन पिक्चर्स और पी फिल्म के तहत करेंगे। फिल्म की इस झलक को देखकर यूजर्स काफी उत्साहित हैं और मांग कर रहे हैं कि लैला मजनू की तरह इस फिल्म में भी तृप्ति डिमारी और अविनाश तिवारी को ही कास्ट किया जाए। एक यूजर ने लिखा, ‘तृप्ति डिमरी और अविनाश प्लीज’, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मैं इस फिल्म का इंतजार कर रहा हूं’, एक और यूजर ने लिखा, ‘लैला मजनू के बाद एक और मास्टरपीस।’

कौन हैं साजिद अली

साजिद अली एक भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखक हैं। वह मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम करते हैं। साजिद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इम्तियाज अली के छोटे भाई हैं। साजिद ने 2018 की रोमांटिक फिल्म ‘लैला मजनू’ से निर्देशन में डेब्यू किया। इसके अलावा उन्होंने ‘कॉकटेल’ जैसी फिल्मों में सह-लेखक के रूप में भी काम किया है।

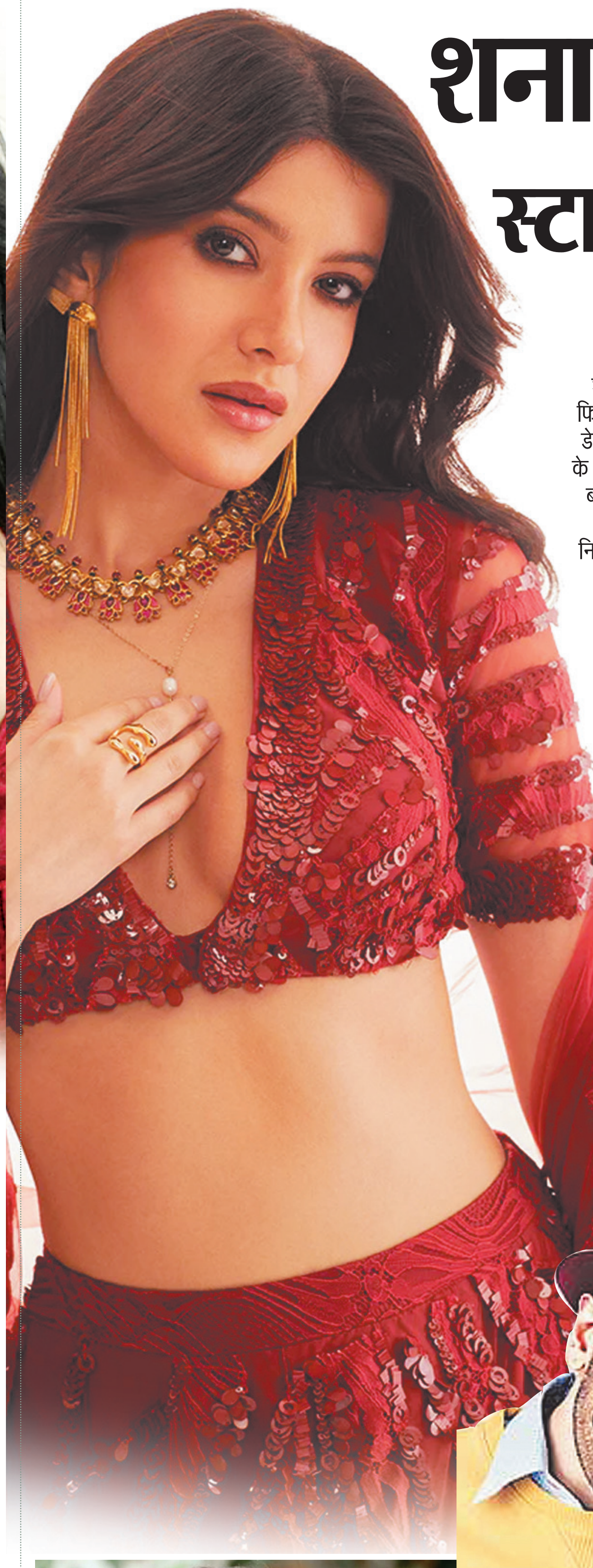

शनाया कपूर ने बताए स्टार किड होने के फायदे

अभिनेता संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘तू या मैं’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। शनाया ने पिछले साल विक्रांत मैसी के साथ फिल्म ‘आंखों की गुस्ताखियां’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब शनाया ने स्टारकिड होने के फायदों के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी होने के उन्हें क्या फायदे हैं? निर्देशक-कोरियोग्राफर अपने हालिया वीडियो व्लॉग में शनाया कपूर और महीप कपूर के घर पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ शनाया के को-स्टार आदर्श गौरव भी नजर आए। इस दौरान फराह ने महीप और शनाया से बातचीत शुरू की और उनसे स्टार पेरेंट्स होने के फायदे या नुकसान के बारे में सवाल किया। इस पर शनाया ने कहा कि स्टार माता-पिता का होना अच्छी बात है क्योंकि वे फिल्म के प्रचार में मेरी मदद करते हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए शनाया ने बताया कि एक बार वह अपनी मां के साथ थिएटर में ‘मार्टी सुप्रीम’ देखने गई थीं। तभी कुछ लड़कियों ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए महीप के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। मैं वहां अपने फोन के साथ खड़ी थी और मैंने देखा कि कुछ लड़कियां हमारी तरफ आ रही हैं। मैंने सोचा, ‘अरे, ट्रेलर अभी-अभी रिलीज हुआ है और शायद वो मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहती हैं। मैं उठने ही वाली थी कि तभी ये लड़कियां मेरी मां के पास गईं और बोलीं, ‘हम आपकी बहुत बड़ी फैन हैं।’ फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप हमारी और अपनी मां की एक फोटो खींच सकती हैं? शनाया ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत पिछले साल आई फिल्म ‘आंखों की गुस्ताखियां’ से की थी। संतोष सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ विक्रांत मैसी नजर आए हैं। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। अब शनाया अपनी दूसरी फिल्म ‘तू या मैं’ से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। बेजॉय नाम्बियार द्वारा निर्देशित ‘तू या मैं’ की कहानी दो सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर के बारे में हैं। जो एक कोलैबरेशन के लिए साथ आते हैं, लेकिन फिर वो किस तरह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिल्म में शनाया कपूर के साथ आदर्श गौरव मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हो गई है।

300 करोड़ है रणवीर सिंह की ‘प्रलय’ का बजट

रणवीर सिंह ने अपनी हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह जासूसी थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म ‘प्रलय’ को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह एक जॉम्बी ड्रामा फिल्म है, जो उनके करियर की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही है, जिसका बजट करोड़ों में है।

क्या है प्रलय का बजट?

एक खबर के अनुसार, इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। यह रणवीर सिंह की अब तक की सबसे महंगी सोलो फिल्म हो सकती है। इसमें स्क्रिप्ट से लेकर वीएफएक्स (विजुअल इफेक्ट्स) तक हर चीज में शामिल है। उन्होंने बैकएंड प्रॉफिट-शेयरिंग डील भी की है।

अभिनेत्री सम्युक्ता का सबसे दमदार रूपः स्वयंभू के टीज़र में वॉरियर अवतार ने मचाया तहलका

अपनी पिछली फिल्मों की कामयाबी पर सवार सम्युक्ता ने स्वयंभू के टीज़र में ऐसा पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ा है कि नज़र हटाना मुश्किल हो जाए। इस बार वो नज़र आती हैं एक भयंकर योद्धा के रूप में, जो अफरातफरी को चीरते हुए पूरे कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ती है। गूंथी हुई चोटी, युद्ध के लिए तैयार तेवर, और रफ-टफ योद्धा वेशभूषा में सम्युक्ता कच्ची ताकत और अटूट इरादे का प्रदर्शन करती दिखती हैं। उनका किरदार शब्दों से नहीं, एक्शन से बोलता है और हर फ्रेम ये इशारा देता है कि वो अपने करियर के सबसे साहसी क्रिएटिव फेज़ में कदम रख चुकी हैं। ये भूमिका इसलिए भी खास लगती है क्योंकि इससे पहले उनका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। भीमला नायक में उन्होंने अपनी दमदार मौजूदगी से सबको प्रभावित किया, बिम्बिसार में पौराणिक दुनिया को एक्सप्लोर किया, विरुपाक्ष में थ्रिल का तड़का लगाया और सर में जमीन से जुड़ा अभिनय पेश किया। अब स्वयंभू में ऐसा लगता है जैसे इन सभी अनुभवों का संगम दिख रहा हो और सम्युक्ता खुद का और भी ताकतवर संस्करण बनकर सामने आई हों। टीज़र में वो एक निडर और बेखौफ योद्धा के रूप में दिखती हैं, जो जेंडर की तय सीमाओं को चुनौती देते हुए तीखे एक्शन सीक्वेंस में कमान अपने हाथ में लेती है। कभी धनुष-बाण साधती हुई, तो कभी तलवार लहराती हुई — हर सीन इस बात का सबूत है कि इस किरदार के लिए उन्होंने जबरदस्त शारीरिक ट्रेनिंग और तैयारी की है। सम्युक्ता कहती हैं, स्वयंभू मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जो मुझे मेरे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर ले जाएं। इस भूमिका ने मुझे शारीरिक और मानसिक, दोनों स्तर पर ऐसी चुनौती दी जैसा पहले कभी महसूस नहीं किया। एक गांव की महिला की आत्मा और शक्ति को समझने से लेकर घुड़सवारी और तीरंदाजी की कड़ी ट्रेनिंग तक, ये सफर बेहद गहन और परिवर्तनकारी रहा। इस किरदार में वो सब कुछ है जिसका एक अभिनेता सपना देखता है — ताकत, संवेदनशीलता और एक मजबूत आवाज़। इस उग्र योद्धा रूप में ढलना मेरे करियर के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक रहा है। स्वयंभू के अलावा भी सम्युक्ता के पास कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं, जहां वो अपनी बढ़ती रेंज दिखाती नजर आएंगी। जल्द ही वो ब्लैक गोल्ड में एक सशक्त पुलिस अधिकारी के रूप में फिल्म को लीड करेंगी और साथ ही पुरी जगन्नाध की स्लम डॉग में विजय सेतुपति और तब्बू के साथ स्क्रीन साझा करती दिखाई देंगी।

अनिल कपूर को मिला था असल नायक बनने का मौका, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पद ठुकराया?

अनिल कपूर की फिल्म ‘नायक’ साल 2001 में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी को दर्शकों ने काफी सराहा था। फिल्म में अनिल कपूर एक पत्रकार की भूमिका में थे, जिसे एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है। वह एक दिन में ही राजनीति की दुनिया को बदलकर रख देता है। असल जिंदगी में भी अनिल कपूर को एक खास पद पर काम करने का मौका मिला था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

यूएन का ऑफर क्यों ठुकराया?

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस से की गई बातचीत में अनिल कपूर कहते हैं, ‘जब मुझे डैनी बॉयल की फिल्म ‘स्लमडॉग मिलियनेयर(2008)’ के कारण इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी मिली तो यूएन की तरफ से एक सिंबॉलिक पोजिशन पर काम करने का ऑफर आया। लेकिन मैं इसे एक फोटो खींचवाने वाली जॉब की तरह नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लोग चार फोटो लें और मैं कुछ काम ना करूं। वैसे भी मेरी इतनी सारी प्रायोरिटीज हैं कि मुझे नहीं लगता कि यूएन वाला काम कर पाता। मैं बिना दिखावा किए सिर्फ वही काम करता हूं, जो मैं कर सकता हूं। मुझसे कहीं बेहतर लोग हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में होने के लायक हैं।’

ओटीटी पर आएगी अनिल की ‘सूबेदार’

हाल ही में अनिल कपूर की फिल्म ‘सूबेदार’ का टीजर रिलीज हुआ। यह 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म की कास्ट और कहानी के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल फैंस अनिल कपूर को नए अवतार में देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस फिल्म में वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे।

अनिल कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स?

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर के खाते में कई फिल्में शामिल हैं। ‘सूबेदार’ के अलावा उनकी आगामी फिल्मों और सीरीज में ‘अल्फा’, ‘किंग’ और ‘फैमिली बिजनेस’ शामिल हैं। इसके अलावा उनके ‘नायक 2’ बनाने की भी चर्चाएं हैं। हाल ही में अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के बेबी शॉवर में नजर आए थे।

शादी मेरी योजना का हिस्सा, पार्टनर को लेकर कही ये बात

मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी शादी की खबरों को लेकर भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। पिछले कुछ वक्त से उनका नाम धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि, शादी की खबरों पर मृणाल इनकार कर चुकी हैं। जबकि धनुष के साथ रिश्ते पर भी दोनों स्टार्स में से किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है। अब मृणाल का कहना है कि वो शादी की योजना बना चुकी हैं।

सही समय और सही जीवनसाथी का इंतजार

पीटीआई के साथ बातचीत में मृणाल ने कहा है कि शादी निश्चित रूप से उनकी योजनाओं का हिस्सा है, लेकिन तभी जब समय और जीवनसाथी सही लगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने जीवन में सही साथी के आने का इंतजार कर रही हैं। उनकी यह टिप्पणी अभिनेता धनुष के साथ उनके रोमांटिक संबंधों की अफवाहों को खारिज करने के कुछ ही समय बाद आई है। अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए मृणाल ने कहा कि वह एक दिन शादी करना चाहती हैं। जब सही दिन और सही जीवनसाथी मिलेगा, तो मैं खुद सोशल मीडिया पर इस खबर की घोषणा करूंगी।

शादी को लेकर बदले लोगों के विचार

अभिनेत्री का मानना है कि समय के साथ लोगों का शादी को लेकर विचार भी काफी बदल गया है। एक्ट्रेस ने कहा कि आज लोग सामाजिक अपेक्षाओं या दबाव के बजाय सच्चे जुड़ाव के कारण शादी का चुनाव करते हैं। पहले शादी के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते थे, लेकिन अब यह सही व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा के बारे में है।

पिछले साल से चल रहीं धनुष मृणाल के अफेयर की खबरें

पिछले कुछ वक्त से मृणाल और धनुष के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले दिनों तो ये भी खबरें आई थीं कि मृणाल और धनुष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर ही शादी भी कर सकते हैं। हालांकि, इन खबरों को मृणाल ने यह कहते हुए खारिज किया था, ‘शादी की तारीख तक आ गई और मुझे इनवाइट भी नहीं किया गया।’ हालांकि, मृणाल और धनुष के रिश्ते की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन पिछले साल उनकी फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की रैप पार्टी में शामिल होने के बाद अटकलें शुरू हो गईं। बाद में ‘सन ऑफ सरदार 2’ के प्रीमियर पर उनके धनुष को गले लगाने के वीडियो ने अफवाहों को और हवा दी।

‘दो दीवाने सहर में’ में नजर आएंगी मृणाल

वर्कफ्रंट की बात करें तो मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस रोमांटिक लव स्टोरी में वो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। रवि उदयवार द्वारा निर्देशित और संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में आदिवी शेष के साथ रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर ‘डकैत’ भी है। यह फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने है।

आईआईएफएल फाईनेंस ने 9 प्रतिशत सालाना रिटर्न के साथ 2000 करोड़ के बॉन्ड जारी किए

मुंबई, एजेंसी। देश की प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाईनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) में से एक, आईआईएफएल फाईनेंस लिमिटेड ने रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) के पब्लिक इश्यू जारी किए हैं, जो मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 से मिलना शुरू होंगे। इनका इश्यू साईज़ 500 करोड़ रुपये है, और 1,500 करोड़ रुपये तक का ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने के लिए ग्रीन-शू विकल्प है। इस प्रकार कुल इश्यू साईज़ 2,000 करोड़ रुपये का होगा। इस फंड का उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि करना और पूंजी बढ़ाना है।

श्री निर्मल जैन, फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, आईआईएफएल फाईनेंस ने कहा कि, ''आईआईएफएल फाईनेंस भारत के प्रमुख एनबीएफसी में से एक है। यह पूरे देश में मजबूत स्थिति रखता है। इसका डाईवर्सिफाईड रिटेल पोर्टफोलियो 4.6 मिलियन से अधिक वंचित ग्राहकों को क्रेडिट प्रदान करता है। इस प्रस्तावित फंड के माध्यम से हम क्रेडिट की उपलब्धता और अधिक बढ़ाएंगे तथा अपने फंडिंग स्रोतों का विस्तार करेंगे। पिछले कुछ सालों में आईआईएफएल फाईनेंस ने बॉन्ड के माध्यम से फंड एकत्रित करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है तथा मूल राशि एवं ब्याज का समय पर भुगतान किया है।''

इस एनसीडी द्वारा 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक का प्रभावी रिटर्न मिलेगा और यह 24 महीनों, 36 महीनों, और 60 महीनों की अवधियों के लिए उपलब्ध होगा। ब्याज का पे-आउट मासिक, वार्षिक या मैच्योरिटी के बाद लिया जा सकता है।

इस इश्यू को क्राईसिल रेटिंग्स ने क्राईसिल एए/स्टेबल रेटिंग दी है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स द्वारा इसे बीडब्लूआर एए+ (स्टेबल) रेटिंग दी गई है, जिससे प्रदर्शित होता है कि इनमें बहुत कम क्रेडिट रिस्क है और ये फाईनेंशियल दायित्वों को समय पर पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं।

31 दिसंबर, 2025 को आईआईएफएल फाईनेंस के पास 98,336 करोड़ रुपये के कंसोलिडेटेड लोन एस्सेट्स अंडर मैनेजमेंट (ए.यू.एम) थे। कंपनी लगातार मजबूत एस्सेट क्वालिटी बनाकर रखती है। 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी की कंसोलिडेटेड लोन बुक के प्रतिशत हिस्से में कंपनी के पास 1.60 प्रतिशत ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एस्सेट (एनपीए) और 0.75 प्रतिशत नेट एनपीए हैं।

लोन बुक को पर्याप्त कोलेटरल द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था

इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी की 83.61 प्रतिशत कंसोलिडेटेड लोन बुक को पर्याप्त कोलेटरल द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था, ताकि जोखिम और कम हो जाए। वित्तवर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में आईआईएफएल फाईनेंस ने 501.3 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (पीएटी) दर्ज किया, जो सालाना 514 प्रतिशत अधिक है। वहीं वित्तवर्ष 2026 के नौ महीनों के लिए पीएटी 1,193.5 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना 265 प्रतिशत अधिक है। विभिन्न बैंकों और फाईनेंशियल संस्थानों के साथ कंपनी के मजबूत संबंध हैं, जिससे फंडिंग की रणनीति में मदद मिलती है। 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी के पास कंसोलिडेटेड आधार पर 4,761 शाखाओं का नेटवर्क था, जो देश के कोने-कोने में फैला था।

डिफेंस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिला 5000 करोड़ रुपये का काम

नई दिल्ली, एजेंसी। डिफेंस कंपनी कोचिन शिपयार्ड (को 5000 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह खबर शेयर बाजार के बंद होने के बाद सामने आई। कंपनी को यह काम डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है। आज सोमवार को डिफेंस कंपनी कोचिन शिपयार्ड के शेयर बीएसई में 0.39 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1468.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है। क्या है वर्क ऑर्डर डीटेल्स स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय ने पांच नेक्सट जनरेशन सर्वे वेसल्स के लिए बोली मंगाई थी। कोचिन

शिपयार्ड इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर उभरी है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोचिन शिपयार्ड को शिपबिल्डिंग्स के साथ-साथ मेंटनेंस का भी काम देखना है। कोचिन शिपयार्ड ने तीसरी तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया है डिफेंस कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार दिसंबर तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 144.60 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 18.30 प्रतिशत कम है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 177 करोड़ रुपये रहा था। डिफेंस कंपनी का रेवन्यू 1350.40 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 17.70 प्रतिशत अधिक है। कोचिन शिपयार्ड की तरफ से दी जानकारी के अनुसार दिसंबर तिमाही में ईबीआईटीडीए 21.50 प्रतिशत की गिरावट के बाद 186.60 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में यह 237.60 करोड़ रुपये रहा था। बीते तीन महीने के दौरान कोचिन शिपयार्ड के शेयरों की कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट आई है।

चुनौतियों के बीच भारत को निर्यात में बढ़त, जनवरी में 0.61 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के निर्यात में जनवरी महीने में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि जनवरी में देश का निर्यात 0.61 प्रतिशत बढ़कर 36.56 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह बढ़ोतरी वैश्विक चुनौतियों के बीच सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक कुल निर्यात 2.22 प्रतिशत बढ़कर 366.63 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि लगातार बढ़ता निर्यात देश की

अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति बेहतर हो रही है। भारत की एक टीम जाएगी अमेरिका इसके साथ ही वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत की एक टीम अगले हफ्ते अमेरिका जाएगी ताकि मार्च में होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते के लिए कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा सके। यह यात्रा 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस महीने भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप दिया था। अब इस ढांचे को कानूनी समझौते में बदलना बाकी है, जिसे दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित किया जाएगा। वाणिज्य सचिव ने यह भी बताया कि दोनों देश इस कानूनी समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हैं और इसके लिए आभासी बातचीत भी हो रही है। अगले हफ्ते भारत के मुख्य वार्ता प्रतिनिधि दर्पण जैन अमेरिका का दौरा करेंगे।

टैरिफ का दिखा असर, अमेरिका को भारत के निर्यात में 22 प्रतिशत गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का इम्पैक्ट दिखाई दिया है। जनवरी में अमेरिका को भारत के वस्तु निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, कुल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह डायवर्सिफिकेशन है। जनवरी में भारत का वस्तु निर्यात 0.61 प्रतिशत बढ़कर 36.56 अरब डॉलर हो गया। वहीं, आयात 19.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 71.24 अरब डॉलर पर पहुंचा। इससे देश के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई। यह बढ़कर 34.68 अरब डॉलर हो गया। यह बढ़ोतरी वस्तुओं और सेवाओं दोनों में देखी गई। अमेरिका की ओर से लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बीच जनवरी में अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात 21.77 फीसदी घटकर 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। चालू वित्तीय वर्ष में कुल निर्यात 860 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है। अप्रैल से जनवरी की अवधि में निर्यात 2.22 प्रतिशत

चीन ने दिया सहारा

बढ़कर 366.63 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। 7 फरवरी से अमेरिका ने 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ हटा दिए हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने हैं। इससे भारत के निर्यात क्षेत्रीय साथियों के बीच प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ गए हैं।

पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में भी निर्यात में गिरावट आई थी। हालांकि नवंबर में 22.61 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई थी। इसी अवधि में अमेरिका से आयात 23.71 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया। चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जनवरी के दौरान अमेरिका को भारत का निर्यात 5.85 प्रतिशत बढ़कर 72.46 अरब डॉलर हो गया। वहीं, आयात 13.87 प्रतिशत बढ़कर 43.92 अरब डॉलर पहुंच गया।

चीन को एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी

चीन को निर्यात जनवरी में 55.65 प्रतिशत बढ़कर 1.63 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन से आयात 16.67 प्रतिशत बढ़कर 12.23 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल-जनवरी अवधि में चीन को निर्यात 38.37 प्रतिशत बढ़कर 15.88 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 13.82 प्रतिशत बढ़कर 108.18 अरब डॉलर हो गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, इटली, हांगकांग, स्पेन, बेल्जियम, मलेशिया और वियतनाम सहित कई देशों को निर्यात में सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके उलट ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्राजील को शिपमेंट में गिरावट आई।

आंकड़ों से क्या मलिता है संकेत

आयात पक्ष पर रूस, इराक, कोरिया, जर्मनी, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इनफ्लो में गिरावट आई। वहीं, यूएई, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान और इंडोनेशिया से आयात बढ़ा। भारत मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से सोना आयात करता है। इस देश से खरीद जनवरी में 836.85 प्रतिशत बढ़कर 3.95 अरब डॉलर हो गई। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, जनवरी 2026 के ताजा व्यापार आंकड़े भारत के निर्यात प्रदर्शन पर अमेरिकी टैरिफ के असर को दिखाते हैं। साथ ही अन्य बाजारों में डायवर्सिफिकेशन के शुरुआती संकेत भी देते हैं।

अमेरिका ने कहा- भारत ने रूसी तेल न खरीदने का दिया भरोसा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिनों पहले ही नई दिल्ली ने दोहराया था कि ऊर्जा खरीद में राष्ट्रीय हित ही मार्गदर्शक कारक होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी की शुरुआत में भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा करते हुए कहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने पर सहमत हो गया है। तब से अमेरिका ने यह दावा कई बार दोहराया है। म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस में बोलते हुए रुबियो ने कहा, भारत के साथ हमारी बातचीत में, हमें अतिरिक्त रूसी तेल न खरीदने की उनकी प्रतिबद्धता मिली है। वह रूस-यूक्रेन युद्ध और मास्को पर लगाए गए प्रतिबंधों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी सम्मेलन में इस सवाल के जवाब में कि क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को प्रभावित करेगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले कहा था कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, यह हमारे इतिहास और हमारे विकास का एक हिस्सा है। यह बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और यह पूरे राजनीतिक दलों में भी फैला हुआ है।

विदेश मंत्री ने वैश्विक तेल बाजार को जटिल और गतिशील बताया। जयशंकर ने कहा, भारत में तेल कंपनियां, यूरोप की तरह और संभवतः दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, उपलब्धता, लागत और जोखिमों को देखती हैं और अपने सर्वोत्तम हित में निर्णय लेती हैं। गौरतलब है कि ट्रेड डील की घोषणा के बाद, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को वापस ले लिया था। ये टैरिफ अगस्त में रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाए गए थे। दूसरी ओर एक अन्य खबर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-जनवरी के दौरान क्रमशः चीन, यूएई, रूस, अमेरिका और सऊदी अरब से सबसे अधिक आयात किया गया।

सोना-चांदी ने बढ़ा दिया भारत का व्यापार घाटा

अमेरिका से भारत का आयात 23.7 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया

नई दिल्ली, एजेंसी। जनवरी में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 34.6 अरब डॉलर हो गया है। यह तीन महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोने और चांदी के आयात में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे आयात बिल बढ़ गया। वहीं, अमेरिका को होने वाले निर्यात में बड़ी गिरावट के कारण कुल निर्यात लगभग स्थिर रहा। जनवरी में भारत का आयात 19.1 प्रतिशत बढ़कर 71.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह पिछले अप्रैल के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और किसी भी महीने के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। सोने का आयात 4.5 गुना बढ़कर 12 अरब डॉलर हो गया, जबकि चांदी का आयात 2.3 गुना बढ़कर 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जनवरी के दौरान र प्रतिशत और आभूषण और कपड़ा निर्यात में गिरावट आई। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर

में थोड़ी वृद्धि देखी गई। इन सबके बावजूद कुल निर्यात 0.8 प्रतिशत बढ़कर 36.6 अरब डॉलर रहा। सरकार को इस साल रिकॉर्ड निर्यात होने का भरोसा है। इस भरोसे का एक कारण अमेरिका की मांग में आई तेजी भी है। फरवरी की शुरुआत में अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिए जाने के बाद र प्रतिशत और आभूषण और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ी है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत का निर्यात, चाहे वह सामान का हो या सेवाओं का, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो महीनों में भी यह इसी गति से जारी रहेगा। राजेश अग्रवाल ने कहा, इस साल हम लगभग 860 अरब डॉलर के निर्यात के करीब पहुंच सकते हैं। साथ ही सेवाओं का निर्यात पहली बार 410 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है। जनवरी में अमेरिका को भारत का निर्यात 22 प्रतिशत घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया। इससे अमेरिका के साथ व्यापार घाटा घटकर 2.1 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल के 4.8 अरब डॉलर के मुकाबले आधे से भी कम है। अग्रवाल ने आगे कहा, वित्तीय वर्ष 2025-26 व्यापार के लिए काफी व्यस्त रहा है और कई सकारात्मक विकासों ने भारत को समग्र व्यापार वृद्धि बनाए रखने में मदद की है। अगले वित्तीय वर्ष में कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते लागू होने के साथ हम वित्त वर्ष 2026-27 में भी इस सकारात्मक गति को जारी रखने की उम्मीद करते हैं।

अब 14 करोड़ की कमाई से हर कोई दंग

कॉलेज में जब दूसरे लड़के ढूंढ रहे थे जॉब, तब शुरू किया एक्सपेरिमेंट

नई दिल्ली, एजेंसी। वरुण रहेजा इंदौर के रहने वाले हैं। वह रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग के संस्थापक हैं। उन्होंने 2018 में मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। कॉलेज के सालों में जब कई छात्र प्लेसमेंट पर फोकस कर रहे थे, वरुण ने कंपोस्टिंग और सोलर ड्राइंग (सौर सुखाने की प्रक्रिया) के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज वह फसल कटने के बाद (पोस्ट-हार्वेस्ट) होने वाले नुकसान से निपटने के लिए अपने सोलर ड्रायर बेचते हैं। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में उन्होंने 14 करोड़ रुपये की कमाई की है। वरुण ने शार्क टैंक इंडिया में भी हिस्सा लिया। जजों से 1.75 करोड़ रुपये की डील हासिल की। कंपनी ने भारत के 26 राज्यों में 8,000 से अधिक सोलर ड्रायर स्थापित किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह केन्या, मलावी, इंडोनेशिया और भूटान जैसे देशों में फैल चुकी है। आइए, यहां वरुण की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। इस

आइडिया से बनाया ड्रायर सोलर ड्राइंग यानी सूरज की रोशनी में सुखाने का कॉन्सेप्ट भारत में नया नहीं है। यह किसानों और घरों के लिए मुफ्त है। भारतीय घरों में पापड़ और अचार को धूप में सुखाना एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जारी है। इंदौर के वरुण रहेजा ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके सोलर ड्रायर बनाए हैं। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। ये किसानों को हर साल होने वाले पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, किसानों को पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान के कारण हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होता है।वरुण राहेजा ने 2018 में बीटेक पूरा किया। कॉलेज के सालों में जब कई छात्र प्लेसमेंट पर फोकस कर रहे थे, वरुण कंपोस्टिंग और सोलर ड्राइंग पर प्रयोग करने में जुटे थे। वरुण का सोलर ड्राइंग में पहला एक्सपेरिमेंट 2017-18 में कॉलेज में रहते हुए शुरू हुआ। उन्होंने अपनी सेविंग से लगभग 25,000-30,000 रुपये के निवेश से पहला सौर ड्रायर बनाया। 2018 में अपनी फर्म रजिस्टर की। बाद में 2019 में इसे रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में बदल दिया। उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पद्म श्री डॉ. जनक पालटा मैकगिलिगन के सानिध्य में इंटर्नशिप की। उनके मार्गदर्शन में वरुण ने सोलर ड्राइंग की प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल की। ये समझा कि कैसे स्थायी तकनीक सीधे किसानों की आय में सुधार कर सकती है। मॉडर्न रिटेल और क्विक कॉमर्स दिग्गज भी ऐसे उत्पाद की डिमांड करते हैं जो एक समान आकार और रंग वाले हों।

23 से ओपन हो रहा यह आईपीओ, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। मोबिलाइज ऐप लैब अपना आईपीओ 23 से 25 फरवरी 2026 के बीच लेकर आ रही है। कंपनी कुल 25,12,000 नए शेयरों का फ्रेश इश्यू जारी कर रही है, जबकि इसमें कोई ऑफर फॉर सेल शामिल नहीं है। प्री-इश्यू शेयर कैपिटल 70,00,000 शेयर है और प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 तय की गई है। इश्यू प्राइस और लॉट साइज की घोषणा जल्द की जाएगी। निवेशकों के लिए 50 प्रतिशत हिस्सा क्यूआईबी, 15 प्रतिशत एनआईआई (एचएनआई) और 35 प्रतिशत रिटेल श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 11 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मोबिलाइज ऐप लैब एक भारतीय आधारित आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंटरप्राइज ऑपरेशंस को आसान और व्यवस्थित बनाने पर काम करती है। कंपनी हेल्थकेयर, फूड एंड बेवरेज और फैसिलिटी मेंटेनेंस जैसे सेक्टरों के लिए कस्टमाइज्ड और मैनेजमेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। इसका प्रमुख उत्पाद एक उन्नत कंप्यूटरीकृत मेंटेनेंस

मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कंपनियों को अपने फिजिकल एसेट्स मैनेज करने, उपकरणों का रिकॉर्ड ट्रैक करने और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करने में मदद करता है। कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स में एडुप्रो ईआरपी शामिल है, जो शैक्षणिक संस्थानों के एडमिशन, अकादमिक गतिविधियों और परिवहन प्रबंधन को संभालता है। एससीएमप्रो ईआरपी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्रोत-से-अनुबंध (एस2सी) और खरीद-से-भुगतान प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है।

आज नीदरलैंड के खिलाफ अभिषेक से आक्रामक पारी का इंतजार रहेगा, स्पिनरों के सामने सुधार करना चाहेगा भारत

अहमदाबाद (एजेंसी)। अपनी पिछली दो पारियों में खाता खोलने में नाकाम रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नीदरलैंड के खिलाफ बुधवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप के मैच में बड़ी पारी खेलने के लिए प्रतिबद्ध होंगे जबकि भारतीय टीम के अन्य बल्लेबाज भी सुपर आठ चरण से पहले स्पिन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक शर्मा ने पिछले 18 महीने में खुद को इस प्रारूप का खतरनाक खिलाड़ी साबित किया है लेकिन घरेलू मैदान पर खेली जा रही आईसीसी प्रतियोगिता में वह अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं।

अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद वह पेट के संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में वापसी की लेकिन खाता खोलने में नाकाम रहे। लेकिन दूसरे छोर पर ईशान किशन की शानदार फॉर्म के कारण अभिषेक के बल्ले से रनों की कमी का टीम की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है। अभिषेक जोखिम लेने से नहीं कतराते हैं और उनकी इस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी से भारत को कई मैच में जीत भी मिली है। लेकिन इस 25 वर्षीय बल्लेबाज का पिछली छह पारियों में चार बार शून्य पर आउट होना यह संकेत देता है कि उन्हें पावरप्ले में अपनी रणनीति की समीक्षा करने की जरूरत है।

अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाज की छवि को देखते हुए यह स्पष्ट है कि विरोधी टीमों ने भारत के इस सलामी बल्लेबाज का सामना करने के लिए अतिरिक्त तैयारी की है। अभिषेक के स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उनके पास टीम के अन्य बल्लेबाजों की तरह शॉट की व्यापक रेंज नहीं है और वह क्रीज का उपयोग करने और अपने बल्ले की स्विंग पर भरोसा करते हैं ताकि विपक्षी टीम में खौफ पैदा कर सकें। उन्हें पावरप्ले में डीप कवर बाउंड्री पर शॉट मारना पसंद है और विरोधी टीमों ने उनके लिए उस क्षेत्र में एक फील्डर तैनात करके समझदारी दिखाई है।

सुनील गावस्कर की अभिषेक शर्मा को सीधी सलाह, पहले सेट हो फिर आक्रमकता दिखाओ

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही है। लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद उनके खेल और अप्रोच पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उन्हें बेहद सरल लेकिन अहम सलाह दी है। गावस्कर का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव से निपटने के लिए बुनियादी बातोंह्यह्य पर लौटना जरूरी है। उनका संदेश साफ है कि पहले खुद को सेट करो, फिर अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखाओ। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गावस्कर ने एक इंटरव्यू में अभिषेक को सलाह दी कि पारी की शुरुआत में जल्दबाज़ी से बचें। उन्होंने कहा कि आक्रामक शॉट खेलने से पहले सिर्फ एक तेज़ सिंगल लें, ताकि शरीर और दिमाग दोनों मैच की लय में आ सकें। गावस्कर के मुताबिक, पहले एक सिंगल लो, फिर खुलकर खेलो। जब तक आप रन बोर्ड पर नहीं लगाते, आत्मविश्वास पूरी तरह नहीं आता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अच्छे फॉर्म को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बल्लेबाज़ शानदार फॉर्म के बाद जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश में गलती कर बैठते हैं।

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फिर होगा भारत-पाक में महामुकाबला?

नईदिल्ली (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबो में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और सुपर-8 में जगह पक्की कर ली। यह टी20 विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 8वीं जीत रही। इस हार के बाद पाकिस्तान की सुपर-8 में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है।

टूर्नामेंट का पूरा फॉर्मेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों को 4 ग्रुप (ए-बी-सी-डी) में बांटा गया है। हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें सुपर-8 में पहुंचती हैं। सुपर-8 में 8 टीमों को दो ग्रुप (ग्रुप-1 और ग्रुप-2) में बांटा जाएगा। हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी।

सुपर-8 में भारत-पाक मुकाबला क्यों मुश्किल?

आईसीसी ने टूर्नामेंट से पहले ही प्री-सीडिंग सिस्टम लागू किया था। भारत को एक्स1 (ग्रुप-1), पाकिस्तान को बाय 3 (ग्रुप-2), यानी सुपर-8 में दोनों टीमें अलग-अलग ग्रुप में रहेंगी। इसलिए सुपर-8 चरण में भारत और पाकिस्तान का दोबारा आमना-सामना संभव नहीं है।

तो फिर कैसे हो सकती है दोबारा भिड़ंत?

सेमीफाइनल में- भारत-पाकिस्तान सेमीफाइनल में तभी भिड़ सकते हैं जब- एक टीम अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहे, दूसरी टीम दूसरे ग्रुप में दूसरे स्थान पर, अगर दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहती हैं या दोनों दूसरे स्थान पर रहती हैं, तो सेमीफाइनल में भी मुकाबला संभव नहीं होगा ।ह्य

एक ओवर में कूटे 20 रन, 22 गेंद में ठोकी फिफ्टी

इटली के बल्लेबाज बेन मानेंटी ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली तूफानी पारी

कोलकाता (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 29वें मुकाबले में भले ही इटली को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बेन मानेंटी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच लिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में मानेंटी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया।

203 रन का पीछा, शुरुआत रही बेहद खराब - 203 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने महज 23 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। ऐसा लग रहा था कि मैच एकतरफा हो जाएगा, लेकिन ओपनर जस्टिन मोस्का और बेन मानेंटी ने पारी को संभाला। मोस्का ने एक छोर थामे रखा, जबकि मानेंटी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।

- **22 गेंद में फिफ्टी, विल जैक्स के ओवर में 20 रन** - मानेंटी ने चौके-छक्कों की झड़ी लगाते हुए महज 22 गेंदों में फिफ्टी पूरी की। खास तौर पर विल जैक्स के एक ओवर में उन्होंने दो चौके और दो छक्के जड़ते हुए 20 रन बटोर लिए। 28 वर्षीय इस बल्लेबाज ने 25 गेंदों में 60 रन की पारी खेली, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे। मोस्का (43) के साथ उनकी 92 रन की साझेदारी ने इंग्लैंड की धड़कनें बढ़ा दीं।
- **ओवरटन और करन ने पलटा मैच** - हालांकि जेमी ओवरटन ने मानेंटी को आउट कर इंग्लैंड को राहत दिलाई। इसके बाद ग्रांट स्टीवर्ट ने 23 गेंदों में 45 रन की तेज पारी खेलकर इटली की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन सैम करन ने उनका विकेट लेकर मैच पर इंग्लैंड की पकड़ मजबूत कर दी।
- **मैच का नतीजा- 24 रन से जीता इंग्लैंड** - इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में इटली की टीम 178 रन पर ऑलआउट हो गई। इंग्लैंड ने 24 रन से जीत दर्ज कर सुपर-8 में जगह बना ली।

फ़ीडे फ्रीस्टाइल विश्व चैंपियनशिप फाइनल में कारुआना से होगी कार्लसन की टक्कर

वाइजनहाउस, जर्मनी (एजेंसी)। फ़ीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैम्पियनशिप 2026 के फाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नॉर्वे के मैगनस कार्लसन का सामना अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फैबियानो करुआना से होगा। दोनों खिलाड़ियों ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। कार्लसन के पास अब अपने करियर का 21वां विश्व खिताब जीतने का मौका है।

कार्लसन ने उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को 3-1 से पराजित किया। पहले दो मुकाबले ड्रॉ रहे, लेकिन तीसरे गेम में निर्णायक क्षण पर अब्दुसत्तोरोव की एक गलती का फायदा उठाते हुए कार्लसन ने बढ़त बना ली। चौथे गेम में भी नॉर्वेजियन स्टार ने दबाव बनाए रखा और मैच अपने नाम किया।

कार्लसन ने मुकाबले के बाद कहा कि यह बेहद कठिन मैच था और अब्दुसत्तोरोव हर बार उनके खिलाफ और मजबूत होकर खेलते हैं।

दूसरे सेमीफाइनल में कारुआना ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को 2-1-2-1-1-2 से मात दी। करुआना ने पहले गेम में काले मोहरों से शानदार जीत दर्ज कर बढ़त बनाई। तीसरे गेम में हार झेलने के बावजूद उन्होंने चौथे मुकाबले में दमदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया।

2027 के लिए क्वालीफिकेशन तय

फाइनल में पहुंचते ही कार्लसन और कारुआना ने 2027 फिडे फ्रीस्टाइल विश्व चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। तीसरा और अंतिम स्थान तीसरे स्थान के मुकाबले में अब्दुसत्तोरोव और कीमर के बीच तय होगा।

अन्य मुकाबलों के परिणाम

5वें से 8वें स्थान के मुकाबलों में यूएसए के हंस नीमन ने लेवोन अरोनियन को 2-1-2-1-2-2 से हराया, जबकि भारत के अर्जुन एरिगैसी ने विश्व कप विजेता उज़्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव को 3-1 से पराजित किया। अब नीमन और अर्जुन पांचवें स्थान के लिए भिड़ेंगे, जबकि अरोनियन और सिंदारोव सातवें स्थान के लिए खेलेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है राह, जिम्बाब्वे के पास सुनहरा मौका, सुपर-8 में पहुँचने के पूरे मौके

कोलंबो (एजेंसी)। क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया पर टी20 विश्व कप 2026 के पहले ही राउंड से बाहर होने का खतरा मंडरा गया है। आयरलैंड को हराने के बाद ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हार गई। हर ग्रुप में 5 टीमें हैं और इसमें से सिर्फ दो को ही सुपर-8 में जगह मिलेगी। ग्रुप बी से श्रीलंका तीन मैचों में तीन जीत के साथ सुपर-8 में जगह बना चुका है। वहीं ओमान की टीम रेस से बाहर हो चुकी है। अब सुपर-8 के एक स्थान के लिए जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच टक्कर है। 17 फरवरी को कोलंबो में बारिश हो रही थी इसीलिए अगर आयरलैंड के साथ मैच रद्द होता है तो एक पाइंट जिम्बाब्वे को मिल जाएगा और वह सुपर 8 में पहुँच जाएगी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप बी के बचे हुए मैच

जिम्बाब्वे -आयरलैंड- 17 फरवरी
श्रीलंका - जिम्बाब्वे- 19 फरवरी
ऑस्ट्रेलिया - ओमान- 20 फरवरी

ऑस्ट्रेलिया को किस्मत का सराहा चाहिए

ऑस्ट्रेलिया को सुपर-8 में जगह बनानी है तो किस्मत का सहारा चाहिए। उसका मैच ग्रुप में सबसे अंत में है। उसे उम्मीद करनी होगी कि जिम्बाब्वे को आयरलैंड के साथ ही श्रीलंका से हार मिल जाए। इस स्थिति में जिम्बाब्वे के 4 पॉइंट ही रह जाएंगे। इसके साथ ही हार से उसका नेट रन रेट भी खराब होगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम ओमान को रौंदकर सुपर-8 में जगह बना सकती है।

जिम्बाब्वे को सिर्फ एक जीत चाहिए

जिम्बाब्वे ने अभी तक खेले अपने दोनों मैच जीते हैं। उसे सुपर-4 में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक ही जीत की जरूरत है। 17 फरवरी को अगर आयरलैंड के खिलाफ उसे जीत मिलती है तो वह सुपर-8 में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम अभी तक सिर्फ एक ही बार टी20 विश्व कप इतिहास में दूसरे राउंड तक पहुंची है।

आयरलैंड की टीम भी अभी बाहर नहीं हुआ है। अगर उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत हासिल कर ली तो भी ऑस्ट्रेलिया को ओमान के खिताब जीत हासिल करनी पड़ेगी।

ऑस्ट्रेलिया पहले भी ग्रुप राउंड से बाहर हो चुकी

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2021 टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। 2009 का टूर्नामेंट एकमात्र टी20 विश्व कप था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप राउंड से बाहर हो गई थी। टीम श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप में थी। उसे दोनों मैचों में हार मिली और ग्रुप राउंड में ही सफर समाप्त हो जाएगा।

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी का कहर, चयनकर्ताओं को दिया मजबूत संदेश

बंगाल (एजेंसी)। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल की ओर से खेलते हुए शमी ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ आठ विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 35 वर्षीय अनुभवी पेसर ने कल्याणी में अपनी धारदार गेंदबाज़ी से विपक्षी बल्लेबाज़ों को टिकने का मौका नहीं दिया। उनके इस प्रदर्शन ने टीम इंडिया में संभावित वापसी की चर्चाओं को फिर से तेज़ कर दिया है।

सेमीफाइनल में घातक स्पेल

कल्याणी के बंगाल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में शमी ने पहली पारी में कहर बरपाया। उन्होंने 59वें ओवर में पांच विकेट पूरे किए और जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाज़ी को पूरी तरह झकझोर दिया। शमी की रफ्तार, लाइन-लेंथ और अनुभव ने बल्लेबाज़ों को लगातार दबाव में रखा। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ कन्हैया वधावन का विकेट उनके स्पेल का अहम मोड़ रहा, जिसके बाद बंगाल ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली।

इस सीजन में शानदार लय

यह प्रदर्शन कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। शमी इस रणजी सीजन में लगातार प्रभावी रहे हैं। अब तक सात मैचों में वह 38 विकेट झटक चुके हैं, जिसमें तीन बार पांच विकेट हॉल भी शामिल है। पिछले महीने सर्विसेज़ के खिलाफ उन्होंने दूसरी पारी में 5/51 का शानदार आंकड़ा दर्ज किया था। उनकी गेंदबाज़ी में पुरानी धार साफ दिख रही है, जो बताती है कि फिटनेस और फॉर्म दोनों उनके साथ हैं।

चयनकर्ताओं के लिए बड़ा संकेत

हालिया समय में भारत की तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण को लेकर चर्चा होती रही है। ऐसे में शमी का घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज़ में मौका नहीं मिला और 2026 टी20 विश्व कप की टीम में भी जगह नहीं मिली। चोट के कारण बदलाव में मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया। बावजूद इसके, शमी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने खेल से जवाब देने का रास्ता चुना।

सीमित ओवरों में भी प्रभाव

रेड-बॉल क्रिकेट के अलावा शमी ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया। सात मैचों में 15 विकेट लेने के साथ उनकी इकॉनमी 6.09 रही, जो सीमित ओवरों के प्रारूप में उनकी उपयोगिता दर्शाती है। हालांकि उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान था, लेकिन तब से वह घरेलू स्तर पर लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं।

बंगाल की मजबूत स्थिति

बल्लेबाजी में सुदीप कुमार घरामी ने 146 रन की शानदार पारी खेलकर बंगाल को पहली पारी में 328 रन तक पहुंचाया। इसके बाद शमी की अगुवाई में गेंदबाज़ों ने जम्मू-कश्मीर को दबाव में रखा, जिससे सेमीफाइनल में बंगाल की स्थिति मजबूत हो गई।

वर्ल्डकप में युवराज समरा की ऐतिहासिक उपलब्धि

चेन्नई (एजेंसी)। टी20 विश्व कप 2026 में कनाडा के युवा बल्लेबाज युवराज समरा ने ऐसी पारी खेली, जिसने एसोसिएट देशों के क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में खेली गई उनकी 110 रन की धमाकेदार पारी अब टी20 विश्व कप में किसी भी एसोसिएट टीम के बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन चुकी है। इस शतक ने न केवल समरा को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया, बल्कि यह भी साबित किया कि उभरती टीमें अब बड़े मंच पर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

110 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी

युवराज समरा ने 65 गेंदों पर 110 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उनकी पारी में 11 चौके और 6 छक्के शामिल रहे, जो उनकी आक्रामक मानसिकता और बेहतरीन टाइमिंग को दर्शाते हैं। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेला और न्यूजीलैंड जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। यह पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, बल्कि एसोसिएट क्रिकेट की बढ़ती ताकत का प्रतीक भी थी।

टी20 विश्व कप में इससे पहले एसोसिएट देशों के बल्लेबाजों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं, लेकिन समरा का 110 रन का आंकड़ा सबसे ऊपर पहुंच गया है। अमेरिका के एरॉन जोन्स ने 2024 में 94* रन बनाए थे, जो लंबे समय तक शीर्ष स्कोर रहा। स्कॉटलैंड के माइकल जोन्स (86) और जॉर्ज मुनसे (84) ने भी यादगार पारियां खेली थीं। वहीं अमेरिका के एंड्रीज़ गौस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 80* रन बनाकर अपनी छाप छोड़ी थी। इन सभी पारियों के बीच युवराज समरा का शतक अब नया बेंचमार्क बन चुका है।

बड़े मंच पर परिपक्व बल्लेबाजी

समरा की पारी की खास बात उनका संयम और मैच की परिस्थितियों को समझने की क्षमता रही। उन्होंने पावरप्ले में तेज शुरुआत की, फिर बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संभाला और अंत में आक्रामक अंदाज में रन गति बढ़ाई। 19 साल की उम्र में इतनी परिपक्व बल्लेबाजी दर्शाती है कि वे लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रभाव छोड़ सकते हैं।झकनाडा क्रिकेट लंबे समय से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। युवराज समरा की यह पारी टीम के लिए प्रेरणास्रोत साबित हो सकती है।

रचिन और फिलिप्स के अर्धशतक से न्यूजीलैंड ने भी मारी सुपर 8 में एंट्री

चेन्नई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली। 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम ने 15.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। टीम ने 29 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड को शुरुआत में कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन इसके बाद रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाल लिया।दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाते हुए कनाडाई गेंदबाजों को दबाव में रखा। रचिन रविंद्र ने 38 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उन्होंने अपना अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया। शिवम शर्मा की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर लगाया गया उनका छक्का मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विजयी चौका जस्करनदीप सिंह की गेंद पर पुल शॉट लगाकर आया, जिसके साथ ही कीवी कैंप में जश्न शुरू हो गया। ग्लेन फिलिप्स ने भी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और रविंद्र के साथ मैच को आसानी से खत्म किया।दोनों के बीच मजबूत साझेदारी ने कनाडा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

रावी नदी पर बांध बनकर तैयार, अब बूंद-बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान

कठुआ, एजेंसी। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से बहते पानी की सियासत अब एक बड़े बदलाव की ओर है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर निर्माणाधीन शाहपुर कंडी बांध परियोजना अपने अंतिम चरण में है। इस परियोजना के चालू होने से रावी नदी का वह बचा हुआ पानी, जो अब तक बहकर पाकिस्तान चला जाता था, पूरी तरह रुक जाएगा और इसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सूखी जमीन को सींचने में किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को जानकारी दी कि इस बांध का काम 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना विशेष रूप से सूखाग्रस्त कठुआ और सांबा जिलों के लिए जीवनरेखा साबित होगी।

यह बांध न केवल जल संचयन करेगा, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। इस परियोजना से जम्मू-कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में 32,173 हेक्टेयर से अधिक भूमि और पंजाब की लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। केंद्र सरकार ने सिंचाई घटक के लिए 485.38 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी है।

बांध के पूरा होने से क्षेत्र में बिजली उत्पादन और कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी।

सिंधु जल संधि और बदलती नीति: 1960 की सिंधु जल संधि के तहत तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का पूर्ण अधिकार है। इसके बावजूद, तकनीकी बाधाओं और बांध न होने के कारण रावी का काफी पानी पाकिस्तान जा रहा था। पूर्व सिंचाई मंत्री ताज मोहिद्दीन के अनुसार, यह बांध सिंधु जल संधि के दायरे से बाहर है क्योंकि 1960 की संधि के तहत रावी, सतलुज और ब्यास जैसी 'पूर्वी नदियों' पर भारत का विशेष अधिकार है। हालांकि, अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया है।

अब भारत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के पानी के अधिक उपयोग की संभावनाएं भी तलाश रहा है। जम्मू-कश्मीर के विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने कहा कि एक बार काम पूरा होने के बाद, पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि हमारे अपने कठुआ क्षेत्र की विशाल भूमि को हरा-भरा करेगा। भारत द्वारा अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल करने से पाकिस्तान के निचले इलाकों में पानी की भारी कमी होने की आशंका है। यह कदम स्पष्ट करता है कि भारत अब अपने प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को लेकर गंभीर है।

दशकों का इंतजार और राजनीतिक इच्छाशक्ति

2001: परियोजना को पहली बार मंजूरी मिली, लेकिन अंतर्राज्यीय विवादों के कारण काम रुक गया।

2018: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच समझौता हुआ।

वर्तमान: अब यह परियोजना मिशन मोड में है ताकि पाकिस्तान की ओर होने वाले पानी के 'अपव्यय' को रोका जा सके। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम न केवल कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव का भी एक हिस्सा है। पाकिस्तान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है।

वाराणसी में बड़ा हादसा टला, टक्कर के बाद गंगा में समाई नाव, पर्यटकों को बचाया गया

वाराणसी, एजेंसी। धर्मनगरी वाराणसी के घाटों पर सोमवार को उस समय चीख-पुकार मच गई, जब एक भीषण नाव हादसा होते-होते बचा। गंगा की लहरों के बीच एक छोटी नाव और तेज रफ्तार मोटरबोट के बीच हुई जोरदार भिड़ंत ने वहां मौजूद लोगों की सांसें थाम दीं। टक्कर इतनी भयानक थी कि नाव देखते ही देखते गंगा में समा गई और उस पर सवार पर्यटक गहरे पानी में डूबने लगे। यह घटना वाराणसी के प्रसिद्ध तुलसीघाट पर दोपहर करीब 2 बजे घटी। गनीमत यह रही कि समय रहते स्थानीय नाविकों और बचाव दल ने मुस्तैदी दिखाई, वरना एक बड़ा हादसा वाराणसी की धार्मिक यात्रा को मातम में बदल सकता था।

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद और पुणे से आए पांच पर्यटकों का एक समूह गंगा पार रामनगर जाने के लिए तुलसीघाट से एक छोटी नाव पर सवार हुआ था। हैदराबाद निवासी दिलीप, दर्शना, देवयानी और पुणे के रोहित व दीपाली श्रद्धा और उत्साह के साथ नाव में बैठे ही थे कि घाट से कुछ ही दूर निकलते ही एक तेज रफ्तार बड़ी मोटरबोट ने उनकी नाव को जोरदार टक्कर

मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर लगते ही नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाव में सवार पर्यटक पानी में गिरकर जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। उनकी चीखें सुनकर घाट पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही घाट पर मौजूद साहसी स्थानीय नाविकों ने तुरंत गंगा में छलांग लगा दी। इसी बीच एनडीआरएफ और जल पुलिस को भी सूचना दी गई। राहत और बचाव कार्य इतनी तेजी से शुरू हुआ कि डूब रहे पांचों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, जिस नाव पर वे सवार थे, वह टक्कर के बाद पूरी तरह से गंगा में समा गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हादसे का जिम्मेदार नाविक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पर्यटकों को बचाने की जद्दोजहद देखी जा सकती है। इस हादसे ने एक बार फिर वाराणसी में नाव संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया कि नाव पर सवार एक भी पर्यटक ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाव पर लाइफ जैकेट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। प्रशासन की ओर से बार-बार चेतावनी और सख्ती के बावजूद कई नाविक नियमों की धज्जियां उड़ाकर पर्यटकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।

बिना सुरक्षा उपकरणों के गंगा की लहरों पर पर्यटकों को ले जाना एक बड़ी लापरवाही है, जिस पर अब प्रशासन कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है।

विधायकों की बैठक की तैयारी में थे डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया ने पलटा गेम, ले जा रहे विदेश

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के सत्ता संघर्ष में कांग्रेस की आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है। 2023 में कांग्रेस को कर्नाटक में सरकार बनाने का मौका मिला था और उसके बाद से ही डीके शिवकुमार खेमा यह कहता रहा है कि ढाई साल के बाद उनके नेता मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया खेमा इस बात से इनकार करता रहा है और रस्साकशी जारी है। इस बीच खबर है कि डीके शिवकुमार कांग्रेस विधायकों की मीटिंग बुलाने वाले थे ताकि शक्ति प्रदर्शन कर सकें। उनके समर्थकों का कहना था कि 136 विधायक डीके शिवकुमार के साथ हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अलग ही दांव चल दिया है, जिसकी खूब चर्चा है। अपने करीबी 27 विधायकों को सिद्धारमैया विदेश दौरे पर ले जा रहे हैं। इन विधायकों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर वह साथ ले जाएंगे। उनके गुट का कहना है कि यह रूटीन विजिट है, जो अकसर तमाम योजनाओं की जानकारियां हासिल करने के लिए होती हैं। लेकिन कयास तेज हैं कि आखिर इसी समय ऐसी विजिट का फैसला क्यों है। इसका जवाब भी कांग्रेस के ही लोग दे रहे हैं और उनका कहना है कि डीके शिवकुमार की बैठक में कम विधायक पहुंचें, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टी के सिद्धारमैया खेमे को लगता है कि डीके शिवकुमार को तब तक रोक लिया जाए और फिर बजट सत्र आ जाएगा। इस बीच कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा ने दावा किया है कि शिवकुमार के साथ सभी 136 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि डीके को कोई भी मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि वह सीएम बनेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। रविकुमार ने कहा कि इस स्थिति में किसी तरह का बदलाव होने की संभावना नहीं है, हमारे नेता मजबूत हैं और सीएम बनने के काबिल हैं। रविकुमार ने डीके शिवकुमार की वफादारी याद दिलाई और कहा कि वह 40 सालों से राजनीति में हैं। उनके पास समर्थन है तो रणनीति के भी वह मास्टर हैं। शिवकुमार के करीबी विधायक ने कहा, 'राजनीति एक गेम है और उसमें जल्दी ही नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा के साथ जाने वाले कयास लगा रहे हैं। ऐसी चीजें गलत हैं और छवि खराब करने के लिए ऐसा हो रहा है। शिवकुमार के करीबी विधायक ने कहा कि आखिर हमें भाजपा में जाने की जरूरत क्या है। यही रहेंगे और डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी से ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे।'

कश्मीर में फिर से खुले 14 पर्यटन स्थल, पहलगाम हमले के बाद हो गए थे बंद

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के उन 14 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद कर दिया गया था। उपराज्यपाल प्रशासन ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। उपराज्यपाल कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'सुरक्षा की गहन समीक्षा और विचार-विमर्श के बाद, मैंने कश्मीर और जम्मू संभागों में एहतियाती तौर पर अस्थायी रूप से बंद किये गए और भी पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है।' इसके साथ ही, अस्थायी रूप से बंद किए जाने के बाद फिर से खोले गए पर्यटन स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इससे पहले, पिछले साल 26 सितंबर को उपराज्यपाल ने 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया था। सिन्हा ने कहा, 'कश्मीर संभाग के 11 पर्यटन स्थलों- कोकरनाग में यूसमर्ग, दूधपथरी, दांडीपुरा पार्क, शोपियां में पीर की गली, दुबजान और पदपावन, श्रीनगर में अस्तनपोरा, ट्यूलिप गार्डन, थजवास ग्लेशियर, गांदेरबल में हंग पार्क और बारामुला में वुलर और वाटलाब – को तत्काल फिर से खोला जाएगा।' उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग के तीन पर्यटन स्थल – रियासी में देवी पिंडी, रामबन में महू मंगत और किश्तवार में मुगल मैदान – भी तत्काल प्रभाव से फिर से खोले जाएंगे। सिन्हा ने कहा, 'कश्मीर संभाग में तीन स्थल- गुरेज, अथवाटू और बंगस- और जम्मू संभाग में एक स्थल – रामबन में रामकुंड – बर्फ हटने के बाद फिर से खोल दिए जाएंगे।' 23 फरवरी से शुरू हो रहे 'खेलो इंडी शीतकालीन खेल' जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 23 फरवरी से शुरू होने वाले 'खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों' (केआईडब्ल्यूजी) में 700 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्की सहायक मोहम्मद रफीक चेची ने कहा, 'इस सर्दी में अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे 'स्कीइंग' और 'स्लेजिंग' गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का यहां आयोजन हो रहा है और इससे हमें अपनी आजीविका कमाने में मदद मिलेगी।' इस वर्ष 'बर्फ स्पर्धाओं' के लिए केआईडब्ल्यूजी का पहला चरण लद्दाख के लेह में 20 से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया था, जबकि 'हिम स्पर्धाओं' के लिए खेलों का दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। युवा सेवाओं और खेल विभाग द्वारा जारी एक वीडियो में चेची ने कहा, 'गुलमर्ग तैयार है, आपका इंतजार है।'

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिसंबर तक शुरू होगा 6जी सेंसर नेटवर्क का ट्रायल

मुंबई, एजेंसी। दिल्ली-मुंबईएक्सप्रेसवे पर कारें आपस में बात करेंगी। इसके तहत सड़क पर लगे सेंसरों के जरिये वाहन एक-दूसरे को सूचना भेजने में सक्षम होंगे। भारत में स्मार्ट कारों और लीविंग इंटेलिजेंट नेशनल हाईवे की मदद से सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जाएगा। दिसंबर 2026 में दुनिया के सबसे लंबे 6जी सेंसर नेटवर्क ट्रायल की शुरुआत होने जा रही है। योजना के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे और बगल में लाखों सेंसर बिछाए जाएंगे, जो फर्राटा भरती कारों को रेड लाइट, साइनबोर्ड, राहगीर, वाहन आदि की पहचान करने में सक्षम बनाएंगे। इस तकनीक को वी2एक्स (व्हीकल टू एवरीथिंग) संचार माध्यम कहा जाता है। सूत्रों ने बताया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं दूरसंचार मंत्रालय के बीच इसको लेकर सहमति बनी है। इसके तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के तीसरे चरण पर 6जी सेंसर नेटवर्क का दुनिया का पहला सबसे बड़ा हाईवे ट्रायल किया जाएगा। इसके तहत अवरोध या दुर्घटना होती है तो 6जी नेटवर्क के जरिए पीछे आ रही गाड़ियों के ब्रेक अपने-आप लग जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि 6जी ट्रायल का पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2026 तक वडोदरा-मुंबई खंड पर शुरू हो जाएगा। व्हीकल टू एवरीथिंग (वी2एक्स) तकनीक के जरिए वाहन एक-दूसरे को वास्तविक समय में जानकारी साझा करते हैं। विंडशील्ड पर एक डिजिटल डिस्प्ले होता है, जो आसपास की अन्य गाड़ियों, ट्रैफिक लाइट और सड़क सेंसर से मिल रहे डेटा को दिखाता है। हरी, नीली और सफेद लाइनें लगातार जानकारी का आदान-प्रदान करती हैं। सड़क तकनीक में चीन, कोरिया, जापान आगे सड़क परिवहन की भविष्यगामी तकनीक में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान सबसे आगे हैं। चीन 5जी पर वी2एक्स में सबसे आगे है, वह 2026 तक कई शहरों को 6जी ट्रायल के लिए तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया सेफरूट 6जी तकनीक अपना रहा है। सेटेलाइट और जमीनी 6जी नेटवर्क से वाहन सुदूर पहाड़ी इलाके या सुरंग में भी नेटवर्क बनाए रखेगा। वहीं, जापान माइक्रोसेकंड लेटेंसी तकनीक का मुख्य जोर सटीकता पर है।

पहुंचे एक लाख से अधिक श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा

बेंगलुरु, एजेंसी। पूरे नॉर्थ कर्नाटक इलाके में महाशिवरात्रि मनाई गई। अलग-अलग शहरों

और गांवों के अलग-अलग मंदिरों में खास पूजा हुई। रविवार को हुबली में सद्गुरु श्री सिद्धारूधा स्वामी के शिवरात्रि यात्रा महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बड़ी संख्या में मठ पहुंचकर सद्गुरु सिद्धारूधा और गुरुनाथारूधा का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि पूजा कार्यक्रम ईश्वर रामलिंगेश्वर और अन्य मंदिरों सहित विभिन्न मंदिरों में आयोजित किए गए थे। उंकल क्रॉस में श्री रामलिंगेश्वर मंदिर में बड़े पैमाने पर महाशिवरात्रि जागरण का आयोजन किया गया था। हजारों भक्तों ने मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया। एक लाख से अधिक श्रद्धालु हुए शामिल केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एक लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। लकड़ी के बने भव्य रथ पर अज्जा स्वामी को बैठाकर पालकी के रूप में जुलूस निकाला जाता है। श्रद्धालु पवित्र रथ को खींचकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्त उनाकल के ऐतिहासिक चंद्रमौलेश्वर मंदिर पहुंचे और मूर्ति के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइनों में खड़े हो गए। हुबली में रेलवे स्टेशन रोड पर ईश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया और भगवान की पूजा की। इस वर्ष रथ के ऊपर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। सदियों पुरानी जात्रा महोत्सव में देशभर से आए भक्त शामिल होते हैं। यह मठ अद्वैत दर्शन को समर्पित है।

बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे मोहम्मद यूनुस के करीबी?

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बांग्लादेश के आम चुनाव में उनकी पार्टी बीएनपी को बड़ा बहुमत मिला है। इस बीच खबरें हैं कि अब तक अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के कई करीबी देश छोड़कर निकल रहे हैं या ऐसा करने की फिराक में हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शेख हसीना की सरकार को भ्रष्टाचार के नाम पर चले आंदोलन के चलते अपदस्थ होना पड़ा था। फिर ईमानदार सरकार के नाम पर मोहम्मद यूनुस कमान संभाल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उनकी ईमानदार सरकार के सलाहकार देश छोड़कर क्यों निकल रहे हैं।

ढाका से निकलने वाले देश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने एक खबर में मोहम्मद यूनुस के करीबी सलाहकार फैज अहमद तैयब का नाम लेते हुए लिखा था कि उन्होंने जर्मनी के लिए फ्लाइट बुकिंग कराई है। अखबार की हेडिंग की भी काफी चर्चा हुई, जिसने इसे सरप्राइज डिपार्चर लिखा। तैयब अब तक मोहम्मद यूनुस के सलाहकार थे और वह उन्हें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल और टेलिकॉम्युनिकेशंस के मामले में मदद कर रहे थे। हालांकि इसे लेकर बांग्लादेश के जानकार आश्चर्य नहीं जता रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो महीनों पहले से कह रहे थे कि मोहम्मद यूनुस के करीबी देश से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं।

यही नहीं सोमवार की शाम को एनसीपी के सीनियर नेता नसीरुद्दीन पटवारी ने भी मोहम्मद यूनुस के सलाहकारों के देश से निकलने का रास्ता खोजने की बात कही और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। पटवारी ने कहा, 'हमने सुना है कि बहुत से सलाहकार सेफ एग्जिट की तलाश में हैं। हम देश के लोगों और खुद सलाहकारों से अपील करते हैं कि सेफ एग्जिट से पहले कम से कम एक बार अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी दें। आप जनता को बताएं कि अपने कार्यकाल में आपने देश के लिए क्या किया है। इसके अलावा डॉ. यूनूस को यह देश याद रखेगा कि उन्होंने इलेक्शन में किस तरह से मदद की।'

अक्टूबर 2025 से ही क्यों लगने लगे थे ऐसे कयास: अब बात करते हैं कि आखिर कथित ईमानदार सरकार के सलाहकारों को डर किस बात का है? इसकी जड़ें अक्तूबर 2025 में मिलती हैं। एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा था कि कई सलाहकारों ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ खुद को जोड़ लिया है और उनसे निकलने का रास्ता मांग रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम यहां राजनीति में फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहां से निकलना ही सही होगा। एनसीपी के ही एक अन्य नेता सरजिस इस्लाम ने तो यहां तक कहा था कि सलाहकारों की आजादी का एक ही रास्ता है और वह है- मौत। इससे समझा जा सकता है कि कुछ महीनों में ही कैसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अलोकप्रिय हो गए।

2030 तक दोगुनी हो जाएगी चीन की परमाणु ताकत?

बीजिंग, एजेंसी। चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है। हाल की रिपोर्टों और सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों के भंडार में लगातार इजाफा कर रहा है। बताया जा रहा है कि 2026 तक चीन के पास करीब 600 परमाणु वॉरहेड हो सकते हैं। इस मामले में वह रूस और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार रखने वाला देश बन चुका है।

तुलना करें तो रूस के पास लगभग 5,400 और अमेरिका के पास 5,100 से 5,200 के बीच वॉरहेड बताए जाते हैं। हालांकि चीन अभी इन दोनों देशों से काफी पीछे है, लेकिन उसकी बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक वह 1,000 से ज्यादा वॉरहेड का लक्ष्य हासिल कर सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर एनवायटी (न्यूयॉर्क टाइम्स) की रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट इमेज के जरिए चीन की गुप्त तैयारियों का पता चला है। इन तस्वीरों में सिचुआन प्रांत की घाटियों में स्थित दो खास जगहों जिटोंग और पिंगटोंग का जिक्र किया गया है। ये इलाके भारत के

अरुणाचल प्रदेश से लगभग 800 किलोमीटर दूर बताए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि यहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और मजदूर पहाड़ों के अंदर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट में इसे एक तरह का इनलैंड न्यूक्लियर एम्पायर यानी अंदरूनी परमाणु साम्राज्य बताया गया है। जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ रेनी बाबियार्ज ने इन सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है।

ट्रंप ने नाइजीरिया में भेज दिए 100 अमेरिकी सैनिक, यहां रोज होता है खून-खराबा; अब तेज होगी जंग

वाशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने नाइजीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया है। हाल ही में लगभग 100 अमेरिकी सैनिक और संबंधित उपकरण नाइजीरिया पहुंचे हैं। यह पहली खेप है, जिसमें कुल 200 सैनिकों की तैनाती का प्लान है। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल समाइला उबा ने पुष्टि करते हुए कहा है कि ये सैनिक ट्रेनिंग, तकनीकी सहायता और खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए आए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी सैनिक सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे और पूरी कमान नाइजीरियाई सेना के पास ही रहेगी।

बताया जा रहा है कि यह तैनाती नाइजीरिया सरकार की औपचारिक मांग पर हुई है, जो देश में बढ़ते आतंकवादी हमलों से जूझ रही है। नाइजीरिया में बोको हराम, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रॉविंस (आई एस डब्ल्यू एपी), लकुरावा जैसे इस्लामिक आतंकी समूह और अन्य सशस्त्र गिरोहों (बैंडिट्स) का आतंक लगातार बढ़ रहा है। उत्तर-पूर्वी इलाकों जैसे बोर्नो, योबे और अडामा में रोजाना हमले, अपहरण और हत्याएं हो रही हैं। हाल के महीनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों विस्थापित हुए हैं।

अमेरिकी सैनिकों की यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब देश में हिंसक हमले चरम पर हैं। पिछले सप्ताह के अंत में मोटरसाइकिलों पर आए बंदूकधारियों ने तीन गांवों में तांडव मचाया, जिसमें कम से कम 46 लोग मारे गए। सबसे

भीषण हमला नाइजर राज्य के कोंकोसो गांव में हुआ, जहां 38 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नाइजीरिया वर्तमान में बोको हरम, आई एस डब्ल्यू एपी, और 'लाकुरावा' जैसे कई आतंकी गुटों से जूझ रहा है। इसके अलावा, 'डाकू' समूह भी सक्रिय हैं जो फिरौती के लिए अपहरण और अवैध खनन में शामिल हैं। ट्रंप ने 2025 के अंत में नाइजीरिया पर खासा दबाव बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है और सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रही। दिसंबर 2025 में क्रिसमस के दिन अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। ट्रंप ने इसे आईएसआईएस के आतंकवादियों पर सीधा प्रहार बताया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधरी। नाइजीरिया ने अमेरिका से ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट मांगा, जिसके जवाब में यह तैनाती हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की नीति में धार्मिक उत्पीड़न (खासकर ईसाइयों की सुरक्षा) को प्राथमिकता मिल रही है, जो उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। नाइजीरिया की 24 करोड़ की आबादी ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच लगभग समान रूप से बंटी हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि हिंसा का शिकार केवल ईसाई नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोग हो रहे हैं। वास्तव में, अधिकांश हमले मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र में होते हैं, जिससे हताहत होने वालों में मुस्लिम नागरिकों की संख्या अधिक है। क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग हाल के महीनों में यह संकट और गहरा गया है क्योंकि पड़ोसी साहेल क्षेत्र के आतंकी समूह भी नाइजीरिया में घुसपैठ कर रहे हैं। 'जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन' जैसे समूहों ने पिछले साल पहली बार नाइजीरियाई धरती पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। दिसंबर में अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिम में ढ्रस्ढ्रुरु से जुड़े लड़ाकों पर हवाई हमले किए थे। अब 100 सैन्य कर्मियों की यह नई तैनाती दर्शाती है कि वाशिंगटन और अबुजा के बीच सैन्य सहयोग फिर से मजबूत हो रहा है। यह तैनाती जंग को तेज करने का संकेत दे सकती है, लेकिन सीमित रूप से। अमेरिकी सैनिक सीधे फायरिंग में नहीं उतरेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक देवन प्रसाद द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं - बी-126, मायापुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110064 से प्रकाशित। सह संपादकः संपादक देवन प्रसाद मो. 9212228045, 8130691216, (नोटः प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं और किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा दिल्ली उच्च न्यायालय में ही किया जाएगा।) RNI. No. DELHIN/2010/32488, Email: news@pratahkiran.com, 9971557129 रंजीत राय फोन नं-011-45795464,